राजस्थान विधान सभा

पंचम बैठक, दिनांक १६ फरवरी १९५३

(सदन का कार्य २ बजकर ६ मिनट पर प्रारम्भ हुआ)

(अध्यक्ष, श्री नरोत्तम लाल जोशी पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—Questions.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्यमंत्री)—Sir, I would request that the first three questions may be postponed to a later stage since the Deputy Chief Minister has not come. He might be meeting the new Chief Secretary. They may be taken later.

एक सदस्य--Will you please speak loudly ?

श्री जयनारायण व्यास--The Deputy Chief Minister has not turned up as yet and I would request the chair to take up the first three questions later on and the other questions may be taken up now.

श्री जसवन्तसिंह--What has happened to the Deputy Chief Minister ?

श्री जयनारायण व्यास—I cannot say exactly what has happened to him, but he has not come here as yet. He was in the office quite up-to-now.

श्री जसवन्तसिंह--My friend, the Hon'ble Chief Minister, is a parliamentarian. Does he not think it proper that any Minister, whether he is the Chief Minister or Deputy Chief Minister should be present at the time the questions are to be answered.

श्री जयनारायण व्यास--It seems this clock runs a bit faster.

श्री जसवन्तसिंह—Well, it is not so.

श्री हिम्मतसिंह (कुनाडी)—Rather two minutes slow.

श्री जसवन्तसिंह--What is the ruling of the Chair ?

श्री अध्यक्ष—May I not reserve my ruling ?

Page No.2

श्री जसवन्तसिंह—But we do hope that the Ministers would be present in time in the future, because it does not reflect well on the Treasury Benches, because if the Ministers set the example in the manner in which the Deputy Chief Minister has done, then other members will also do so.

श्री हिम्मतसिंह—He has come, Sir.

श्री अध्यक्ष—Well, it is desirable that the Hon'ble Members of the Treasury Benches should be in attendance when questions are called.

(Pause). So we can start from the other end.

श्री हिम्मतसिंह—No Sir. He has come.

(श्री उप-मुख्य मंत्री का सदन में प्रवेश)

प्रश्न संख्या ८४

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु (डिवीजन नं० ४६)—क्या गृह मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे :—

साल १९५२ में जिला गंगानगर में कितने कत्ल, डकैती, चोरी व जरबे शदीद पहुंचाने के केस हुए, उनमें से कितने बरामद हुए, कितने चालान हुए और कितने चालान कामयाब हुए हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—नक्शा मुकदमात जिला गंगानगर का इस प्रकार है.......

रिपोर्ट शुदा

डकैती	१३
कत्ल	६२
चोरी	१२३
ज़र्ब शदीद	५४

माना गया

डकैती	१०
कत्ल	५६ मफरूर १ मर गया
चोरी	१२२
ज़र्ब शदीद	५०

अदमपता

डकैती	३
कत्ल	६

	चोरी	३९
	जर्ब शदीद	७
जेरतफतीश		
	डकैती	५
	कत्ल	१२
	चोरी	२८
	जर्ब शदीद	६
चालानशुदा		
	डकैती	३
	कत्ल	४१
	चोरी	५५
	जर्ब शदीद	३७
जेर तजबीज अदालत		
	डकैती	३
	कत्ल	३६
	चोरी	१५
	जर्ब शदीद	२०
सजा		
	डकैती	..
	कत्ल	२
	चोरी	२५
	जर्ब शदीद	१
रिहा		
	डकैती	..
	कत्ल	३
	चोरी	१५
	जर्ब शदीद	१६

एक सदस्य—क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ४२० आई.पी.सी. के मुकद्दमे गंगानगर में कितने हुए ?

श्री टीकाराम पालीवाल (गृहमंत्री)—अलग अलग दफाओं के मुकद्दमे छांटे नहीं हैं। अगर इस तरह से चाहा जावेगा तो छांट कर बताया जा सकता है।

प्रश्न संख्या ८५

श्री हरिकृष्ण व्यास–Will the Minister-in-charge for Home Affairs be pleased to state.—

(*a*) Is it a fact that the workers of the Maharaja Kishangarh Mills were kept in police lock-up for some hours and were then taken in Police lorries and left one fifty miles away from Jaipur?

(*b*) Under what law were they thus forcibly removed?

(*c*) Is it a fact that they were lathi charged in the village?

(*d*) Is the Government aware that the village Panchayat has testified to the fact of such lathi charge?

(*e*) Is the Government prepared to order a judicial enquiry in the whole matter?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)–(*a*) Since the question is vague a definite reply is not possible. Some persons purporting to be ex-workers of the closed Maharaja Kishangarh Mills were found travelling without tickets and they were tried by the Railway Magistration and convicted. Later, as the Police came to know of a design to commit cognizable offence of these persons they were removed in police transport out of the zone of mischief.

(*b*) 151 Cr. P. C. to prevent the commission of a cognizable offence.

(*c*) No.

(*d*) No.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार इसे वाजिब चीज समझती है कि लोगों को बगैर खाने के एवं रहने के प्रबन्ध के स्थान में, जंगल में ले जाकर छोड दिया जाय?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने अभी निवेदन किया कि ऑफेंस कमिट करने के अन्देशे की वजह से वहां से हटाये गये और ऑफेंस कमिट करने के स्थान से दूर हटा दिये गये।

श्री हरिकृष्ण व्यास–Is it fair on the part of the Government to remove people from a place and leave them in the jungles without shelter and food?

श्री टीकाराम पालीवाल—I could not hear well.

श्री अध्यक्ष—Order? There cannot be any question like that. You can seek information. Questions are meant for information and not for expression of opinion.

श्री हरिकृष्ण व्यास—किस कानून के मातहत वे बाहर ले जाकर छोडे गये ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इसका उत्तर में पहले ही दे चूका हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि उन पर लाठी चार्ज हुआ हे या नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं हुआ ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किस अधिकारी द्वारा जांच करवाई गई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इस प्रकार शिकायत ही नहीं प्राप्त हुई तो जांच क्या करवाई जावे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या वहां की ग्राम पंचायत ने सरकार को लिखित पत्र इस बारे में नहीं भेजा है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सरकार को ऐसा कुछ नहीं मिला है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इसकी फिर से जांच करेगी कि ऐसा कोई पत्र आया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अगर ऐसा कोई पत्र आया होगा तो उसे देख लिया जावेगा; पर सरकार जांच की कोई आवश्यकता नहीं समझती ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इस प्रकार का आश्वासन देने को तैयार है कि आगे से इस तरह लोगों को जंगल में नहीं छोडा जावेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऑफेंस कमिट करने का जरा सा भी अन्देशा सरकार समझेगी वहां से लोगों को सरकार जरूर मूव करेगी या जैसा उचित समझेगी वैसा अवश्य करेगी । सरकार ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकती ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो इससे क्या यह समझा जाय कि सरकार आवश्यकता पड़ने पर लोगों की जान को खतरे में भी डालना चाहती है ।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर, ऑर्डर ! नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ८६

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या गृहमन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे —

क्या यह सच है कि चक ३९ आर. बी. के गुरुद्वारा बनाने के लिए पुलिस पदमपुर, जिला गंगानगर, ने मन्जूरी देने से इन्कार किया है ?

(ख) यदि हां तो क्यों ?

श्री टीकाराम पालीवाल—साधारणतया इस प्रकार के मामलों में पुलिस की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन यदि कहीं शान्ति-व्यवस्था का प्रश्न इस प्रकार के मामले से जुड़ा हो तो मजिस्ट्रेट अपने कानूनी अधिकार का उपयोग करता है और जो आज्ञा पुलिस को मजिस्ट्रेट से मिलती है उसे पुलिस को पालन करना होता है। पदमपुर के थानेदार के हस्तक्षेप करने का कोई समाचार सरकार का इस सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार का ध्यान इस बात की तरफ है कि हर गुरुद्वारा के लिए मन्जूरी लेनी पडती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—किससे मन्जूरी लेने की बात आप कह रहे हैं ?

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—यह मैंने पुलिस के लिए कही है। पुलिस से ऐसी मन्जूरी लेनी आवश्यक है ? हर गुरुद्वारे के लिए मन्जूरी लेनी पडती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने कहा कि पुलिस से कोई मन्जूरी लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—बिना पुलिस से मन्जूरी लिये महकमा माल कभी मन्जूरी नहीं देता।

श्री टीकाराम पालीवाल—इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। यह आपको महकमा माल से पूछना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ८७

श्री एच० के० व्यास—Will the Minister-in-charge for Finance be pleased to answer :—

(*a*) What was the total amount of securities to the credit of the Rajasthan Government at the time of its formation in 1949 ?

(b) What have been the total revenue receipts of the Government since its formation in 1949 to upto date ?

(c) What has been the total expenditure incurred by the Government during the same period ?

श्री जयनारायण व्यास—(*a*) Government Securities &c. taken over on formation of Rajasthan:—

(*i*) General Reserves including earmarked funds.—

G. P. Notes	Rs.	14,89,71,900-0-0
Fixed Deposits		52,15,754-14-3
Postal &c. Certificates		37,89,082- 8-0
Total (*i*)	Rs.	15,79,76,737-6-3

(*ii*) Trust Funds

G. P. Notes	Rs.	99,36,100-0-0
Fixed Deposits		24 55,027-4-6
Postal Certificates		39,110 0-0
Total (*ii*)	Rs.	1,24,30,237-4-6

Grand Total (*i*) and (*ii*) Rs. 17,04,06,970-10-9

Sterling Securities £ 1,69,762-0-4 or Rs. 22,16,375 (Approx.)

(*b*) Total revenue

Year		*Total Revenue Receipts*
1949-50 (1st Oct. 1949 to 31st March, 1950)		6,52,33,000
1950-51		14,60,53,000
1951-52		15,51,48,000
	Total	36,64,34,000
1952-53	(Budget Estimates)	16,32,18,000
		52,96,52,000

(*c*) Total Expenditure (including Capital)

Year.	Service Head.	Capital	Total
1949-50 (1st Oct., 1949 to 31st March, 1950)	7,94,42,000	48,28,000	8,42,70,000
1950-51	13,91,29,000	2,00,73 000	15 92,02,000
1951-52	15,76,16,000	6,07,23,000	21,83,39,000
			46,18,11,000
(B.E.) 1952-53	17,25,66,000	22 64,000	17,48,30,000
		Total	63,66,41,000

श्री हरिकृष्ण व्यास—What steps the Government is contemplating to take to bridge the gulf between revenue and expenditure ?

श्री जयनारायण व्यास—The question relates to securities. It does not relate the gap between revenue and expenditure.

Page No.8

श्री हरिकृष्ण व्यास–Sir, My part (*b*) relates to revenues since the formation of Rajasthan up-to-date and part (*c*) relates to expenditure incurred by Government during the same period. Both those parts have been replied. So the question as a whole relates to income and expenditure also.

श्री जयनारायण व्यास–The Government is always attempting to fill up that gap. But that gap is due to so many reasons and there are factors which are outside the purview of the Government as well as the outside the strength or the power to fill up that gap. So the Government has, on the one hand, approached the Government of India, as the Hon'ble Member has seen, and the Government of India has tried to fill up the gap to a large extent by giving us what we may call financial assistance. Then on the other hand we would bring economics and create new wealth through our projects and all these things. But the question is a very wide one and I do not think I can give its answer except in a big lecture.

श्री जसवन्तसिंह–Sir, the Chief Minister has said that there are certain factors which are beyond the purview of the Government. May we know which are those factors which are beyond the purview of the Government?

श्री जयनारायण व्यास–As I said, Sir, the question requires perhaps a big speech and I will reply to this question in my speech on the Budget. I think the Hon'ble Member should keep a little patience and wait for that time.

श्री जसवन्तसिंह–Sir, I asked a simple question and that is about the factors which are beyond the purview of the Government. Of course we will listen with very great interest the lecture on budget. But before that we would like to know the number of factors which are beyond the purview of the Government.

श्री जयनारायण व्यास–The number is numberless but if the Hon'ble Member likes, I can count a few ones; for example, grades of the staff Even before we integrated into the Rajasthan Union the staff was paid a grade which cannot be called 'Rajasthan grade', and we had to unify that grade and that grade cannot be reduced now. Now on account of there being more staff, we have perhaps to increase our expenditure and that is a factor which is perhaps beyond the purview of the Government.

श्री जसवन्तसिंह–My question is how can you not change the grades?

श्री जयनारायण व्यास–I would submit, Sir, that I will require at least half an hour if I narrate all these things, which are beyond the purview of the Government. Here I have narrated only one factor.

श्री जसवन्तसिंह–But what has the question of the Finances of the State to do with the grades of the staff and how is this outside the purview of the Government. This is a legitimate question, Sir.

श्री अध्यक्ष–Members can seek information by way of questions and when the answers are there they require study and after study if they want, they are entitled to ask subsequent questions. Answers involving general questions of policy and great elucidation of policies require lengthy time and such elucidation should always be in the Budget speech.

श्री हरिकृष्ण व्यास–One supplementary more, Sir.

श्री अध्यक्ष–Order! You should prepare yourself with the answer.

श्री हरिकृष्ण व्यास–I am ready with the supplementary.

श्री अध्यक्ष–Order!

प्रश्न संख्या ८८

श्री सरदारसिंह—क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे—

(१) राजस्थान में बेकारी मिटाने के लिए क्या क्या योजनाएं तैयार की जा रही हैं ?

(२) क्या सरकार को यह मालूम है कि टोंक जिले में अच्छे कारखाने व उद्योग धंधों के अभाव से बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ती जा रही है और इस कारण आबादी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, क्या सरकार के इस जिले में ऐसी बढ़ती हुई बेकारी को दूर करने के लिये कोई योजना विचाराधीन है ?

(३) अगर है, तो वह क्या व कबतक कार्यान्वित होजावेगी ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—राजस्थान से बेकारी मिटाने के लिए अनेक योजनायें हैं। भाखरा नांगल बांध, चम्बल स्कीम, जवाई स्कीम, माइनर प्रोजेक्टस् आदि और डिप्रेस्ड क्लासेज, को आगे बढ़ाने के लिए उनको आर्थिक सहायता आदि कई बातें बेकारी मिटाने के लिए की जा रही हैं।

(२) सवाल का दूसरा हिस्सा मेरे हिस्से में नहीं। मैं समझता हूं कि इस पार्ट को मुझे एड्रेस नहीं किया जाना चाहिये था।

श्री जसवन्तसिंह--अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया उनमें से कौन कौन सी बातें अमल में ली जाती है ?

श्री जयनारायण व्यास--मैंने जितनी भी बातों का उल्लेख किया वे सब अमल में आती हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या मुलाजिमों की छंटनी भी बेकारी दूर करने की योजना में शामिल है ?

श्री जयनारायण व्यास--जी हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या सरकार और ज्यादा लोगों की छंटनी कर ज्यादा बेकारी नहीं बढा रही है ?

श्री जयनारायण व्यास--जो मुलाजिम छंटनी के लायक होंगे उनको छांट कर उनकी जगह दूसरे व्यक्तियों को नियुक्त करना बेकारी दूर करने का उपाय है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या सरकार मुलाजिमों की छंटनी करना बेकारी दूर करने की योजना समझती है ?

श्री जयनारायण व्यास--मुलाजिमों की छंटनी करने की कोई योजना नहीं होती है; किन्तु बेकारी दूर करने की योजना होती है। इस योजना में यदि मुलाजिमों की छंटनी आवश्यक समझी जायगी तो वह भी की जायगी।

श्री सन्तोषसिंह--जिस इलाके में भाखरा-नांगल, चम्बल बांध आदि नहीं है उन जगहों के निवासियों की बेकारी मिटाने के लिए सरकार क्या उपाय सोच रही है ?

श्री जयनारायण व्यास--जहां तक फैमिन एरिया का ताल्लुक है वहां पर काम किया जाता है; जैसे पी.डब्ल्यू. डी. विभाग द्वारा, इरीगेशन विभाग द्वारा काम दिया जाता है।

श्री सरदारसिंह--टोंक भाखरा बांध से दूर है, इसलिये मैंने प्रश्न किया था ?

श्री जयनारायण व्यास--जहां पर बन्ध का काम नहीं वहां पी.डब्ल्यू.डी. विभाग द्वारा सडकें आदि बनवाना, माइनर इरीगेशन का काम, चम्बल बांध का काम जवाई का काम, सडकों का काम और इमारतें आदि बनवाने का काम, ऐसे बहुत से काम हैं। कई जगह स्कूलें खोली जायंगी। वहां शिक्षकों की नियुक्ति की जायगी। इसके साथ एक बात यह भी कह दूं कि जागीरें खत्म होजायंगी तो उनको जमीन देकर बेकारी दूर की जायगी, और बेकारों को खेती का काम देंगे। (हिअर-हिअर)

श्री सन्तोषसिंह--परगना बिलाडा में न तो सड़कों का काम है, न चंबल का काम है वहां की जनता जो बेकार है उनकी बेकारी मिटाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—ऐसे सवालों के लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार केवल योजनायें ही बनाती है या उन पर कोई ठोस कार्य भी होता है ?

श्री जयनारायण व्यास—सरकार योजना बनाकर उस पर ठोस कार्य भी करती है। कार्य करते हुए भी जो लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ तो उनकी सुनती भी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार जो कार्य करती है वह जनता की नजरों में नहीं आता है; इसका क्या कारण ?

श्री जयनारायण व्यास—लोगों की नजरों में आते हुए भी जो लोग सरकार के कार्य को नजरों से ओझल कर देते हैं इसमें सरकार का दोष नहीं है ?

प्रश्न संख्या ८६

(श्री अवनि कुमार द्वारा प्राधिकृत होने पर श्री जवानसिंह ने पूछा)

Will the Home Minister be pleased to state—

(*a*) How many murders were committed in Rajasthan with a view to terrorise the people not to vote for the Congress.

(*b*) Whether the Government can cite 6 such cases in which it has been proved in a Court of Law (or even alleged in a court of Law) that the murder committed was with a view to terrorise people not to vote for the Congress ?

(*c*) Have any other political murders been committed in Rajasthan and if any committed, what are the details ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप मुख्य मंत्री)–(*a*) Some murders were no doubt committed just before the general elections in Rajasthan. These were held, according to one section of the opinion, to be with the motive of terrorising the people. In such cases, it is rather doubtful to ascertain the precise nature of the motive particularly when it gets mixed up with other motives also. Whilst, therefore, some of the murders may have been committed with a view to terrorising the people not to vote for the Congress, it could not be cnocluded definitely after investigation as to how far the motive was entirely political. However, from the instances given in the answer to part (c) of the question, it appears that the possibility of there being an element of truth in this belief is not entirely ruled out.

(b) No. It was not possible to obtain witnesses in view of the intensity of the violence used and the non-arrest of dacoits employed on such crime some of whom had to be shot dead later in direct encounter by the police.

(c) List of political murders is as under :—

(i) Malar murder case—On 31-10-51 at about 4 P. M. fifteen armed dacoits on camels came to village Malar, district Jodhpur. They started firing on the Kisans belonging to one particular community of the village. Seven persons were shot dead and one more was injured. Then the dacoits set 8 houses to fire and proceeded to a neighbouring village Budhana, where they shot dead 9 more kisans of the same community and injured 2 more. These murders followed the preponderately Jat Kisan Sabha merging into the Congress in October, 1951. Also, the liquidation of dacoits Badan Singh and Ram Singh by the police on the information of certain kisans of these villages was avenged. Out of the assailants, who were also dacoits, (1) Khanura (2) Mohan Singh (3) Sugan Singh (4) Ratania Dholi alias Narain Singh (5) Ram Singh and (6) Binjraj Singh have been shot dead since by the police in direct encounter.

(ii) In Udaipurwati, district Jhunjhunu, two Congress workers, Shri Karni Ram Advocate and Shri Ramdeo Singh were murdered by shooting in broad day light in June last as a result of agrarian disputes prevailing between the Bhomias and the Kisans. Out of 19 accused persons fifteen have been arrested.

(iii) The proposer, Shri Doonga Ram, of the defeated Congress candidate, Shri Paras Ram, was shot dead while returning home on cycle. This was believed to have been done by a notorious dacoit Ram Singh, who has since been killed by the police in direct encounter. The seconder of Shri Paras Ram also lost his life in resisting a dacoity committed in his village Chadi,

(iv) Gurubux Singh murder case—One Shri Gurubux Singh, while returning after seeing brother-in-law along with his wife and his brother Shri Jog Singh, was attacked with spears by three persons, namely Pal Singh and two Mazhabi Sikh (names not known), with the result that Shri Gurubux Singh succumbed to injuries. It is mentioned in the F. I. R. that Pal Singh and his brother, Jogendra Singh, cherished ill-will against the deceased since the last election. Shri Gurubux Singh had helped the Congress while the party of Jogendra Singh was in opposition and could not succeed in the elections. The case has been registered and investigation is proceeding. The three accused are at large.

Page No.13

श्री जसवन्तसिंह–राजस्थान भर में जितने जुर्म हुए हैं क्या उन सभी की लिस्ट सुना दी है ।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)–जी नहीं, यहां सारी नहीं है ।

श्री जसवन्तसिंह–आप सिर्फ कांग्रेस वालों के लिए इन्ट्रेस्टेड हैं या आपके ध्यान में ऐसे इन्स्टान्सेज (उदाहरण) भी आये हैं जिनमे कांग्रेस वालों ने, जो उनके बरखिलाफ खडे हुए थे उनको भी मारा ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)–ऐसे केसेज ध्यान में नहीं आये हैं। जो क्वेश्चन (प्रश्न) पूछा गया है उसका जबाब दिया गया है । आप क्वेश्चन (प्रश्न) पढेंगे तो आपको मालूम होगा कि मेरा जबाब टू दी पाइन्ट है ।

श्री जसवन्तसिंह–मैं मानता हूं कि आपका जबाब टू दी पाइन्ट है । मैं सप्लिमेन्ट्री (पूरक) प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी उदाहरण आपके ध्यान में आया है जिसमें उल्टा नतीजा हुआ हो, जिसमें कांग्रेस वालों ने पिछले इलेक्शन में लडने के लिए, जो उनके खिलाफ खडे हुए हों, जिन्होंने उनके सामने कन्टेस्ट किया हो, उनको मारा ।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)–नहीं, मेरे ध्यान में ऐसी बात नहीं आई है । कांग्रेस और नॉन कांग्रेस का कोई सवाल नहीं है । सवाल पोलीटिकल मोटिव का है।

श्री कानसिंह–यह जो आंकडे आपने दिये हैं क्या डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी के है या किसी लीगल इन्क्वायरी की रिपोर्ट के हैं..........

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)–सवाल समझ में नहीं आया । थोडा माइक्रोफोन को दूर रख कर बोलें तो साफ समझ में आये ।

श्री कानसिंह–आपने जो आंकडे बताये हैं वह जुडीशियल इन्क्वायरी पर बेस्ड (आधारित) हैं या महज पुलिस की तफतीश पर बेस्ड (आधारित) हैं ?

श्री अध्यक्ष–यह जो फीगर्स हैं वह पुलिस की इन्क्वायरी पर आधारित है या जुडीशियल कार्यवाही पर ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)–यह डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट पर आधारित हैं ।

एक माननीय सदस्य–कितने ऐसे मुकद्दमें फैसल हुए हैं जिनमे यह साबित हुआ है कि कांग्रेस वालों को ही मारा गया है ।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)–मैंने यह कहा ही नहीं कि कांग्रेस वालों को मारा गया है। मैंने यह कहा है कि पोलीटिकल मोटिव्ज (राजनैतिक उद्देश्य) से कुछ क्राइम (अपराध) हुए हैं । वह भी एन्टायरली पोलीटिकल मोटिव्ज (केवल राजनैतिक उद्देश्य) से ही नहीं हुए हैं। कुछ उनमें

पोलिटिकल मोटिव्ज (राजनैतिक उद्देश्य) और कुछ पर्सनल मोटिव्ज (व्यक्तिगत उद्देश्य) के होंगे। मल्हार केस के बारे में, जो कि सबसे बडा इम्पॉर्टेन्ट (मुख्य) और सीरीयस (गंभीर) मामला हुआ है कह सकता हूं कि उसमें ८ आदमी तो एक गांव में मारे गये हैं और ६ आदमी एक जगह कत्ल किये गये। मैंने यह नहीं कहा कि उनका मोटिव एन्टायरली पोलिटिकल (उद्देश्य केवल राजनैतिक) था; बल्कि दोनो बातें थीं। उनमें एक बात यह भी थी कि उस गांव में यहां जो किसान मारे गये वे एक विशेषजाति के थे, और उनमें से ज्यादातर किसान सभा के मेम्बर्स थे जिनका कि उन्हीं दिनों कांग्रेस से पोलीटिकल एफीलियेशन (राजनितिक गठबन्धन) हुआ था। दूसरा जो मोटिव हो सकता था वह यह कि उन किसानों के इन्फर्मेशन (सूचना) देने पर एक बहुत बडा नोटोरियस (कुख्यात) डाकू, बदनसिंह मारा गया था। जिन्होंने यह कांड किया था वह उसके दोस्त थे, उससे कनैक्टेड थे। मैंने यह नहीं कहा है कि जो मर्डर (कत्ल) हुए हैं वे एन्टायरली पोलीटिकल मोटिव (केवल राजनैतिक उद्देश्य) से हुए हैं। पोलीटिकल (राजनैतिक) और पर्सनल (व्यक्तिगत) कन्सीडरेशन भी हो सकते हैं।

श्री गोपोलाल यादव—इकॉनामिक मर्डर्स, अनएम्प्लायमेंट मर्डर्स (आर्थिक कत्ल, बेकारी के कारण कत्ल) भी पोलीटिकल मर्डर्स (राजनैटिक कत्ल) में शामिल होते हैं या नहीं?

माननीय अध्यक्ष—ऑर्डर, ऑर्डर! नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६०

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Dy. Chief Minister be pleased to state :—

What is the number of village decoities in Sirohi District after its merger into Rajasthan?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—The number of village dacoities Sirohi District after its merger in Rajasthan is 5.

श्री जवानसिंह—क्या सिरोही जिले में तंवरी गांव में डेक्वायटी (डकैती) नहीं हुई?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—मैंने यह नहीं कहा कि नहीं हुई है। आपने डिस्ट्रिक्ट (जिले) के बारे में संख्या मांगी थी वह मैंने दे दी।

श्री मोहब्बतसिंह—इतनी डेक्वायटीज़ होने पर भी पुलिस और मिलिट्री की ज़ो स्ट्रेन्थ वहां थी वह कम क्यों कर दी है?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—यह दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। किसी एक साल के मुकाबले में ज्यादा हो सकती हैं और दूसरे साल के मुकाबले में कम। किसी एक इलाके, एक जिले के मुकाबले में ज्यादा, लेकिन ओन दी होल इन्टिग्रेशन (एकीकरण) से अब तक ३, ४ साल में एक डिस्ट्रिक्ट में केवल ५ डकैती होना कोई एबनोर्मल (असाधारण) बात नहीं है, साधारण सी बात है।

Page No.15

प्रश्न संख्या ६१

श्री श्यामलाल (डिविजन नं० १४४)--क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे-

(१) तहसील नादोती, जिला सवाई माधोपुर, में कितने व कहां कहां चौकीदार राज्य द्वारा मुकर्रर किये गये हैं ?

(२) उनकी खिदमत के मुआवजे में उनकी तनख्वाह मुकर्रर की गई है या जमीन दी गई है ?

(३) अगर जमीन दी गई है, तो कितनी और उसका लगान उनसे लिया जा रहा है या नहीं ?

(४) अगर हां, तो कब से और क्यों ?

(५) क्या अब उन चौकीदारों का लगान माफ किया जावेगा ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--(१) तहसील नादोती में चौकीदारों की जगह ५४ हैं जिनमें ५३ पर चौकीदार मुकर्रर कर दिये गये हैं ।

(२) २६ चौकीदारों को जमीन एलॉट कर दी गई है परन्तु उनका कब्जा अभी उनको नहीं मिला है । १० और चौकीदारों को जमीन एलॉट भी कर दी गई है और कब्जा भी दे दिया गया है, परन्तु उनका लगान अभी माफ नहीं हुआ है। १७ चौकीदारों को जमीन नहीं मिली है, उनका मामला विचाराधीन है ।

(३) इन ५४ चौकीदारों को ८२२ बीघा जमीन एलॉट हुई है, जो उनमें वितरित कर दी जायगी; परन्तु कितनी कितनी यह भी तय नहीं है; लेकिन यह शीघ्र ही तय हो जायगा ।

(४) उन चौकी दारों को ४६६ रु० १४ आ० का लगान माफ होगा ।

श्री श्यामलाल (डि० नं० १४४)--क्या महरबानी करके आप बतलायेंगे कि चौकीदारों से काम लिया जा रहा है या नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--जी हां, वह काम कर रहे हैं।

श्री श्यामलाल--क्या वह बेगार में काम कर रहे हैं ? उनका लगान माफ हुआ है या नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--उनके केसेज, (मामले) चल रहे हैं, और वे मन्जूर हो जायेंगे ।

श्री श्यामलाल--कब तक हो जायेंगे ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--जल्दी से जल्दी ।

श्री श्यामलाल--"जल्दी से जल्दी" की क्या तारीफ है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री—यह रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट बतायेगा ।

एक माननीय सदस्य–क्या नादोती तहसील के अलावा और भी जगह यह चौकीदार रखे गये हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)–राजस्थान के फॉर्मेशन (बनने) से पहले जयपुर यूनिट में चौकीदारी का रिवाज था ; अन्य भागों में नहीं था । वह अब फॉर्मर जयपुर स्टेट के एरिया में ही क्रियान्वित किया जा रहा है ।

श्री जवानसिंह–क्या यह कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई नई जागीरदारियां हैं ?

माननीय अध्यक्ष–आर्डर, आर्डर ।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)–अगर जागीरदार लोग इस तरह का काम सम्हाल लें तो उनकी जागीरदारियां हमेशा के लिए बनी रहेंगी ।

प्रश्न संख्या ६२

श्री सज्जनसिंह (डि० नं० १३२)—Is the Minister-in-Charge, Roads and Buildings answer:—

That in Nainwa Tehsil of Bundi District, the Fair Weather Road from Bansi to Dehi while passing through Bhanjeri village, has been so cut across the bank of the village Nala as to endanger a Baori and a temple. If yes, what steps he contemplates to be taken to remove the danger to the temple and the Baori.

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)–यह सडक १२ साल पहले बनाई गई थी । उस समय से अब तक पानी के कटाव के कारण कुछ थोडा फर्क उसमें आया है, जिसकी जांच की जा रही है, और उसकी दुरुस्ती कर दी जायगी । मंदिर और बावड़ी बनाने की जिम्मेदारी पी. डबल्यू. डी. की नहीं है ।

श्री रोशनलाल–१२ साल से अब तक उसकी रिपेयर नहीं हुई क्या ?

श्री सज्जनसिंह–मेरा प्रश्न बावड़ी और मंदिर के रिपेयर का नहीं है । मंदिर और बावडी के समीप बनाने से उनको खतरा है ; क्या यह सरकार के ध्यान में है ? यदि है तो सरकार उसका प्रबन्ध कर रही है ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)–सड़क की दुरुस्ती में जो इसमें सुधार करना आवश्यक होगा वह अवश्य किया जायगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास–वह सडक "ठीक नहीं" की केटेगरी में या "खतरनाक" की केटेगरी में पहुंच गई है ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)–यह फेयर वेदर रोड है । कच्चे टीले आने के कारण.....

श्री हरि कृष्ण व्यास–लेकिन कौनसी केटेगरी में सरकार इसको प्लेस करती है ।

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)–फेयर वेदर रोड ।

श्री अध्यक्ष–नेक्स्ट ।

श्री सज्जनसिंह–क्या मंत्री महोदय को विदित है कि उस सड़क पर एक बस सरविस रन करती है, और मंदिर की ऐसी स्थिति है कि अगर उसकी ठीक तरह से दुरुस्ती नहीं की गई तो उसके गिरने से आदमियों की जान का खतरा है ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)–मंदिर पी. डबल्यू. डी. का बनाया हुआ नहीं है । मंदिर जनता का बनाया हुआ है, और सडक बनाने से पहले खराब हालत में था । गिरते हुए मंदिर को बनवाने की जिम्मेदारी पी. डबल्यू. डी. पर नहीं है । वह सडक के दुरुस्ती की जिम्मेदारी ले सकती है ।

श्री सज्जनसिंह–लेकिन पी. डबल्यू. डी. के सड़क बनाने से खतरा बढ़ता है तो क्या पेसेन्जर्स के जान की हिफाजत करना सरकार का कर्तव्य नहीं ? उनकी हिफाजत करना सरकार का काम है । वह मंदिर ऐसी स्थिति पर पहुंच गया है कि उससे जान को जोखिम है ।

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)–फिलहाल सरकार उसकी ऐसी स्थिति नहीं मानती है ।

एक माननीय सदस्य–क्या सरकार उस सडक को मंदिर से दूर हटा देगी ?

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)–यदि इन्जीनियर्स की ऐसी राय होगी तो करेंगे ।

प्रश्न संख्या ६३

श्री तेजमल बापना–Sir, before I put Q. No. 93, may I know as to why some portions of it have been cut off ?

श्री अध्यक्ष–(पूछ-ताछ के पश्चात्) Because the question was comprehensive and it related to two separate Ministers. So some portions which related to one Minister have been taken and the remaining portion will come on the 18th.

श्री तेजमल बापना–क्या निर्माण मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या सरकारी दफ्तरों के लिए इमारत बनाने की सरकार की कोई योजना है ?

(२) यदि कोई है तो उसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है ?

(३) यदि नहीं, तो कब तक सरकार इतना किराया बर्दाश्त करेगी ?

श्री भोलानाथ—यह पूरा सवाल जिस शक्ल में था उसका जवाब इस प्रकार है :—

(१) भीलवाडे में इस समय कुल ३१ न्यायालय व दफ्तर हैं ।

(ब) इनमें से ८ तो राजकीय भवन में हैं और शेष ३ किराये पर हैं ।

(स) लगभग दो हजार रुपया प्रतिमास किराया चुकाना पडता है और गत चार वर्षों में ९५,१८४) रुपये चुकाने पडे हैं ।

(द) योजना तो है ही किन्तु साथ ही पूर्ण प्रयत्नशील भी ।

(घ) किये गये आर्थिक सहायता संबन्धी प्रयास के सफल होते ही ।

(ई) राजकीय भवनों का अभाव रहने तक, अनिच्छा होते हुए भी, विवशता वश यह रह सकता है ।

श्री तेजमल बापना—कब तक भवन निर्माण का काम वहां पर शुरू कर दिया जायगा । आखिर इसका कोई अनुमान भी लगा सकते हैं या नहीं ?

श्री भोलानाथ—मैं आशा करता हूं कि यह कार्य अगले वर्ष में शुरु कर दिया जायगा ।

श्री तेजमल बापना—एक लाख रुपया, जो मकानों के किराये में दिया गया यदि योजना पर लगाया जाता तो आज काफी मकान बन जाते ।

श्री भोलानाथ—मैंने जो रुपयों की तादाद बतलाई है वह ४ साल की रकम है ।

श्री रामदयाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि भीलवाडे के सिवाय दूसरी जगह भी इस प्रकार के भवन निर्माण का कार्य शुरू किया जायगा ?

श्री भोलानाथ—फिलहाल २० लाख की रकम खर्च करने का विचार है ।

श्री एच. के. व्यास—स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए कितने पैसे की दरकार है ।

श्री भोलानाथ—यदि अच्छे स्टेन्डर्ड के माफिक बनाए जाएं तो एक करोड रुपयों की ।

श्री रामदयाल—क्या भीलवाड़े में एक करोड रुपये लगेंगे ?

श्री भोलानाथ—नहीं, वहां तो करीब १० लाख से काम चल जायगा ।

प्रश्न संख्या ६४

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या अर्थ मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर डिविजन में कितनी संस्थाओं को सरकार द्वारा कितनी एड (aid) दी जाती है ?

Page No.19

(२) राजस्थान में कितनी व्यवसायिक कंपनियों को सरकार द्वारा कितनी रकम कर्ज अथवा सरकारी हिस्सों के रूप में दी गई है ?

(३) राजस्थान मे पंचायतों को, सरकार द्वारा, इस वर्ष कितनी सहायता दी गई ?

(४) राजस्थान के कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनको वेतन की दृष्टि से प्रथम श्रेणी में माना जावे ?

(५) राजस्थान के मंत्रियों को वेतन और यात्रा व्यय मिला कर कुल कितना रुपया सरकार से प्रति माह देना पड़ता है, औसतन सबसे अधिक और सबसे कम रकम किस मंत्री ने ली ?

श्री जयनाराण व्यास–अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत लम्बा चौडा है और वह किसी एक मंत्री से संबन्धित नहीं था; इसलिए में इस प्रश्न के आर्थिक पहलू पर जिससे कि मुझसे संबन्ध है, उत्तर देता हूं :–

(१) प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार की संस्थाओं के विषय में सूचना वान्छित है ।

(२) राजस्थान में स्थित २२ कंपनियों को सरकार द्वारा रु० १,६८,८३३।५।० सरकारी हिस्सों के रूप में दिया गया है ।

(३) वर्तमान वर्ष के रिवाइज बजट में पंचायतों की सहायता के लिये रु० १,१०,०००) का आयोजन है । वर्ष के अन्त तक यह समस्त द्रव्य सहायता के रूप में दिया जा चुकेगा ।

(४) अधिकारियों का वर्गीकरण केवल वेतन के आधार पर नहीं होता ।

(५) वर्तमान सरकार के सब मंत्रियों को मिलाकर औसतन, लगभग १२००), नहीं, नहीं रु० १२,०००) मासिक वेतनादि के रूप में दिया जाता है । इसमें मंत्रियों की मोटरों का व्यय, जो मंत्रियों को नहीं दिया जाता बल्कि सीधा गैराज ही को देय है, शामिल नहीं है । मुख्य मंत्री को छोडकर औसतन सबसे अधिक मासिक अदायगी राजस्व मंत्री को तथा सबसे कम श्रम मंत्री को हुई । मुख्य मंत्री को वेतन के अतिरिक्त रु० ५००) मासिक उपवेतन मिलता है ।

श्री एच. के. व्यास–बराबर आंकडों में अदलाबदली क्यों की जाती है यह मेरी समझ में नहीं आया ?

श्री जयनारायण व्यास–में आपको समझ नहीं पाया ।

श्री एच. के. व्यास–कभी १२००) और कभी १२००) के बदले १२ हजार बतलाना यह मेरी समझ मे नहीं आया ।

श्री जयनारायण व्यास–अगर कोई चीज गलत बोल दी जाती है तो समझदार आदमी उसको दुरुस्त किया करते हैं ।

प्रश्न संख्या ६५

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :—

(१) उदयपुर डिविजन में कितनी कन्याशालायें हैं ?

(२) उनमें कितनी अध्यापिकायें किस किस योग्यता की रखी हुई हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा—उदयपुर डिविजन में १३२ कन्या पाठशालाएँ हैं, जिन में ३१२ अध्यापिकायें हैं, जिनकी योग्यता का विवरण नीचे दिया हुआ है:—

ग्रेजुएट	८
इन्टर	६
मैट्रिक	२४
ट्रेन्ड मिडिल	४१
मिडिल	११६
नोन मिडिल	१०६
संगीत	५

श्री रामदयाल—क्या सरकार को मालूम है कि मिडिल स्कूलों में बहुत सी हैड मिस्ट्रेसेज ऐसी हैं जो खुद मिडिल पास नहीं हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा—ऐसा कोई केस हमारे ध्यान में नहीं है।

श्री रामदयाल—क्या ऐसे मामले सरकार के ध्यान में लाने पर सरकार इन्सपेक्टरों व डिप्टी इन्सपेक्टरों को, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिये हिदायत करेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा—जब यह भी मालूम नहीं है कि कितने ऐसे केसेज हैं तो ऐसी हालत में कैसे हिदायत की जा सकती है।

श्री रामदयाल—क्या सरकार उनके खिलाफ......

श्री अध्यक्ष—नेक्सट्

प्रश्न संख्या ६६

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister-in-charge, Jail Department, be pleased to state.—

Why Sirohi Jail has been reduced to the status of a lock-up ?

श्री टीकाराम पालीवाल—Sirohi Jail has not been reduced to the status of a lock-up so far.

It has been suggested by the Economy Committee that it may be converted into a lock-up because the population of convicted prisoners at Sirohi Jail does not justify to keep it a Jail.

The average number of convicted prisoners in Sirohi Jail is 21. The total population required for 'D' class Jail should be between 50 and 100 prisoners.

श्री मोहबतसिंह–जोधपुर जिले में ५६५१ कैदी....

श्री टीकाराम पालीवाल–I do not see the point of my Hon'ble friend will it add to the prestige of the Sirohi District to have more convicts there.

श्री अध्यक्ष–Ignorance is bliss.

श्री मोहबतसिंह–क्या वजह है कि जब सिरोही में जेल है तब कैदियों को पाली भेजा जाता है।

श्री टीकाराम पालीवाल–कैदियों को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्विनीएन्सके हिसाब से एक जगह से दूसरी जेल में रखा जाता है और यदि आवश्यकता हुई तो माननीय सदस्य की इच्छाओं का आदर किया जायगा।

एक सदस्य–मैंने कल भी एक प्रश्न Agriculture Office खोलने के बारे में पूछा उस समय भी सरकार की तरफ से Administrative Convenience के बारे में कहा गया था। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि Administrative Convenience का क्या मतलब है।

श्री टीकाराम पालीवाल–Administrative Convenience की तारीफ करना मुश्किल है। मैं यह.................

श्री अध्यक्ष–ऑर्डर, ऑर्डर !

प्रश्न संख्या ६७.

श्री श्यामलाल–क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

जिला सवाई माधोपुर में अन्डरट्रायल कैदियों पर वे दैनिक भोजन में क्या व्यय किया जाता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल––जिला सवाई माधोपुर जेल से प्राप्त आँकडों के अनुसार उस जेल के एक अण्डरट्रायल कैदी के दैनिक भोजन का खर्चा साढ़े आठ आना होता है ।

श्री श्यामलाल–किस आधार पर साढ़े आठ आना रोज खर्चा होता है ? क्या इस संबन्ध म कोई रूल्स बने हुए हैं ?

Page No.22

श्री टीकाराम पालीवाल—जेल के नियम इस संबन्ध में बने हुए हैं, जिनके अनुसार १० छटांक एक अंडर ट्रायल को, साढे दस छटांक साधारण कैदी को और १२ छटांक रिगरस इम्प्रिजनमेंट वाले कैदी को खुराक दी जाती है। लेकिन इस खुराक की कीमतें अलग अलग जगहों पर अलग अलग आती हैं।

प्रश्न संख्या ६८

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या गृह मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि:

उदयपुर डिविजन में कई पुलिस चौकियों को नये हथियार देने के नाम पर, हथियार मंगा कर अब तक बिना हथियार क्यों रक्खा जा रहा है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—उदयपुर डिविजन में जो पुलिस चौकियें हैं उनमें हथियार दिये जा चुके हैं, और सब से पहले हथियार उन चोकियों में दिये गये जो पाली डिस्ट्रिक्ट की सरहद पर पडती हैं क्योंकि वहां डकेतियों का जोर था। दीगर चौकियों में हथियार बाद में दिये गये।

श्री रामदयाल—यह हथियार, यह सवाल पूछने से पहले दिये गये या बाद में।

श्री टीकाराम पालीवाल—पहले ही दिये गये।

प्रश्न सख्या ६९

श्री भवानीसहाय शर्मा—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(अ) पंचवर्षीय योजना में अलवर जिले की कौन कौन सी सडकें तैयार की जावेगी ?

(ब) नारायणपुरा–कुशलगढ की सडक की हालत कैसी है ?

(स) नारायणपुरा से तालवृक्ष तक की सडक को पक्की बनाने की कोई योजना है ?

(द) प्रतापगढ से थाना गाजी की सडक कितनी कच्ची है और कितनी पक्की है ?

(र) क्या नारायणपुरा से घाटा बांदरोल की सडक पक्की बनाई जाने की योजना है ? यदि है तो उसपर कितनी रकम खर्च की जाने की सरकार ने इजाजत दे दी है ?

श्री भोलनाथ—(अ) अलवर जिले में पंचवर्षीय योजना में सडकें बनाने की योजना है।

(ब) कोई नियमित सडक नारायणपुरा से कुशलगढ़ तक नहीं है, केवल शिकार की सडक (ट्रेक) है। नारायणपुर से तालवृक्ष तक की सडक को पक्की बनवाने की योजना नहीं है।

(स) प्रतापगढ़ से थाना गाजी सडक २ मील पक्की है और १४ मील कच्ची है।

(द) नारायणपुरा से घाटा बांदरोल की सडक पक्की बनाई जाने की योजना है। इस सडक के लिये पंचवर्षीय योजना में १,५०,००० रु. प्रस्तावित किया गया है। ५०,००० रु. आर्थिक वर्ष १९५४–५५ में व १,००,००० रु० १९५५–५६ में।

प्रश्न संख्या १००

श्री भवानीसहाय शर्मा–क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) अलवर जिले में १९५२ में कितने स्कूल भवनों की मरम्मत करवाई है ?

(ख) लक्ष्मणगढ़ हाई स्कूल बनवाने में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने किस मद (हैड) से यह रुपया दिया है ?

(ग) लक्ष्मणगढ स्कूल भवन को नये रुप में बनवाने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कितनी रकम का ठेका दिया है ?

श्री भोलानाथ–(अ) आर्थिक वर्ष १९५२–५३ में अलवर जिले में ४६ स्कूलों की मरम्मत करवाई है ।

(ख) निर्माण विभाग ने लक्ष्मणगढ हाई स्कूल-भवन बनाने के वास्ते ५० पी. डब्ल्यू. (डी) (१) इमारतों की मरम्मत की मद से यह रुपया दिया है ।

(ग) लक्ष्मणगढ हाई स्कूल भवन नये रुप से बनाने की अभी कोई योजना नहीं है ।

केवल किले के भवन की मरम्मत करवा कर इसे हाई स्कूल के भवन में परिवर्तित किया गया है ।

(घ) "घ" का जवाब "ग" में आगया है ।

श्री रामदयाल–अलवर जिले में तो खर्चा कर दिया गया, दूसरी जगह नहीं किया इसका क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ–मरम्मत सभी जिलों की स्कूलों की करवाई गई है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या गंगानगर जिले में भी स्कूलों की मरम्मत करवाई गई है ?

श्री भोलानाथ–सब जिलों में करवाई गई है ।

श्री रामदयाल–जिन जिन स्कूलों की मरम्मत करवाई गई है उनके नाम बताये जायें ।

श्री भोलानाथ–यदि चाहेंगे तो लिस्ट बाद में पेश कर सकूंगा ।

प्रश्न संख्या १०१

श्री तेजमल बापना–Will the Education Minister be pleased to state.—

(i) How many new Primary and Secondary Schools have been opened in Bhilwara District and in Jodhpur District from 1st April to 31st December, 1952 respectively?

(*ii*) What is the percentage of education in Bhilwara District ?

(*iii*) Is the Government planning to establish at least one school within a radius of six miles ?

(*iv*) How many new schools, primary or secondary, will be opened in Bhilwara District in the year 1953-54 ?

(*v*) If no school is to be opened, what other means do the Government propose for improving education in Rajasthan in general and Bhilwara District in particular ?

श्री नाथूराम मिर्धा–(१) भीलवाडा तथा जोधपुर जिलों में १–४–५२ से ३१–४–५२ तक कोई प्राइमरी अथवा सैकिन्ड्री स्कूल नहीं खोले गये ।

(२) भीलवाडा जिले में शिक्षा का प्रतिशत अनुमानतः २३ है ।

(३) ऐसी कोई स्कीम विचाराधीन नहीं है ।

(४) ऐसे स्कूल खोले जाने की सरकार की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है । आगामी वर्ष में खुलने वाले स्कूलों की संख्या की स्वीकृति प्राप्त होने पर अन्य जिलों में खोले जाने वाले स्कूलों के स्थानों के साथ साथ भीलवाडा-जिले के स्थानो पर भी विचार किया जावेगा ।

(५) अभी यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री खेतसिंह– इस अर्से में स्कूलें नहीं खोली गईं, क्या इसके लिये सरकार को फक्र है ?

श्री नाथूराम मिर्धा–पिछले साल सरकार ने नई स्कूलें खोलने की स्कीम नहीं बनाई थी, इस साल खोली जायेंगी ।

श्री अध्यक्ष–The Hon'ble Members will ask supplementaries and not to put sarcastic questions. They can seek information in a decent way also.

श्री रामदयल––क्या सरकार यह समझती है कि भीलवाड़े में बहुत स्कूलें हैं ?

श्री नाथूराम मिधा––वहां ऑलरेडी स्कूलें हैं । पिछले साल स्कूलें खोलने की सरकार की योजना नहीं थी । इस साल योजना है । उस योजना के अनुसार जब दूसरी जगह स्कूलें खोली जायंगी उनके साथ साथ भीलवाड़ा ज़िले के लिए भी विचार किया जायगा ।

श्री मोहब्बत सिंह––क्या आर्थिक संकट की वजह से मंजूरी नहीं मिली ?

श्री नाथूराम मिर्धा––हां ।

श्री मोतीराम––कुछ स्कूलें सेठों की तरफ से खोली गई थीं, उनके सम्बन्ध में क्या हो रहा ह ?

श्री नाथूराम मिर्धा––यह एक दूसरा प्रश्न है जो इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता ।

श्री संतोषसिंह—गवर्नमैन्ट बार बार घाटे में जा रही है; तो क्या हम यह समझ लें कि हम अब सरकार के सम्मुख स्कूलें खोलने का नाम न लें।

श्री नाथूराम मिर्धा–बराबर नाम लीजिये। हमेशा घाटा ही घाटा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। पैसा भी आयगा। अब लगातार स्कूलें खोली जायंगी, आप चिन्ता नहीं करें।

श्री रामदयाल—नई स्कूलें खोलना तो दूर रहा, भीलवाडे में जो स्कूल चल रही थी वह भी बंद हो गई है।

श्री नाथूराम मिर्धा—मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

प्रश्न संख्या १०२

श्री तेजमल बापना–Will the Education Minister be pleased to state.—

(*i*) What are the subjects taught in Intermediate classes in Maharana College, Bhilwara?

(*ii*) Is Steno-typing also a subject there?

(*iii*) Is it a fact that no lecturer has been appointed there for the last two years for the teaching of Steno-typing and many students have left the College?

(*iv*) How many years more will it take the Government to make the appointment.

श्री नाथूराम मिर्धा—(१) निम्नलिखित विषय गवर्नमैन्ट इन्टर कालेज, भीलवाडा की माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाये जाते हैं–

१. अंग्रेजी
२. हिन्दी
३. इतिहास
४. नागरिक शास्त्र
५. वाणिज्य

(२) हां।

(३) भीलवाड़ा इन्टर कॉलेज सन् १९५१ में आरम्भ किया गया था। कॉमर्स का लेक्चरार वहां क्लासेज के आरम्भ से ही कार्य कर रहा है, किन्तु उन्हें स्टेनो टाइपिंग नहीं आता। इस पर स्टेनो टाइपिंग जानने वाले एक अन्य लेक्चरार का वहां स्थानान्तर किया गया, किन्तु बाद में वह आज्ञा निरस्त कर दी गई। इसके बाद इस विषय को जानने वाले एक अन्य लेक्चरार की नियुक्ति की गई, किन्तु उन्होंने ज्वाइन नहीं किया।

कॉमर्स विभाग के दो लेक्चरार जो स्टेनो टाइपिंग की शिक्षा भी देने योग्य हैं पहले से ही नियुक्त कर दिये गये हैं।

(४) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

श्री संतोषसिंह--क्या सरकार धर्म शिक्षा का सब्जेक्ट (विषय) रखने से डरती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा--मेरे ख्याल से इस प्रश्न से धर्म शिक्षा का कोई सवाल पैदा नहीं होता।

श्री संतोषसिंह--प्रश्न में यह पूछा गया था कि कौन कौन से विषय रखे गये हैं। क्या धर्म शिक्षा का विषय नहीं रखा गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा--अब तक इस विषय की कोई आवश्यक्ता महसूस नहीं हुई और न लोगों ने ही इसके लिये मांग की।

श्री हरीकृष्ण व्यास--क्या कॉमर्स में स्टेनो टाइपिंग इन्कल्युडेड (सम्मिलित) नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा--कॉमर्स में कई अलग अलग विषय है जिनमें से स्टेनो टाईपिंग भी एक है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो कॉमर्स के जो शिक्षक भीलवाड़ा भेजे गये वे स्टेनोटाइपिंग न जाननेवाले क्यों भेजे गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा--मैंने इसीलिये कहा था कि पहले जो टीचर भेजे गये थे वे स्टेनो टाइपिंग नहीं जानते थे और अब उनके बदले में एक दूसरे आदमी को जो इस विषय को जानते हैं, भेजे गये हैं।

श्री जसवन्तसिंह--सवाल यह है कि पहले ऐसा टीचर क्यों भेजा गया जो स्टेनोटाइपिंग नहीं जानता था ?

श्री नाथूराम मिर्धा--स्टेनो टाइपिंग जानने वाले लेक्चरार नहीं मिल रहे थे और जो एक दो मिले थे उन्होंने ड्यूटी जोइन नहीं की थी।

श्री जसवन्तसिंह--क्या राजस्थान गवर्नमेन्ट के रिसोर्सेज ऐसे ही हैं जिससे उनको ऐसालेक्चरार नहीं मिल सका ?

श्री नाथूराम मिर्धा--इसमेंरिसोसज का कोई सवाल नहीं है। जो ग्रेड उनके लिये नियत हैं उनमें कोई योग्य आदमी नहीं आया: इसलिये नहीं भेजा गया।

श्री जसवन्त सिंह--क्या सरकार को विदित है कि स्टेनो टाइपिंग जानने वाले बाजार में इतने घूमते हैं कि नौकरी भी कहीं नहीं मिलती ?

श्री नाथूराम मिर्धा--शायद आपको बाजार में मिलते होंगे, पर हमको तो नहीं मिले।

एक माननीय सदस्य—हम आपको बता सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसा क्या कारण है कि सरकार को स्टेनो टाइपिस्ट नहीं मिल रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा—मेरे ख्याल से आप स्टेनो टाइपिस्ट का मतलब उनसे समझ बैठे हैं जो क्लर्क स्टेनो टाइपिंग का काम करते हैं। पर अध्यापक उन्हीं को रखा जासकता है जो कोर्स की डिग्री लिये हुए हों और स्टेनो टाइपिंग जानते हों।

श्री जसवन्तसिंह—दूसरी जगहों पर तो ऐसी शिकायत नहीं आई। क्या कारण है कि राजस्थान में ही यह शिकायत सुनने को मिलती है ?

श्री नथूराम मिर्धा—यह हमारा दोष नहीं है।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार उन स्टूडेन्ट्स (छात्रों) को कंपेन्सेट (Compensate) करने का विचार कर रही है जिनका समय व्यर्थ ही बरबाद किया गया ?

अध्यक्ष महोदय—ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री तेजमल बापना—क्या सरकार ने इन स्टेनोग्राफर अध्यापकों के लिये सूचना निकाली थी ?

अध्यक्ष महोदय—ऑर्डर ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या १०३

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या प्लानिंग मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

भीलवाड़ा जिले के विकास के लिये जो धन सरकार को केन्द्र द्वारा इस वर्ष दिया गया है वह जिले के किन किन विकास कार्यों में कितना कितना व्यय किया जावेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जो जो कार्य भीलवाडा जिले में सिंचाई निर्माण, सहकारी, कृषि व ग्राम पंचायत विभाग द्वारा किया जाना है वह इस प्रकार है—

(१) सिंचाई विभाग

नाम कार्य	रुपया
१. जारोल तालाब	१.१४ लाख
२. लालला तालाब	०.०२ लाख
३. बरतपुरा तालाब	०.०८ लाख
४. मगवापुरा तालाब	०.०२ लाख
५. बरनागर तालाब	०.१५ लाख
६. कामलिया वास तालाब	०.१० लाख

Page No.28

७. नवलपुरा तालाब	०.५० लाख
८. दुलह् सागर	०.४८ लाख
९. शिवपुरा तालाब	०.३० लाख
१०. बरुदनी तालाब	०.४६ लाख
११. सावलपुरा तालाब	०.२२ लाख
१२. गोवता	९.६३ लाख
१३. उमेदसागर	४.०० लाख
१४. नाहरसागर तालाब	३.८० लाख
१५. मेजा प्रोजक्ट	१०.०० लाख
१६. खारी प्रोजक्ट	०.८० लाख
१७. मानसी प्रोजक्ट	०.८० लाख

(२) निर्माण

१. भीलवाडे से काँकरोली तक पक्की सडक	५,००,०००
२. भीलवाडे से मांडलगढ तक पक्की सडक	४,००,०००
३. नसीराबाद से नीवाहेडा तक सड़क का कच्चा व पक्का भाग	९,१८,०००
४. शाहपुरा, जाहजपुर की पक्की सडक	५,७५,०००
५. देवगढ से माँडल तक पक्की सडक	६,००,०००
६. असिन्द मांडल कच्ची सडक का निर्माण	१,३०,०००

इसके अलावा निम्नलिखित उपमार्ग और लिये गए हैं।

१. बानेरा से शाहपुरा : मांडल सड़क	३०,५००
२. कुर्दा से गुलाबपुरा ग्राम तक पक्का उपमार्ग	३४,१००
३. रायेला ग्राम से रायेला किलेग स्टेशन और इम्पीरियल सड़क तक पक्का उपमार्ग	२५,५००
४. बेगम काठुन्डा उपमार्ग	३९,७६६
५. गंगरार ग्राम से गंगरार स्टेशन तक	२८,९००
६. गंगापुर से भीलवाडा कांकरोली को मुख्य सड़क तक	१७,६००
७. हमीगढ ग्राम से नसीराबाद निम्बेहरा सड़क तक	१४,६००

(३) सहकारी विभाग

सन्	सहकारी शिक्षा	सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता
१९५१-५२	...	...
१९५२-५३	६२० ट्रेनिंग ऑडीटर व सहायक इन्सपेक्टर	...

ग्राम पुर्ननिर्माण

१९५१,५२	...	...
१९५२-५३	...	...

(४) कृषि विभाग

कृषी उन्नति के लिये निम्न योजनाएं बनाई गई हैं।

१. प्लान्ट प्रोटेक्शन

२. टिड्डी से बचाव

३. बीज वितरण

४. कृषि शिक्षा

५. कृषि अन्वेषण

६. अमुक अधिक अन्न उपजाऊ उपाय

उपरोक्त योजनाओं में से भीलवाडा जिले में बीज वितरण के लिये गोदाम बनाये जायंगे, जिसमें प्रति गोदाम निम्न खर्चा होगा—

गोदाम बनाने का खर्चा	१५,०००
कीमत बीज	२०,०००
स्टाफ, चोकीदार आदि	५५०
	३५,५५०

इसके अतिरिक्त दूसरी योजनाओं में से भी आवश्यकतानुसार खर्चा किया जावेगा।

(५) पंचायत विभाग

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान के गांवों में पीने के पानी के साधनों के निर्माण एवं प्रबन्ध के लिये जो रुपया ग्राम पंचायतों द्वारा व्यय करने की योजना है उसमें से भीलवाडा जिले के लिये चार लाख रुपया शामिल है।

सन् १९५२-५३ की धन राशि से भीलवाडा जिले में उपरोक्त कार्य हेतु ८१,१२० रुपये खच करने की योजना है जिसका विवरण संलग्न सूचि में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

नोट:—तीन पृष्ठ कार्य-विवरण के पीछे परिशिष्ट की भांति बनाये गये हैं।

श्री रामदयाल--महुवा और हिंडोन की तरफ क्या पंच वर्षीय योजना का कार्य प्रारम्भ हो गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल--हां, कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के जो ब्लॉक हैं उनमें से महुवा हिंडोन भी एक है जहां कार्य प्रारम्भ होगया है ।

श्री रामदयाल--क्या इसमें डूंगरपुर भी शामिल है ?

श्री टीकाराम पालीवाल--महुवा हिंडोन में यह शामिल नहीं है ।

श्री रामदयाल--जो क्षेत्र पहले चुने गये हैं क्या वे मिनिस्टरों के चुनाव क्षेत्र ही हैं या इसके अलावा और भी हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल--चुनाव क्षेत्र की दृष्टि से योजना क्षेत्र नहीं बनाये गये हैं। डूंगरपुर को जब योजना क्षेत्र में शामिल किया गया था तो वहां के कोई व्यक्ति मिनिस्टर नहीं थे ।

श्री भीमसिंह--किस आधार पर ये क्षेत्र चुने गये हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल--उदयपुर ऐसा क्षेत्र चुना गया है जहां का कोई मंत्री नहीं है ।

श्री भीमसिंह--किस आधार पर ये क्षेत्र चुने गये हैं यही मेरा प्रश्न था ?

श्री टीकाराम पालीवाल--कम्युनिटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ हिदायतें निकाली थीं उनके आधार पर आबादी के अनुपात को ध्यान में रख कर, जहां पर दूसरी सुविधायें, जैसे इरिगेशन, मेडिकल एड, शिक्षा सुविधा आदि को ध्यान में रखकर, ये क्षेत्र चुने गये हैं ।

श्री मोहम्मद इब्राहिम--क्या भरतपुर जिला भी इस योजना में शामिल है ?

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट ।

श्री मोहम्मद इब्राहिम--मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया ।

श्री टीकाराम पालीवाल--पंच वर्षीय योजना में भरतपुर जिला भी शामिल है ।

प्रश्न संख्या १०४

श्री श्यामलाल--क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) पंच वर्षीय योजना में सब डिविजन गंगानगर में क्या क्या कार्य होंगे ?

(२) सब डिविजन हिंडोन में क्या क्या कार्य होंगे ?

श्री टीकाराम पालीवाल (योजना मंत्री)–पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जो जो कार्य सब-डिविजन गंगापुर व सब डिविजन हिन्डोन में पी. डब्ल्यू. डी., सिंचाई, कृषि व सहकारी विभाग के संबंध में किये जायगे, वे इस प्रकार हैं:—

हिन्डोन : १. लालसोट से हिन्डोन तक की सड़क के १७ मील कच्चे भाग को पक्का बनाना ।

२. कोटली, करोली, हिन्डोन सडक ८ मील ।

३. जगर से हिन्डोन तक की कच्ची सड्क १० मील ।

४. धोलेला धावन से हिन्डोन तक की पक्की सडक ।

५. बयाना से हिन्डोन तक की सडक ११ मील के कच्चे भाग को पुनः पक्का बनाना ।

गंगापुर : १. मोरा सागर से बामनवास और फिर गंगापुर लालसोट की कच्ची सडक ।

सिंचाई : नाग तलाई बन्ध :–इस योजना पर लगभग १,७५,००० रु० व्यय होगा और २ हजार एकड़ की सिंचाई होगी । इस वर्ष इससे लाभ होने की आशा है ।

हिन्डोन सब डिविजन में जग्गर वन्ध योजना पर लगभग १४ लाख रुपया व्यय होगा और १० हजार एकड भूमि की सिंचाई होगी ।

कृषि योजना :–१६ करोड ८१ लाख की रकम में से कृषि विभाग को १ करोड २६ लाख रुपये कृषि उन्नति के लिये दिये गये हैं । इस रकम से ये योजनाएं बनाई गई हैं

१. प्लान्ट प्रोटेक्शन, २. टिड्डी से बचाव, ३ बीज वितरण, ४. कृषि शिक्षा, ५. कृषि अन्वेषण, ६. अमुक अधिक अन्न उपजाऊ उपाय ।

श्री अध्यक्ष–जबाब अगर लंबा हो तो टेबल पर रख दीजिये ।

श्री टीकाराम पालीवाल–में टेबल पर जवाब रख दूंगा ।

श्री रामदयाल–में गंगापुर........

श्री अध्यक्ष–टेबल पर जवाब रख दिया जायगा । (कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री एच. के. व्यास–According to Rule 38, lengthy answers to questions may be placed on the table of the Assembly without being read but a copy in such case may invariably be given to the Member asking such question.

श्री अध्यक्ष–The time is up and naturally all the questions which have not been answered, their answers will be put on the table. If the Hon'ble member thinks it necessary to put another question which arises out of those answers he can table any questions.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

We proceed with the next agenda.

राजस्थान सहकारी समिति विधेयक, १६५२, पर श्रीमन् राजप्रमुख के अनुमोदन प्राप्त होने की घोषणा

श्री मनसाराम पुरोहित (सचिव)–Sir, I have to inform the House that His Highness the Rajpramukh has given his assent to the Rajasthan Co-operative Societies Bill, 1952, which was passed by the Rajasthan Legislative Assembly during its October-November, 1952, session.

विधान कार्य

श्री अध्यक्ष—We come to the Legislative business.

पुरः स्थापित होने वाले विधेयक

राजस्थान उत्पाद भाटन नियामक 'संशोधन' विधेयक, १६५२

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)–I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Rajasthan Produce Rents Regulating Act, 1951.

श्री अध्यक्ष–The question is that leave be granted to introduce a Bill further to amend the Rajasthan Produce Rents Regulating Act, 1951.

(स्वीकृत)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया–I introduce the Bill.

राजस्थान अकाल (कार्यवाहियां-स्थगन) संशोधन विधेयक, १६५३

श्री मोहन लाल सुखाडि–मैं राजस्थान अकाल (कार्यवाहियां–स्थगन) अधिनियम, १६५२ (अधिनियम संख्या २१, सन् १६५२,) का संशोधन करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

राजस्थान तमाखू विक्रेता अनुज्ञापत्र विधेयक, १६५२

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)–मैं, निर्मित तमाखू के फुटकर विक्रय का आनियमन करने वाला विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

भारतीय, पंजीयन (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १६५३

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—मैं, राजस्थान में लागू होने वाले, भारतीय पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) अधिनियम १६०८, का संशोधन करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री एच. के. व्यास–Is the Revenue Minister not introducing the Bill.

श्री अध्यक्ष--(राजस्व मंत्री को संबोधित करते हुए) I think you have only sought leave to introduce the Bill.

(विराम)

I think that was for introduction and not for leave.

(विराम)

I may announce that there was a little mistake when the leave of the House was granted for introduction of the Rajasthan Produce Rents Regulating (Amendment) Bill. The Hon'ble Member did not actually introduce the Rajasthan Produce Rents Regulating (Amendment) Bill. So we should take it that this Bill has been introduced and the proceedings will be corrected accordingly.

श्री अध्यक्ष--We come to further discussion on the debate on H. H. the Rajpramukh's Address.

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर सामान्य वाद-विवाद

श्री मांधोसिंह--अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाशण पर वाद-विवाद चल रहा है। मैं, हालांकि सदन की इजाजत से दो चार दिन बाद में आया हूं, दो-तीन महत्व के विषयों पर अर्ज करना चाहता हूं।

राजस्थान की आर्थिक स्थिति के बारे में यह बतलाया गया है कि हमने सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से आर्थिक मदद ली है और इससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और हम धन्यवाद दें। किन्तु अर्थ विभाग द्वारा जो गलतियां की गईं और उन गलतियों के करने पर अर्थ मंत्री से उनका जो पोर्टफोलियो छीना गया है उस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)-This is objectionable, Sir.

श्री अध्यक्ष-The Hon'ble Member will speak with some grace, I think.

श्री माधोसिंह-तो अर्थ (Finance) के मुतल्लिक सरकार क्या कदम उठाने जा रही है और आयन्दा अर्थ विभाग का किस तरह से सुधार होगा एवं राजस्थान की आर्थिक स्थिति किस प्रकार सुधरेगी, इस ओर अभिभाषण में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है।

श्रीमन् राजप्रमुख महोदय ने शिक्षा विभाग पर छोटा सा अभिभाषण दिया है और यह फरमाया है कि शिक्षा विभाग राजस्थान में जगह जगह पर उन्नति कर रहा है। किन्तु जो हालत आज शिक्षा विभाग की है उससे क्या यह मालूम हो सकता है कि शिक्षा मंत्री ने शिक्षा के प्रश्न को समझा है? शिक्षा मंत्री

[श्री माधोसिंह]

ने नींद ली है और प्रचार के लिए कुछ भी कार्य किया है । इस संबंध में जो कुछ गलतियां की गई थीं तो उन पर श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर जरूर प्रकाश डाला जाना चाहिये था । सरकार चाहती तो जो गलतियां सरकार द्वारा की गई हैं उनको श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में रख सकती थी ताकि सदस्यों को मालूम होता कि अमुक गलतियां की गई हैं और अमुक गलतियों में सुधार किया जा रहा है । हमें खेद है कि हम श्रीमन् राजप्रमुख को धन्यवाद नहीं दे सकते क्योंकि सरकार ने जो गलतियां की हैं उनके विषय में सदन को पर्दे में डालकर, उन्हें छिपाया गया है और यह इसलिए किया गया है कि सदन के सामने उनकी त्रुटियां पेश न हो सकें । इसलिए में इन (विरोधी सदस्यों की ओर इशारा करते हुए) सदस्यों के साथ हूं । अध्यक्ष महोदय, में आपके जरिये उन सदस्यों को (ट्रेजरी बेन्च की ओर इशारा करते हुए) अपनी आवाज पहुंचा देना चाहता हूं कि श्रीमन् राजप्रमुख महोदय को धन्यवाद देने में मैं उनका साथ नहीं कर सकता ।

डा० श्री मंगलसिंह—अध्यक्ष महोदय, इस सत्र के आरम्भ में श्रीमन् राजप्रमुख ने जो अभिभाषण दिया है उन्होंने पिछले कुछ महीनों की कार्यनीति का दिग्दर्शन कराया है और भविष्य के लिये पथ प्रदर्शन किया है। इस अभिभाषण पर जो हमारे माननीय विद्वान मित्र, श्री गुलाबचन्द कासलीवाल ने जो प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं दो-चार शब्द कहना चाहता हूं ।

श्रीमान् राजप्रमुख ने सबसे पहले इस प्रान्त की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है । उन्होंने आर्थिक स्थिति को बडी गम्भीर और कठिन परिस्थिति में बतलाया है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रान्त की आर्थिक स्थिति कुछ सालों से बराबर बिगड़ती चली जा रही है लेकिन किसी देश या प्रदेश की आर्थिक स्थिति केवल रुपये, आना, पाई के आंकडों से ही नहीं आंकी जा सकती है ।

किसी देश या प्रदेश की आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए चार मुख्य बातों को देखने की आवश्यकता है :—

पहली, प्रदेश की भूमि, उसके खनिज पदार्थ एवं उनके यहां का कच्चा सामान और गृह-उद्योगादि ।

दूसरी बात, जो कच्चा सामान आदि उपलब्ध है, उसका संकलन, उत्पादन, और विक्रय करने की लोगों में क्षमता है या नहीं; वह अनुभव है कि नहीं कि जो वस्तु हमारे पास उपलब्ध है उसका अच्छे से अच्छा उपयोग किया जावे ।

तीसरी चीज, पूंजी है।

और चौथा है श्रम।

इन चारों बातों को अगर हम अपने प्रान्त में देखें तो चारों की चारों प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।

हमारे यहां की उर्वरा भूमि इतनी पडी हुई है कि यदि इस पर खेती का अच्छा प्रबन्ध किया जावे, इस प्यासी भूमि की प्यास बुझाने का प्रबन्ध किया जावे तो वह अनाज इस कदर पैदा कर सकती है कि

[डा० श्री मंगलसिंह]

हमारे प्रान्त की आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं हो सकेगी; बल्कि आस पास के प्रान्तों को भी हम अनाज दे सकते हैं।

इसके लिए सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सहायता से भाखरा, जवाई, चम्बल और दूसरे-दूसरे बांधों द्वारा पानी लाने का प्रयत्न किया है। इस सिलसिले में मैं अपने अनन्य और अभिन्न मित्र यादवजी की बात उठाऊंगा जिन्होंने इन बांधों के पानी के अलावा छोटे छोटे कुओं और तालावों और दूसरे साधनों, जिन्हें माइनर इरिगेशन के नाम से कहा जाता है, के द्वारा भी पानी देने के सरकार के प्रयत्नों के बारे में सदन को सुझाया है। तो इस तरह से इन जलाशयों और बांधों की सहायता से यहां की खाद्य स्थिति धीरे धीरे सुधर जाएगी। इससे हम आशा कर सकते हैं कि आगामी तीन वर्षों में हम अपनी खाद्य स्थिति पर पूर्ण रूप से काबू पा जावेंगे और साथ ही आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी।

दूसरी बात जो हमको अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने में काम लानी है वह यह है कि यहां के जितने भी खनिज पदार्थ हैं, कल कारखाने हैं, जितने भी श्रम के लिए लोग तरस रहे हैं; इन सबका अच्छे से अच्छा उपयोग करके हम अपनी आर्थिक दशा का सुधार व उन्नति कर सकते हैं।

इस प्रदेश के अन्दर नमक एक अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। हमारे यहां सांभर में जो नमक बनता है, उसी तरह से जिला भरतपुर में नमक इतनी मात्रा में तैयार किया जा सकता है और बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है कि जितना सांभर में भी नहीं बनाया जा सकता। लगभग ८० वर्ष पहले भरतपुर जिले में विशेषकर कुम्हेर तहसील में नमक इतना अधिक बनाया जाता था कि उसका उत्पादन सांभर से ड्योढ़ा था। पर उस समय केन्द्रीय सरकार की नीति यह थी कि जहां जहां नमक बनाया जाता था वहां का उत्पादन स्थल केन्द्रीय सरकार के आधीन होता था। इससे वहां का उत्पादन बन्द करना पड़ा क्योंकि नमक उत्पादन का स्थल वहां काफी फैला हुआ था; सांभर से कई गुना विस्तृत था और वह सारी जमीन उस समय के भरतपुर के महाराजा साहब केन्द्रीय सरकार को सौंपने को तैयार नहीं थे, नाही यह सम्भव था। उस समय इस बारे में काफी लिखा भी गया था। परिणाम स्वरूप नमक का वह उत्पादन बन्द कर दिया गया और इसके एवज में भरतपुर महाराजा को दो-चार लाख रुपया प्रति वर्ष दे दिया गया।

मेरा यह अनुमान है कि भरतपुर, धौलपुर और ऐसी ही दूसरी जगहों पर नमक बनाने के बड़े बड़े कारखाने खोले जा सकते हैं। इनमें सोडा एश (soda ash) और सौडियम सल्फेट आदि और दूसरे नमक अन्य कैमिकल्स भी बनाये जा सकते हैं जिसके लिये भारत को लाखों और करोडों रुपया विदेशों से मंगाने के लिए भेजना पडता है। इन कैमिकल्स का उत्पादन खेती के लिए खाद तैयार करने के काम में भी आ सकता है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह राजस्थान में ऊन के उत्पादन के बारे में है। आज हिन्दुस्तान की कुल ऊन की पैदावार का १/४ से ज्यादा और लगभग १/३ हिस्सा हमारे राजस्थान में पैदा होता है। यहां की ऊन का एक विशेषज्ञ जो आस्ट्रेलिया भेजा गया था उसने बताया कि सम्भवतः आस्ट्रेलिया को छोड़कर और दूसरी जगह इतना अच्छा ऊन और ऐसी अच्छी प्रकार की भेडे नहीं मिलतीं जैसी की हमारे राजस्थान के बीकानेर के इलाके में मौजूद हैं। इनमें से एक दो जाति की भेडों के बालों की लम्बाई १५

[डा० श्री मंगलसिंह]

इन्च तक है। और ऐसी भेडें भी मौजूद हैं जिनसे जो ऊन निकाली जाती है विश्व में ऐसी अच्छी ऊन कहीं भी नहीं मिलती है। तो मेरे कहने का यह अभिप्राय है कि अगर इस ऊन को, जिसे आजकल हम कौडियों के मोल बाहर बेचते हैं और उसी को वहां से कपडा बन कर आने के बाद सैंकडों गुना दाम देकर खरीदते हैं, हम यहीं अपने प्रदेश में साफ करके कताई करके कपडा बुनने के काम में ले लें तो हमारी आर्थिक स्थिति कितनी सुधर सकती है इसका अन्दाज हम लगा सकते हैं। इसके लिए दो चार बडे बडे पैमाने पर कारखाने हम राजस्थान में खोलें। लोगों को कार्य मिले और आर्थिक स्थिति सुधरे।

हमारे यहां इसके अतिरिक्त बहुत सी धातुएं और दूसरी चीजें इस भूमि में मौजूद हैं। मेरे एक मित्र ने मुझे उस दिन की डिबेट में यह बतलाया कि हमारे यहां पेट्रोल और सोना भी है। लेकिन यह बात तो खोज की है। फिर भी जो कुछ आज उपलब्ध है उसे भी अगर प्रयोग में लावें तो हमारा आर्थिक संकट बहुत कुछ दूर किया जा सकता है।

तीसरी चीज, इस सब काम करने के लिए, इसके उत्पादन, संकलन और विक्रय आदि के लिए हमारे पास ऐसे अनुभवी व्यापारी, अनुभवी काम करने वाले आदमी हैं या नहीं; यह देखना है। यह क्षमता हमारे लोगों में है या नहीं इस बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि इस प्रान्त के रहने वालों ने हमारे इस प्रदेश म ही नहीं, दूसरे प्रदेशों में ही नहीं, विदेश में भी यह बतला दिया है कि इस प्रदेश के रहने वाले जितने व्यापार आदि में और उसके सम्पादन में कुशल हैं उतने दूसरे नहीं हैं। विश्व में शायद यहूदियों को छोडकर (हंसी, "हीयर-हीयर" की आवाज विरोधी पक्ष की बैंचों से) हमारे मारवाडी सेठों के मुकाबले में कोई भी इस कार्य में उनसे अच्छे नहीं है।

ऐसा ही आर्थिक संकट तीन चार सौ वर्ष पहले इस प्रदेश में आया था और उस संकट से जनता घबरा गई थी, सिपाही लोग भी हतोत्साह हो चुके थे; लोग स्थान छोड कर चले गये थे और वह विश्व के महान वीर भारत के भाल राणा प्रताप का समय था। उस समय भी आर्थिक संकट के कारण हमारे प्रदेश की स्वाधीनता खतरे में पड गई थी। श्रीमन्, मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय भी यदि ऐसे बडे भारी आर्थिक संकट को दूर करने वाला कोई था तो वह इन्हीं धन-कुबेरों के पूर्वज, दानी देश भक्त भामाशाह, थे। उन्होंने ही हमारे प्रदेश के उस समय के भीषण आर्थिक संकट को दूर करके हमारी स्वाधीनता को अक्षुण रक्खा था।

क्या भामाशाह के अन्दर जो देश भक्ति और त्याग के बीज थे, आज हमारे मारवाडी व्यवसाइयों सेठों एवं जो धन-कुबेर हैं उनमें नहीं है? क्या उनमें वह खून नहीं है? क्या उनमें वह उदात्त भावना नहीं है? मुझे विश्वास और पूर्ण विश्वास है कि वह भावना अवश्य है। अगर इस आर्थिक संकट को देखकर इस ओर अपनी मातृभूमि की पुकार को सुनकर अपने संकलित धन में से शतांश भी इधर लगाने का विचार करेंगे तो हमारा आर्थिक संकट दूर हो सकता है। मेरे कहने का यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार से देश की राजनैतिक एकता के लिए हमारे राजा महाराजाओं ने त्याग किया, देश भक्ति दिखलाई और दानवीरता एवं उदारता का परिचय दिया क्या हमारे ये धनिक लोग, पूंजीपति उनका उदाहरण लेकर यह नहीं करेंगे कि वे इस प्रदेश की आर्थिक कठिनाई दूर करने के लिए अपने संचित धन का प्रयोग करें। आज उनकी मातृभूमि उन की तरफ देखरही है। उनकी मातृभूमि के निवासियों की प्यास बुझाने के लिए उनका

[डा० श्री मंगलसिंह]

कर्तव्य उन्हें पुकार रहा है। अपनी मातृभूमि उन लोगों से कहना चाहती है कि तुम्हारे ही भाईयों को इस प्रदेश में भर पेट खाने को नहीं मिलता, इनके बदन पर वस्त्र नहीं है, रहने को मकान नहीं है, और तो और, अपने बच्चों को, जो इस प्रदेश के भावी स्तम्भ बनने वाले हैं, उनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हैं। इतना ही नहीं, यहां के व्यक्ति जो बीमार पड़ने पर अपना व अपने आश्रितों की चिकित्सा नहीं करा सकते तो तुम्हारी करोडों की सम्पत्ति किस दिन काम आयेगी ? उनको सहायता देना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य हो जाता है। तुम्हारे भाई इस हालत में है और तुम उस लक्ष्मी के स्वामी बने हो और उसको गड्ढे में गाड़कर रक्खे हुए हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है।

मैं समझता हूं कि आज हिन्दुस्तान में कोई ऐसा शिक्षणालय नहीं है जिसमें किसी मारवाड़ी का कन्ट्रिव्यूशन, सहयोग या सहायता न हो, कोई चिकित्सालय नहीं होगा जिसमें हमारे मारवाड़ी धनिक का कोई भाग न हो , ऐसा कोई तीर्थस्थान नहीं जहां बड़े बड़े महल या प्रासाद, धर्मशालादि मारवाड़ी धनिकों द्वारा जनता के लिए न बने हुए हों। क्या वे धनिक लोग आज की स्थिति में यह नहीं देखेंगे कि आज उनकी मातृभूमि आर्थिक कठिनाई से गुजर रही है ? यदि ऐसा नहीं कर सकते तो उनका धन किस दिन काम आयेगा ? इसके अलावा मैं यह भी कहूंगा कि आज उनको अपने धन का सदुपयोग करने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है; इसलिए उनको अपने धन का उपयोग अच्छी तरह से करना चाहिये। मैं तो यही कहूंगा कि संभवतः यह आर्थिक संकट केवल आपको सेवा करने का सुयोग देने के लिये ही आया है।

श्रीमन्, मैं कहूंगा कि जिस वक्त भगवान रामचन्द्रजी सीताजी को लेकर बनवास को जाने के लिए तैयार हुए, लक्ष्मणजी उनको बन में जाते हुए देखकर माता से आज्ञा लेने जाते हैं तो उस समय उनकी माता ने केवल यही कहा था कि "तुमरे हेत राम बन जाई" संभव है कि धनपतियों के कल्याण के लिए, उनको मौका देने के लिए इस प्रान्त में आर्थिक कठिनाई आई हो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वे लोग अपने कर्तव्य को समझ कर इस आर्थिक संकट को मिटाने में सहायक हों।

चौथी बात मैंने जो कही थी वह है श्रम के विषय में। श्रमिक आज मांग रहा है काम। आज हमारे प्रान्त का श्रमिक (मजदूर) "त्राहि-त्राहि" कर रहा है, उसके पास शरीर है किन्तु है वह हड्डी और चमड़ी का; उसके पास काम नहीं, दाम नहीं। अगर ये सेठ लोग अपनी सम्पत्ति लगावें, अपने काम के अनुभव उपयोग करें तो यहां के श्रमिक की स्थिति भी सुधर सकती है। श्रमिक की स्थिति के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। यह आज उनकी मातृभूमि चाहती है कि तुम्हारा धन काम में लगाया जाय उसमें एक शर्त यह होगी जोकि श्रमिक और धनिक वर्ग में जो संघर्ष हो रहा है. उसको मिटाना होगा। जो पूंजी लगायी जायगी उसमें श्रमिक का, जो तुम्हारा ही भाई है, उस धन में आधा भाग मान लेना होगा। जो भी कल कारखाने खोले जायेंगे, उसके अन्दर जो धन लगाया जायगा, श्रमिक काम करेंगे, उनका, वेतन और भत्ते और बोनस के अलावा, जो मुनाफा होगा उसका आधा हिस्सा श्रमिक का होगा और आधा पूंजी लगाने वाले एवं प्रबन्ध कर्त्ताओं का। और इस प्रकार जो आधा हिस्सा श्रमिक को दिया जायगा वह उनके नाम हिस्सों (Shares) के रूप में दिया जाएगा। जब तक ५० प्रतिशत शेयर न होजाय, जब तक मुनाफे का आधा हिस्सा न हो जाय, श्रमिक के लिये देते रहना होगा। अंत में ५०, ५० प्रतिशत मुनाफा श्रमिक और पूंजी को हो जायगा। आधा मुनाफा धन कुबेरों के अनुभव, कार्य और प्रबन्ध के लिये

[डा० श्री मंगलसिंह]

आधा श्रमिकों को बांट दिया जाएगा। इस प्रकार उनकी जन्मभूमि उन पूंजीपतियों से कहती है यह एक शर्त होगी जिसके अनुसार पूंजी लगाई जायगी। इससे प्रान्त को यह लाभ होगा कि स्ट्राइक आदि जो संघर्ष चल रहे हैं वे आगे नहीं होंगे। आधी पूंजी उनकी होगी, चाहे वे छ: घंटे काम करें या ८ यह प्रश्न ही नहीं उठेगा। इस प्रकार से हमने काम किया तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति ठीक हो जायगी।

अब मैं जिस प्रश्न पर बोल रहा हूं वह है राजप्रमुख के भाषण पर उनको धन्यवाद देने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में। मैं तो यह समझता हूं कि राजप्रमुख ने जितनी भी बातें कहीं है उन बातों को सदन में बैठे हुए हरेक सदस्य ने माना है।

(आवाज "नहीं माना है")

जैसा कि राजप्रमुख महोदय ने कहा है कि आर्थिक स्थिति खराब है यह बात किसने नहीं मानी मैं तो यह समझता हूं कि सदन में बैठे हुए किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा कि हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति खराब नहीं है, अर्थात् सब ने इस बात को माना है कि आर्थिक स्थिति खराब है।

दूसरा शान्ति और व्यवस्था के बारे में यह कहा गया है कि इसमें कुछ तरक्की हुई है। मेरे दाहिनी तरफ बैठे हुए विरोधी दल के नेता ने भी यह माना है और भूरि भूरि प्रशंसा की है कि शान्ति और सुरक्षा की हालत में काफी सुधार हुआ है। जितनी तरक्की हम चाहते हैं उतनी तो नहीं हुई है, फिर भी तरक्की हुई है, इस बात को माना है।

तीसरी बात जो सदन के सदस्यों ने मानी है वह है प्रान्त की खाद्य स्थिति। खाद्य स्थिति के बारे में भी यह कहा गया है कि इसमें भी सुधार हुआ है; चाहे वह एक आना भी सुधार हुआ हो। लेकिन सुधार हुआ है, यह सदन ने माना है।

पिछड़ी हुई जातियों के लिए जो खर्च किया जा रहा है, जो प्रयत्न पिछड़ी हुई जातियों को ऊपर उठाने, के लिये सरकार कर रही है, जितना कर रही है, उससे सन्तोष तो नहीं है; फिर भी जो कुछ किया है उसको हमने माना है। अब यह प्रश्न रह जाता है कि जब हम सब लोगों ने आबू को वापस लेने के लिए सर्व सम्मति से इच्छा प्रगट की है और उसको लेने के लिए उत्सुक हैं और जिसका उल्लेख श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में किया है और सब चाहते हैं कि आबू प्रान्त हमारे प्रान्त में फिर से आवे; अगर इस बात को कोई नहीं चाहता है तो वह मुझे बतलावे।

अब ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो आप सब ने नहीं माना हो। आज राजप्रमुख ने, जो हमारे प्रान्त के पहले नागरिक हैं, ऐसी सब बातें कही हैं जिसे हम सब नें माना है। फिर हम उनको धन्वाद क्यों न दें, धन्यवाद के प्रस्ताव पर वोट क्यों न दें, यह तो हमारी भारतीय परम्परा के विपरीत है। जिस चीज को हमने मान लिया और उसका धन्यवाद न दें तो यह भारतीय सभ्यता, इस शब्द का प्रयोग तो मैं नहीं करूंगा किन्तु यह जरूर कहूंगा कि यह भारतीय परम्परा के अनुकूल नहीं है। जिस चीज को हमने स्वीकार कर लिया है उसके लिए धन्यवाद देना हमारा धार्मिक कर्तव्य है। इतना ही नहीं हमारी परम्परा तो यह है

[डा० श्री मंगलसिंह]

कि अगर कोई चीज देते हैं और हम स्वीकार नहीं भी करते तो तब भी धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य हो जाता है ।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अगर हम श्रीमन् राजप्रमुख को, उनकी बातों को मान कर भी, धन्यवाद नहीं देना चाहते तो यह तो भारतीय परम्परा के खिलाफ है। इस सदन के अन्दर जितने भी लोग बैठे हैं मुझे गर्व है कि हमारी दाहिनी तरफ जो बैठने वाले हैं उनको सदा यह भारतीय परम्परा का गर्व रहा है, वे हमेशा भारतीय परम्परा के रक्षक रहे हैं उन को तो इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। श्रीमन् राजप्रमुख ने कृपापूर्वक हमारे सामने जो भाषण दिया है और उसके लिए मेरे मित्र ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको सर्व सम्मति से बुलन्द आवाज से एक चित्त होकर पास करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है । इसलिए में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री हिम्मतसिंह–अध्यक्ष महोदय, में आरम्भ करूं इसके पहले एक बात जानना चाहता हूं कि आप मेरे को कितना समय देंगे ?

श्री अध्यक्ष–You will be wasting your time.

श्री हिम्मतसिंह–No, Sir, not at all. I will stick to the time alloted to me.

श्री अध्यक्ष–Ten minutes.

श्री हिम्मतसिंह–That is not sufficient.

श्री अध्यक्ष–Seven minutes.

श्री हिम्मतसिंह–It is still worse. यह मेरे पास जो नोट्स हैं यह वेद के मंत्र तो हैं नहीं कि में इन्हें केवल पढ़ दूं । यदि आप कहें तो पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष–You don't want to speak.

श्री हिम्मतसिंह–I want.

श्री अध्यक्ष–Speak then. Go on. If you go on wasting your time.....

श्री हिम्मतसिंह–I would not waste my time श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में तीन बातें रेज कीं, एक्टिविटीज़, एचीवमेन्ट, और पालिसी । एक्टिविटीज से शुरू करता हूं कि गवर्नमेंट की क्या एक्टिविटीज इस अर्से में, ४ महीने के अर्से में, रहीं ।

एक्टिविटीज गवर्नमेंट की रहीं, अवश्य रहीं, सबने देखीं । मिनिस्टर्स लोग, आफिसर्स, सबोर्डिनेट्स, सब एक्टिव थे । कारों में फिरे, दौडे, भागे । लेकिन किसलिए ? परिणाम उस एक्टिविटी का क्या ? ४० लाख रुपये ट्रेवलिंग ही ट्रेवलिंग में इन एक्टिविटीज में सालाना खर्च हुए और रिजल्ट रहा ज़ीरो ।

[श्री हिम्मतसिंह]

दूसरी एक्टिविटी रही पुलिस की । पुलिस भी एक्टिव रही । ३०–४० डाकू मारे । बहुत सारे गिरफ्तार किये । क्या हुआ ? कितने रुपये खर्च हुए हैं इन एक्टिविटीज के लिए ? करीब २ करोड रुपये इन एक्टिविटीज में खर्च हुए होंगे और केवल ३०–४० डाकू मारे । इससे हुआ क्या ? एक मच्छर को मारने के लिए पंसेरी से काम लिया गया । और यही नहीं, इस पुलिस फोर्स में जो आदमी लगाये गये हैं, उसमें हमारे यहां के आदमियों को भरती नहीं किया गया है, बाहर से, गढ़वाल से बुलाये गये हैं; हमारे राजस्थान का धन बाहर भेजने की कोशिश की । यही नहीं पुलिस की चेष्टा यहां तक रही कि पुलिस वालों ने खुद ने डाके डाले ।

चेष्टा एन्टीस्मगलिंग डिपार्टमेन्ट की भी रही । क्या चेष्टा रही ? उन्होंने स्मगलिंग को रोका तो नहीं, लेकिन, शायद, प्रोत्साहन ही दिया । अफीम निकल रही है और वे शिकार खेल रहे हैं, मौज कर रहे हैं । करीब करीब २–३ लाख रुपये एन्टी स्मगलिंग पर खर्च हो रहे हैं ।

एन्टी–लोकस्ट डिपार्टमेन्ट की भी एक्टिविटी रही । टिड्डियां उन्होंने नहीं भगाई, न मारी । कितना पाउडर उनको मारने में वेस्ट किया, कितना धन राजस्थान का वेस्ट हुआ, यह मिनिस्टर साहबान ही जानते होंगे; लेकिन हुआ क्या कि उस पाउडर से शायद एक भी टिड्डी नहीं मरी । टिड्डियां आई, बैठीं और उड़ गई । रिपोर्ट दे दी गई कि टिड्डियां भगा दी गई । यह फैक्ट (तथ्य) है, कल्पना नहीं ।

पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की भी एक्टिविटीज रहीं, और रहती हैं । आप सब जानते ही हैं और हम भी देखते हैं कि क्या एक्टिविटीज रहीं हैं । उसका सबसे मुख्य काम है ब्लाईंडिंग का । अभी भी ब्लाईंडिंग की एक्टिविटी पी. डब्ल्यू. डी. की रही ।

एक्टिविटीज के लिए और अर्ज करने में ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि आपने १० मिनट के लिए ही फरमाया है ।

एचीवमेंट्स के बाबत अर्ज करता हूं । लॉ एन्ड ऑर्डर का एचीवमेंट यह है कि डेक्वायट्स को भगा दिया; लेकिन उधर क्राइम (अपराध) तो बढ़ गये । यह खुद आई. जी. पी. साहब ने अपने टूर में कहीं कहीं जिक्र किया । लेकिन सबसे बड़ी बात लॉ एन्ड ऑर्डर को रेग्युलर होने की थी । खाली क्राइम रोकने का ही काम नहीं है, लेकिन साथ ही साथ बड़ी भारी खराबियां इसमें हो रहीं हैं । पब्लिक का धन जितना कि डेक्वाइटीज और थेफ्ट्स (चोरियों) में नहीं जा रहा है उतना और जरिये से जा रहा है । वह जिन जरियों से जा रहा है यह मैं बतलाता हूं । मनी लेन्डर्स (महाजन), गवर्नमेंट सरवेन्ट्स, और ऐसे कई कार्यों में करोडों रुपये पब्लिक के इस तरह से, वेस्ट चले जा रहे हैं । यह भी एक एक्टिविटी है । पब्लिक को चूसा जा रहा है, यह एक एचीवमेण्ट है ।

एचीवमेण्ट फूड सिचुएशन के बाबत भी रही । मेरा ऐसा ख्याल है, पहले सेशन में यह बतलाया गया था कि फूडसिचुएशन हमारी अच्छी है, लेकिन अब फुड सिचुएशन ऐसी बतलाई जाती है कि अच्छी नहीं है । और फुड सिचुएशन अच्छी होगी या नहीं, यह किसी के बस की बात नहीं है । यह बरसात पर डिपेन्ड करता है । अगर नहरें हो तो शायद फुड सिचुएशन ठीक हो सकती है; लेकिन फुड सिचुएशन में भी कोई सुरारनहीं है । फुड सिचिएशन की एक्ठिविटीज में मोनोपोली प्रोक्योरमेंट की भी एक

[श्री हिम्मतसिंह]

एक्टीविटी है । मोनोपोली प्रोक्योरमेंट से काश्तकारों को किस कदर हानि हो रही है; यह भी गवर्नमेंट के विचार और ध्यान में होगा ।

एचीवमेन्ट में यह भी बतलाया गया है कि चम्बल हाइडल वर्क्स को भी फाइव इयर प्लान में इन्क्ल्यूड कर लिया गया है । यह भी एक गवर्नमेन्ट की एक्टिविटी है ।

और एचीवमेन्ट यह भी बतलाया गया है कि इतने बिल तो पास कर दिये गये हैं और इतने बिल और पास होने वाले हैं । यह भी एक एचीवमेन्ट है । लेजिस्लेशन खाली पास कर देने से तो कार्य नहीं चलेगा । जितने लेजिस्लेशन ज्यादा होंगे उतना करप्शन बढ़ता है । वह देश ज्यादा अच्छा है जहां लेजिस्लेशन कम है; और उन पर अमल होता हो । लीस्ट गवर्न्ड (Least Governed) जितना भी देश हो वह बैटर (better) गवर्न्ड है ।

अब पॉलिसी के लिए मैं अर्ज करता हूं कि पॉलिसी गवर्नमेन्ट की क्या रही है । पॉलिसी के लिए मैं कहूंगा कि राजस्थान गवर्नमेन्ट की क्या पॉलिसी हो सकती है ? यह तो एक "बी" स्टेट है, जो कि श्री प्रेसीडेन्ट साहब के ही आधीन है, और जो पॉलीसी वहां की हो सकती है वही यहां की भी पॉलिसी हो सकती है । हम तो अभी तक माइनर सब्जेक्ट ही हैं ।

पॉलिसी यह बतलाई गई है कि जो डेजर्ट राजस्थान में बढ़ता चला आ रहा है उसको भी रोकने की पालिसी है । यह भी एक सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की पॉलिसी है, राजस्थान गवर्नमेन्ट की पॉलसी नहीं है । जहां तक मेरा खयाल है खर्चा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट करेगी क्योंकि राजस्थान गवर्नमेन्ट के बस के बाहर की चीज है ।

मेडिकल डिपार्टमेन्ट के एचीवमेन्ट के लिए मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में फरमाया है कि महाराव साहब कोटा ने अस्पताल के लिए जो रकम दी है उसका कन्स्ट्रक्शन जारी है । मैं हाउस को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वहां एक पत्थर भी नहीं रखा गया है, एक इन्च जमीन भी नहीं खोदी गई है । समझ में नहीं आता है कि श्रीमन् राजप्रमुख ने कैसे यह फरमा दिया है कि कन्स्ट्रक्शन जारी है ।

श्री जसवन्तसिंह—उन्होंने कहा कि नक्शा जारी है ।

श्री हिम्मतसिंह—अगर नक्शे से ही कन्स्ट्रक्शन समझ लिया जाय तो समझ लीजिये ।

(विराम)

मेडिकल डिपार्टमेन्ट के एचीवमेन्ट के लिये मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां डाक्टर हैं वहां पर दवाइयें नहीं और जहां दवाइयें उपलब्ध् हैं वहां पर डाक्टर नहीं । यह मेडिकल विभाग का हाल है । आयुर्वेदिक या युनानी औषधालयों के लिये श्रीमन् राजप्रमुख ने कोई जिक्र अपने भाषण में नहीं किया है । इनका भी कुछ करेंगे या नहीं । मौजूदा समय में जो आयुर्वेदिक औषधालय हैं उनकी यह दशा है कि राजस्थान सरकार ने उनको जो रकम देने का वायदा किया था वह भी उनको रकम अभी तक नहीं मिली है । अभी तक वे लोग अपने कार्यालय अपने पैसों से चला रहे हैं और जो मदद उनको सरकार से मिलनी चाहिये,

Page No.42

[श्री हिम्मतसिंह]

नहीं मिली है। मेडिकल विभाग के यह भी एचीवमेन्ट हैं कि टी.बी. के टिक्ट बहुत जोरों से बेचे जाते हैं और जब तक प्रेस्क्रिप्शन पर टी.बी. का टिकट नहीं लगाया जाता उसको दवा नहीं दी जाती है।

शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि प्राइमरी शिक्षा, जिसका जिक्र हमारे विधान में किया गया है कि यह कुछ ही समय में देश व्यापी हो जावेगी, मगर मौजूदा शिक्षा को देखने से मालूम होता है कि जो शिक्षा हमारे देश में पहले थी वह भी चली गई है। धन-दौलत से तो जनता महरूम हो ही रही है किन्तु इसके साथ साथ शिक्षा से भी महरूम हो रही है। गये साल सोशियल वीक शिक्षा विभाग की तरफ से मनाया गया। उसमें लडकों और मास्टरों ने भाग ले कर कितना पैसा इकट्ठा किया और उसका क्या हुआ, यह सब जानते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं उन सब बातों को आपके सामने रख सकूं। शिक्षा विभाग ने नाइट स्कूल्स भी खोले हैं और वहां भी लड़के पढ़ते; मगर वहां पर बी.ए. के लडकों को पढाने के लिये आपको मास्टर इन्टर पास मिलेंगे।

इसके बाद में कोम्युनिटी प्रोजेक्ट के बारे में अर्ज करूंगा। आपने कोटा में जो स्कीम खोली उसकी आज क्या व्यवस्था है; वहां पर क्या कार्य हो रहा है। वहां पर जाकर किसी ने देखने की कोशिश नहीं की। मैं कहना तो नहीं चाहता था..........

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—कह दीजिये।

श्री हिम्मतसिंह—अच्छी बात नहीं है, इस लिये नहीं कहूंगा। लोग बागों का क्या खयाल है, यदि मैं कहूंगा, तो बहुत भद्दा लगेगा।

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसा खयाल है तो छोड़ दीजिये।

श्री हिम्मतसिंह—कोम्युनिटी प्रोजेक्ट ऐसी जगह पर खोले जा रहे हैं; जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा ऐसी जगह जहां पर भील रहते हैं और वह भी पहाड़ों में जहां पर कि ये लोग बहुत दूर दूर पर रहते हैं।

(श्री अध्यक्ष ने समय समाप्ति की सूचना दी)

श्री हिम्मतसिंह—मैं सिर्फ पोइन्टस् ही पोइन्टस पर बोल रहा हूं। मैं यह अर्ज करूंगा कि आपोजिशन को अधिकार है कि वह राजप्रमुख के स्पीच पर बोले। हमारा हक है, ट्रेजरी बेंचेज़ का नहीं। आपको हमें सुनना चाहिये।

श्री टीकाराराम पालीवाल—हमें तो सुनने में कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—I have got a list before me in which I can say that the time occupied by the Opposition side is greater and the Hon'ble Members should know that they will have on opportunity to criticise the Government at the time when the demands for grant come.

श्री हिम्मतसिंह—I am not criticising the Government, but I am only speaking on the speech of His Highness the Rajpramukh and am not going beyond it.

(श्री अध्यक्ष ने घंटी बजाई)

श्री हिम्मतसिंह—This is the freedom of speech ? May I sit down, Sir ?

श्री अध्यक्ष—Yes.

(विराम)

श्री खेतसिंह—में तो अपनी पार्टी का एक ही आदमी हूं मुझे भी बोलने का अवसर मिलना चाहिये ।

श्री हरिदत्त—माननीय अध्यक्ष, इस सदन में श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण पर दोनों पक्ष की ओर से काफी वाद विवाद हो चुका है। राजकीय पक्ष की ओर से भी कई सदस्यों ने इस अभिभाषण पर दिलचस्पी ली है। इससे यह प्रकट हो जाता है कि इस समय जो हमारे राजप्रमुख का भाषण हुआ उस पर विरोधी पक्ष के सदस्यों को अपने अपने विचार, भाषण में जो जो त्रुटियें रहीं है, उन पर रखना आवश्यक है । राजप्रमुख का भाषण प्रत्येक सत्र के आदि में जब दूसरा सत्र शुरू होता है तो हुआ करता है जिसमें राज्य संचालन में जो जो कार्य होते हैं उनका उल्लेख किया जाता है। राज्य संचालन में अवश्य त्रुटियें हुआ करतीं हैं । उन त्रुटियों को जब हमारा अधिवेशन शुरू हो उस समय उनके सामने रखनी चाहिये ताकि जो जो सदस्य दूर दूर से आकर यहां पर इकट्ठे होजाते हैं वे अपने विचार प्रकट करके भविष्य के लिए कुछ सुझाव भी दे सकें। ऐसी त्रुटियों को बतलाने के सम्बन्ध में हमारे माननीय अध्यक्ष ने कई दफा इस बात का संकेत किया कि सदस्यगण महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार प्रकट करें। यह ठीक है और ऐसा ही करना चाहिये। फिर भी बहुत से सदस्य अपने अपने क्षत्रों से आते हैं, उन घटनाओं के सम्बन्ध में, हालाँकि जिनका महत्व कम हो, लेकिन फिर भी उन पर यह विचार करके राज्यसंचालन पर आक्षेप कर सकते हैं। उसके करने में, कभी वे लोग आवेश में आकर, दुखित हृदय हो अपने भावों को प्रकट करने में ऐसी बातें कह देते हैं जिसे हम कह देते हैं कि ये बातें मर्यादा में नहीं है और उनको खास संकेतों द्वारा रोका भी जाता है। पर में अपने राजकीय पक्ष के सदस्यों से नम्र निवेदन करूंगा कि कुछ कटुता के साथ आ जाने पर वे बातें ज्यादा कारगर हो जातीं हैं। आप ऐसी कटुता, जो हमारी तरफ से हो, उसको हमारे लिये छोड दें और सत्य को आप ग्रहण करें।

इससे हमारे राज्य-संचालन में सुधार होगा और हम सब प्रेम के साथ अग्रसर हो सकेंगे।

विरोधी पक्ष का कर्तव्य है कि वह शासन की जो भी खराबियां हों उनको ट्रेजेरी के सामने रखें। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो में कहूंगा कि वह अपने कर्तव्य पथ से च्युत होता है। शासन की खराबियों

[श्री हरिदत्त]

को आपके सामने रखने का जो हमारा कर्तव्य है उसके प्रति मेरी यह मान्यता है कि ऐसा करके हम आपको सहयोग देते हैं । यह एक ऐसा सहयोग है कि जिसके लिये हम यहां एकत्रित होते हैं, यह एक सक्रिय सहयोग है ।

मैं यह कहूंगा कि राजपक्ष की यह भूल होगी यदि वह विरोधी पक्ष द्वारा उनकी त्रुटियों का उल्लेख करने पर बुरा मानें; यह तो एक फूलों की मार है । उनको यह देखना चाहिये कि विरोधी पक्ष जो त्रुटियों का उल्लेख करता है उसके लिये वह मैदान में आयें और विरोधी पक्ष जो नुकीली भालों की आजमायश उन पर करता है वह भाले उनकी सत्य रूपी ढाल पर टकरा कर खाक हो जायं । ऐसा होने पर ही उनका साहस बढेगा और दर्शकगण भी ऐसा देख कर उनकी वाह वाह करेंगे । इसी से राजस्थान की मर्यादा बढेगी, मेरा यही कहना है ।

मेरे पूर्व पूर्व वक्ताओं ने जो भाषण दिये हैं उनकी बातों की ओर ध्यान दिलाते हुए मैं प्रार्थना करता हूं कि राजप्रमुख के अभिभाषण पर जो वाद विवाद हुआ है उसमें बहुत से सुझाव भी रखे गये हैं परन्तु मैं यह निवेदन करूंगा कि उस अभिभाषण से ही राज्य शासन का सारा हाल मालूम हो जाता है । इसके लिये मैं एक मिसाल पेश करूंगा :

एक रोगी जो राजयक्ष्मा से पीडित होकर मृत्यु शय्या पर पड़ा हुआ मृत्यु की बाट जोह रहा है, उसकी सेवा करने वाले जो सेवक हैं वह बाहर की दिखावट के रूप में अच्छी सफाई रख रहे हैं । उनका हित रोगी में नहीं है बल्कि अपने अन्दर होता है । सुबह के वक्त जब डाक्टर आता है और रोगी की निस्बत वह सेवकों से पूछता है कि रात को रोगी को नींद आई कि नहीं और रोगी ने दूध पिया कि नहीं; तो उसका प्रमुख सेवक कहता है कि रोगी रात भर खूब अच्छी तरह सोया और उसने दूध भी पिया । यह बात सुनकर वह रोगी जिसको अपनी हालत खराब होती दिखती है वह धीमी आवाज में कह उठता है कि डाक्टर साहब ने मुझे रात भर नींद आई और न मुझे दूध ही पिलाया गया है । इस पर प्रमुख सेवक दूसरे सेवक की तरफ देखता है । वह तुरन्त जवाब देदेता है कि तुम्हें रातको नींद में होश ही नहीं रहा ; तुम्हें दूध मैंने पिलाया था । तीसरा सेवक कहता है कि सुबह मैंने आपका मुंह धोया तब आपकी मूंछों पर मलाई तक थी । डाक्टर सब बात समझ तो जाता है । प्रमुख सेवक डाक्टर से कहता है कि वह खर्चा जिसपर हम सेवा कर रहे हैं वह तो खत्म हो गया है, पर वह चला जाता है आप जायं तो बडे डाक्टर साहब से कहकर कुछ और खर्चा भेजें ।

यही बात मैं समझता हूं माननीय राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में चित्र के रूप में रखी है । उन्होंने कह दिया कि आर्थिक संकट से हमारा राजस्थान ग्रसित है पर उन्होंने यह नहीं बताया कि यह आर्थिक संकट क्यों आया और किस तरह मिटाया जा सकता है । पिछले साल जब बजट की तैयारी हो रही थी तो इस पक्ष की ओर से बार बार दोहराया गया था कि यह एक ऐसे ढोल की शक्ल में रखा जा रहा है जो अन्दर से बिल्कुल खोखला है, आज वह फूट भी गया है । समय आया और समय ने बतला दिया कि ढोल फूट गया है । अब उसी फूटे हुए ढोल को श्री राजप्रमुख अपने अभिभाषण में बतलाते हुए यह कह रहे हैं कि यह ढोल अब भी बज रहा है । हमें इसपर गंभीरता पूर्वक देखना है । यह मेरा कटाक्ष

[श्री हरिदत्त]

जैसा आप पर है वैसा हम पर भी है। हम लोग भी इस आर्थिक संकट को देखते हुए माहवारी तनख्वाह लेते हैं, हमें सबको सहृदय होकर आर्थिक संकट को सुधारने का प्रयास करना है ।

एक समय था, यह प्रणाली जिस पर आप चल रहे हैं अंग्रेजों द्वाराप्रतिपादित हुई थी। अंग्रेज विदेशी थे और हम देशवासियों पर कम विश्वास करते थे; इसलिये खुली शकल में अपनी कार्य-प्रणाली को एसेम्बली में नहीं रखते थे । पर अब वह बात नहीं रही । हम सब एक ही देश के निवासी हैं, खुली शक्ल में सब बात यहां रखी जानी चाहिये। यदि घर की हालत घर के भाइयों के सामने नहीं रखी जायगी तो हो सकता है कि जब घोर संकट आ जाय तो आप यह कह कर दूर हो जायं कि क्या करें, मजबूरी की हालत है, हम यह कहदें कि हम पहले ही कहते थे। पर इस से जनता का कोई हित नहीं होगा । यह उत्तरदायित्व तो सारे सदन पर अवश्य बना रहेगा।

मैं दुख के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में आर्थिक संकट की बात कहकर गोल-मोल शक्ल में अपने शासन को अच्छा बतलाते हुए कहा जिसके लिये हम कह सकते हैं कि हमें असली हालत नहीं बतलाई गई, धोखा देने का प्रयास किया गया ।

ऐसी दशा में हमको प्रस्ताव द्वारा यह कहा जाना कि श्रीमन् राजप्रमुख के लिये हमें कृतज्ञ होना चाहिये , यह सभ्यता और शोभा से कतई दूर है ।

यह जो आर्थिक संकट आया है, यह एक घोर संकट है । डाक्टर मंगलसिंह जी ने इसके वास्ते बहुत सुझाव रखे हैं; उससे स्पष्ट हो जाता है कि संकट विकट है ।

यह संकट क्यों आया और कैसे दूर हो सकता है, यह कहीं भी राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में नहीं बतलाया, आमदनी कम होने के विषय में भी राजप्रमुख ने नहीं कहा । तो इससे यही मालूम होता है कि खर्चा बेजा तरीके से हुआ है, जिस पर मेरे मित्रों ने प्रकाश डाला है । मैं इस पर आपको यह बताऊं कि घरमें हमने जो खर्चा किया वह तब तक मालूम नहीं हो सकता जब तक कि घर के बजट और महकमों के खर्च को ठीक तौर से देखा न जाय ।

हमारे राजस्थान में खर्चा किस तरह से किया गया है यह सडकों के दोनों तरफ देखने से पता चलेगा । सडकों के दोनों तरफ सड़क के एक एक पत्थर को, दरख्त को तथा पोल्स को रंगा गया है। हो सकता है कि कुछ अतिशयोक्ति हो पर वास्तविकता तो यह है कि सफेद और पीली पट्टियों से सडकों के दोनों ओर पत्थर और दरख्तों को रंग दिया गया है ।

क्या इस कारण उन्होंने पेडों को रंगा कि जब उनकी मोटर रात में पास हो तो उसकी रोशनी म ये चमकते रहें और उनको रास्ता दिखाते रहें और उनको सड़क नजर आती रहे। क्या अजीब बात है ? मोटर की खुद की रोशनी से उनको सडक नजर नहीं आती है। लाखों रुपये उन्होंने इस तरह बरबाद कर डाले । जहां मोड होती थी वहां इस तरह का प्रयोग पहले किया जाता था लेकिन यह नहीं कि किसानों के पसीने के पैसे को बेदर्दी के साथ इस तरह फिजूल बहा दें। यह आप राजस्थान के किसी भी कोने में जाकर हर एक सडक पर देख सकते हैं। इसलिये मेरा आक्षेप है कि यदि हमारे रुपये ठीक तरह से

[हरिदत्त]

इस्तेमाल नहीं किये गये हैं बेजा खर्च किये गये हैं तो उसका उत्तरदायित्व आप पर है। आप इस बात को इस भावना से न ल कि विरोधी पक्ष वाले ऐसा कहा ही करते हैं। मैं कहूंगा कि आप असलियत को पहिचानें।

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

अभी आपके कोष में धन नहीं होता तो आप राजकर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकते थे। अभी कुछ दिन पहले अखबारों में यह सनसनीखेज खबर चारों तरफ फैली थी कि कोष में रुपया नहीं है। दौड़ धूप करके तत्काल कुछ प्रबन्ध किया गया था। जब कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन एफिशियेन्टली कैसे चल सकता है ? पेन्शन वालों को बराबर पेन्शन नहीं मिल रही है, इसकी अबतक शिकायत है। हमारा आर्थिक संकट एडमिनिस्ट्रेशन को खराब करता है। आप बाजार में जाइये, दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है; मिलों में जाइये मिलें बन्द पड़ी हैं। इसी सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि २२ मिलें बन्द पड़ी हैं। मैं जानता हूं भरतपुर में तीन मिलें हैं जो काफी दिनों से बन्द पड़ी हैं। मजदूर बेकार बैठे हैं। इसी तरह पढे लिखे नवयुवक बेकार बैठे हैं। ये अपनी शिकायतें लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। अभी अखबार में निकला था कि राजस्थान में ७० हजार पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। यह कितने दुर्भाग्य की बात है, यह आर्थिक संकट का नतीजा है।

कहा जाता है, जैसा कि अभिभाषण में कहा है, कि राजस्थान में रेगिस्तान को रोकने का बहुत कुछ उद्योग किया जा रहा है। यह एक ऐसी चीज है जिससे हर एक को खुशी होगी; पर यहां तो घर घर में बरोजगारी का रेगिस्थान हो रहा है, इसे आपको निकालना है।

इस भाषण में कोटा महाराजा साहब की तारीफ की गई है, जिन्होंने कृपा करके एक अस्पताल को दान दिया है। लेकिन हमारे संबन्धित मन्त्री महोदय ने इस सदन में कहा है कि बहुत से अस्पताल राजस्थान में ऐसे हैं जिनमें डाक्टर नहीं हैं और डाक्टर हैं तो दवाइयां नहीं हैं। असली हालत हमें इससे मालूम होती है न कि दान देने से। कुछ मारवाड़ी सेठों को कहकर, उनसे दान लेकर अस्पताल चलाने से कोई वास्तविक हल नहीं निकलता।

बंध और सड़कें बनवाना आवश्यक है; लेकिन जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा आपके लिये यह काम पर्याप्त नहीं होगा। आपको नेशन बिल्डिंग फीलिंग्ज क्रिएट (create) करनी है। जब तक यह क्रिएट नहीं होंगी तब तक हमारी प्रगति नहीं होगी। ये फीलिंग्ज क्रिएट होने पर ही शासन सुधरेगा और देश का हित होगा। मुझे याद है कि मेरे एक कांग्रेसी मित्र ने कहा था कि आज कल के जमाने में वकीलों का आधिपत्य है। पर मैं देखता हूं कि इसी सदन में और इसी अधिवेशन में इतने विधेयक पेश हो रहे हैं कि समझ में नहीं आता कि उनकी क्या जरूरत है। प्रत्येक छोटी मोटी बात के लिये एक विधेयक निकल जाता है। जनता नहीं समझ पाती कि इन विधेयकों से किस समय उन्हें जकड़ लिया जाय। ऐसे कई कानून है जो आपके सामने इस अधिवेशन में आ रहे हैं; जैसे एग्रीकल्चर इन्कम टेक्स बिल, हेबिच्युअल औफेन्डर्स बिल आदि। हेबिच्युअल औफेन्डर्स बिल हमारे लिये क्या अभिशाप नहीं साबित हो जायगा ? क्या इससे

[श्री हरिदत्त]

पुलिस को खुली छूट नहीं मिल जायगी ? किसी को रात दिन परेशान कर सके ऐसे बिल की कोई आवश्यकता नहीं है । में यह कहूंगा कि विधान में जो हमको राहत दी गई है, स्वतंत्रता दी गई उसको आप इन विधेयकों द्वारा वापिस छीन रहे हैं और इसके लिये आपको पुलिस और मिलिटरी की आवश्यकता पड़ गई है ! अभी तीन चार दिन पहले किशनगढ़ मिल के मजदूरों को पुलिस द्वारा घेरा गया और उन पर लाठी चार्ज किया गया । जब उनकी आवाज इस सदन तक आने लगी तो स्वयं सेक्रेटरी साहब उठ कर दरवाजा बन्द करते हैं ताकि उनकी आवाज हम सुन नहीं पावें; यह बात उचित नहीं है। यदि मजदूर खुश नहीं हैं तो आप पर और भी संकट आ सकता है। आपको अपनी जनता के साथ प्रेम लेकर चलना है। आप अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्हीं की तरह अत्याचारी न बन जांय । हो सकता है कि कभी सयम आ जाय तो आपको भी बाहर निकलना पड़े । अंग्रेज तो अपने सगे संबंधियों के पास चले गये किन्तु आपको तो यहीं हमारे बीच रहना है। इसलिए आपको ऐसा शासन चलाना है जो प्रेम पर आश्रित हो और जिससे जनता खुश हो सके ।

अब में यह कहूंगा कि जो सुझाव कंस्ट्रक्टिव फार्म में आपके सामने रखे जा चुके हैं वे महत्वपूर्ण हैं। मैं सिर्फ एक ही सुझाव आपके सामने रखता हूं, वह है आर्थिक संकट । आप चाहें एक ही पार्टी के नाम पर शासन रखियेगा, हमें इससे आपत्ति नहीं है ; लेकिन कम से कम फाइनेन्स तो आप विरोधी पक्ष को दे दें। इसको देने में फिजूल खर्ची कम हो जायगी और जनता को विश्वास हो जायगा कि हमारे अर्थ का काम दोनों पक्ष मिलकर कर रहे हैं । इस प्रकार उनको संकट से बचाना होगा । इन बातों पर प्रकाश डालता हुआ, क्योंकि अब समय कम है, मैं यह कहूंगा कि जो प्रस्ताव अभिभाषण के प्रति कृतज्ञता प्रगट करने का है, उस पर मेरे माननीय मित्र यादवजी ने जो एमेन्डमेन्ट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हुआ यह प्रार्थना करता हूं कि कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ है, इस अवधि में कि जिसके लिए हम श्रीमन् राजप्रमुख के प्रति कृतज्ञता प्रगट करें ।

श्री बी. एन. जोशी–Mr. Speaker, Sir, I rise this afternoon to state my views about the past achievements and the future policy of the Government as contained in His Highness the Rajpramukh's Address. One thing for which I wish to thank the Government is the bravity of the Address as compared to any of the Addresses delivered on the last two occasions.

The first place which has been rightly given in the Address is to the present financial crisis in the State. But I cannot help feeling and expressing that the very intricate problem of finance has been implified in the Address. But we have not come across the circumstances and reasons which have led to this crisis. We find that such a thing is totally omitted from the Address. I feel that the House is entitled to know the reasons and causes which have led to the present state of affairs and the ways and means which the Government propose to adopt for the amelioration of the present condition. But the question of finances of the State is not so

Page No.48

[श्री बी. एन. जोशी]

small. In this connection I would wish to give a number of suggestions and also state the reasons which, in my opinion, are responsible for the present regretable state of the State's finances.

In the very first instance I would like to stress the slackness of the administration machinery in the matter of realisation. I do not think there is any single Tehsil in Rajasthan from which quite a few lacs of rupees of State revenues have not been realised. Little is being done to effect necessary realisation of State dues. The result is that those who pay State taxes regularly and in time feel that they are the only persons who are unnecessarily spending their money and those who are not paying State dues are enjoying all the benefits and in no way they are being forced by the machinery of the State. I also feel that the interests of the State revenues are not being properly safeguarded. Big pieces of land, earmarked for improvement which can fetch good prices are allowed to be forcibly taken possession of and no steps are taken to get them back inspite of repeated reminders and requests.

Then we are also aware of a number of instances in which persons have been imported from outside and where they have been paid exceptionally fat and large salaries. In this connection we can cite the exemple of the Chief Conservator of Forests who is paid three times the salary of a Minister, although suitable persons within the State, who can work in his place and who can work only on one third of the salary that he draws, are available.

At the same time, one of the reasons which have accentuated the expenditure of the State is the number of very frequent transfers inside the State. I have come to know that there are several cases in which one officer had been transferred three times in a month. There are cases in which during the last three to six months, the same officer has been transferred five or six times. Now transfers from one place to another in the province involve a lot of expenditure by way of T. A. and D. A. etc. It is this factor which has been responsible to large extent in raising the expenditure of the administration. There are other sources of revenue also which can yield large revenues, but they are either not touched at all or only partially touched. There is a lake of economy in every direction and adequate attention is not paid to it. If proper economy is effected a great deal of expenditure can be saved. In this connection I would cite the example of railways and the method which they have adopted in this regard. The State Government

[श्री बी. एन. जोशी]

have also appointed some experienced officer as job-analyser with a view to go into the administration of this Department and to see whether the present strength of the Department is in excess of the required strength and if it is so, then a great deal of economy can be effected.

(Interruption by Chair).

Sir, I have taken only five minutes while there are speakers who were allowed 15 to 20 minutes.

श्री उपाध्यक्ष–Two minutes more.

श्री बी. एन. जोशी–As a protest against this I discontinue my speech because I have a number of things to say and I am sorry that I shall not do justice to my subject if I am asked to speak only for two minutes.

श्री भोपालसिंह (वि० सं० २०)–अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख ने हमारा जो स्वागत किया है उसके लिए तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। श्रीमन् राजप्रमुख महोदय ने अपने अभिभाषण में सबसे पहले आर्थिक स्थिति चिन्ताजनक है, उसके बारे में फरमाया है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब राजस्थान बना या उस समय १८ और १९ करोड रुपया दिया गया था और सालाना आमदनी होती ही थी तो वैसी हालत में हमारी आर्थिक स्थिति चिन्ताजनक क्यों बन गई है ? इसके लिए तो यह कहा जा सकता है कि चाहे करोडों और अरबों रुपये दे दिये जायं, फिर भी खर्चा समझदारी से नहीं किया जाय तो हमारी आर्थिक स्थिति तो चिन्ताजनक ही बनी रहेगी । इसका तो कोई उपाय ही नहीं है । यदि सरकार की आमदनी कम होती है तो हमारे यहां कई सेठ साहूकार और उनके जरिये हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ हो सकती है और जो सुदृढ बनाने में कई व्यवसाय, धन्धे हमारी सरकार को बता सकते हैं और कोशिश भी कर सकते हैं; लेकिन जितना भी रुपया दिया जायगा और वह वैसे ही खर्च कर दिया जायगा, तो आर्थिक स्थिति चिन्ताजनक ही रहेगी । जिन अर्थ मंत्री का काम हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति को सुदृढ बनानें का है वे मेड़ता की तरफ दौरे में आये थे और उस वक्त उन्होंने तमाम तहसीलों का दौरा किया था ; किन्तु कोई सरकारी कार्य नहीं किया गया, सिर्फ चुनाव का धन्यवाद प्राप्त किया है; खुद के, कलेक्टर, एस. डी. ओ., तहसीलदार आदि के टी. ए. बिल बने हैं। कितना सरकारी रुपया खर्चा हुआ है, आप ही अनुमान कर सकते हैं । मेड़ता के अन्दर अर्थ मंत्रीजी की खुद की बनाई हुई किसान बोर्डिंग है। उसको उसकी नई इमारत होते हुए भी २५,०००) (पच्चीस हजार) रुपया दिया गया है। इस प्रकार यह जान कर कि मंत्री-पद कौन सा बार बार आता है मनमाने ढंग से रुपया देने से तो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती ।

एक सदस्य–अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे भूतपूर्व अर्थ मंत्री हैं या मौजूदा अर्थ मंत्री ?

श्री भोपालसिंह–वे भूतपूव अर्थ मंत्री ही हैं ।

Page No.50

[श्री भोपालसिंह]

अब में आपको पंचायतों का जो चुनाव हो रहा है उस बारे में एक दो शब्द कहना चाहता हूं। चुनाव जो हो रहे हैं वे इस ढंग से हो रहे हैं कि बस भ्रष्टाचार का बोलबाला है। चुनाव के वक्त रिजल्ट नहीं सुनाया जाता है। इन्सपेक्टर की जेब में रुपया गया कि चाहे सरपन्च लिखा पढ़ा ही क्यों न हो वह सरपन्च और उप-सरपन्च दर्ज कर लिया जाता है। इसकी मिसाल में मेड़ता तहसील के रीयां बड़ी ग्राम की दे सकता हूं। वहां सरपन्च और उप-सरपन्च बिलकुल लिखे-पढ़े नहीं हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं। कोई देखने वाला नहीं है। अतः किस बात के लिए सरकार को धन्यवाद दिया जाय। इतना ही कह कर में अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—माननीय अध्यक्षजी, श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण पर हुई बहस में माननीय सदस्यों ने जो रचनात्मक सुझाव दिये हैं उनके लिये तो मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं किन्तु इस बहस में कुछ मुझसे संबंध रखने वाली मिथ्या बातें कही गई हैं उनको संक्षेप में स्पष्ट करना आवश्यक है; अतः मैं उनका स्पष्टीकरण करता हूं।

मेरे एक माननीय मित्र ने खाद्यस्थिति पर सन्तोष प्रकट करते हुए, पिछली बार तो यह कहा था कि डूंगरपुर-बांसवाड़ा में चने का एक दाना भी नहीं बोया जाता फिर भी वहां पर चने का बीज भेजा गया। में माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उनके गांव में या जहां वे रहते हैं उसके पास में जितना चना पैदा होता है उससे कई गुना चना बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में बोया जाता है और पैदा होता है। यदि वे चाहें तो आज भी जाकर देख सकते हैं।

दूसरी बात उन्होंने यह बताई कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा में बीज का चना सड़ रहा है। मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि वे जाकर देखें कि वहां कोई चना नहीं सड़ रहा है। यह जो बात कही गई है बिलकुल मिथ्या है, झूंठ है।

साथ ही एक माननीय मित्र ने बताया कि चम्बल प्रोजेक्ट पर ३८ लाख रुपया जो खर्च हुआ है उसमें से ८ लाख रुपया भी वास्तव में खर्च नहीं हुआ है। माननीय सदस्य ने यह तो नहीं बताया कि उसमें क्या क्या गडबडियां हुई हैं, वर्ना मैं इसकी जांच करता और फिर ठीक उत्तर देता; किन्तु यह तो एक साधारण आदमी भी समझ सकता है कि वहां बीसियों मील लम्बी सडकें बनी हों, मकान बने हों, योजनाएं और उनके अनुसार काम हुआ हो, वहां पर यह कहना कहां तक ठीक है। आपने यह भी कहा कि आठ लाख भी इस काम पर खर्च नहीं हुआ, तो क्या मैं इससे यह समझूं कि एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि जब भी कोई बात इस सदन में कही जावे तो तथ्यों व आंकड़ों सहित बताई जानी चाहिये। उन्होंने तो इसके लिये चेलेन्ज तक दिया है। मैं तो इसके लिए हमेशा ही तैयार हूं; थोडी बहुत भी अगर उन्हें गडबडी मालुम हुई हो या हो तो वे अवश्य बताएं; उसकी अवश्य जांच होगी और इस कार्य में आपका जो सहयोग होगा उसके लिए मैं आपका आभारी होऊंगा।

श्री दिलीपसिंह—क्या जांच करेंगे आप?

श्री भोगीलाल पंड्या–जब-जब भी जो-जो भी आप बताएंगे उसकी बराबर जांच होगी । पर जब तक आप कोई बात नहीं बताएं तब तक मैं किस बात की जांच कराऊं; यह मेरी समझ में नहीं आया क्या आठ लाख रुपये भी खर्च नहीं हुए; क्या इन शब्दों की जांच कराऊं ? इन शब्दों की इन्क्वायरी तो नहीं हो सकती ।

श्री दिलीपसिंह–मुझे तो इस बात का आश्चर्य होता है कि.........

श्री अध्यक्ष–ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री भोगीलाल पंड्या–दूसरी बात मेरे एक माननीय मित्र ने कही कि लेवी जो व्यापारियों से ली गई उससे किसानों को नुकसान हुआ । मुझे इससे बडा आश्चर्य हुआ कि इससे किसानों को क्या नुकसान हुआ ? इससे तो, मुझे ही क्या, हरेक को आश्चर्य होना चाहिये । मैं इसके उत्तर में इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि इससे किसी किसान को कोई नुकसान नहीं हुआ ।

साथ में एक बात यह भी बतलाई गई थी कि माइनर ईरिगेशन की अधिक आवश्यकता ह । इससे मैं भी सहमत हूं । इस समय मेजर ईरिगेशन का भी काम चल रहा है, मीडियम ईरिगेशन का काम भी चल रहा है और माइनर का भी चल रहा है। भारत सरकार ने १।।। करोड रुपया अगले तीन वर्षों के लिए दिया है और इसके लिए योजनाएं बना कर साथियों एवं सम्बन्धित व अन्य अन्य विभागों के पास वे भेज रहे हैं। उन सब की रायों पर और आपकी ओर से भी जो सुझाव आवेंगे उन सब पर विचार करके एक अन्तिम योजना बना कर उस पर कार्य करेंगे ।

एक माननीय मित्र ने यह बतलाया था कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट डूंगरपुर में चल रहा है इससे वहां क्या फायदा होगा वहां तो केवल भील ही रहते हैं ? मुझे उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ । वास्तविक बात तो यह है कि वहाँ केवल भील ही नहीं रहते हैं पर थोडे समय के लिए अगर आप की बात मान भी लें तो जहां भील रहते हैं वहां क्यों नहीं होना चाहिये। आपने यह भी बताया कि कुछ भील एक टेकडी पर रहते हैं, कुछ दूसरी पर। इस तरह से इन बिखरी हुई टेकड़ियों पर क्या काम होता होगा ? इसके लिए माननीय सदस्य से मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि एक बार वे उस क्षेत्र को देख आवें । मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जो कार्य वहां चल रहा है उसे अगर वे देख लेते तो उन्हें पूर्ण सन्तोष हुए बिना न रहेगा ।

मैं तो साथियों से नम्र निवेदन करूंगा कि सदन में जो बात बताई जावे तो कुछ तथ्य लेकर बताई जानी चाहिये । ऐसी मिथ्या बात बताई जाने से जनता में अविश्वास हो जाता है और मतलब कुछ नहीं निकलता है ।

मुझे तो इतनी ही बातें बतानी थीं जो मैंने बता दी हैं।

श्री अध्यक्ष–श्री दिलीपसिह ।

एक सदस्य–ये बोल चुके ।

Page No.52

श्री अध्यक्ष–श्री रूपनारायण ।

अवाज–ये भी नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष–श्री मोटाराम ।

अवाज–ये भी नहीं हैं ।

श्री तेजमल बापना–सर, मेरा नाम आपकी लिस्ट में है ?

श्री खेतसिंह–अब सरकार की ओर से जबाब शुरू हो जाना चाहिये ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)–श्री अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर काफी चर्चाएं दोनों ओर से हुई और मैंने बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण सुने और जो उन्होंने कहा उसको जाना। पिछले अवसरों पर इस सदन में जो भाषण होते रहे हैं उसके अतिरिक्त कोई खास ऐसी सिद्धान्त की चर्चाएं नहीं सुनने में आई कि जिसकी वजह से उनको बहुत स्पष्ट करने का और उत्तर देने का सवाल आये ।

बहुत सी बातों के बारे में तो पिछली बातों के दोहराने की सी स्थिति मालूम होती थी; फिर भी मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूंगा ।

सबसे पहले तो प्रश्नोत्तर के दर्मियान सिरोही के बारे में जो जिक्र आया उस पर कहना चाहता हूं। सिरोही के बारे में जो जवाब दिया गया वह तो एग्रीकल्चर विभाग के पाली और सिरोही के मिलाने के सम्बन्ध में था। लेकिन उसकी कुछ अखबारों में गलत रिपोर्टिंग होने से उस इलाके में भी गलत तरीके का असर पैदा हुआ और यह गलतफहमी पैदा हो गई कि सिरोही जिला तोड़ा जा रहा है। सिरोही जिले को तोडे जाने का कोई निर्णय नहीं है, यह मैं साफ कर देना चाहता हूं। यह तो महज एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट का प्रश्न था ।

फिर भाषणों के दौरान में पिछले अधिवेशन के समय जो बातें तकावी के बारे में कही गई उन्हीं को दोहराया गया। मैं समझता हूं मैंने उस समय भी स्पष्ट कर दिया था और फिर आज और स्पष्ट करदूं कि तकावी एक तो रेवेन्यू विभाग की तरफ से ली जाती है, और दूसरी तकावी, पिछले वर्ष, जिसकी कि ज्यादातर चर्चा होती है, वह फेमीन विभाग की तरफ से ली गई थी, और तीसरी तकावी एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से ली जाती है। इनके बारे में जहां तक एग्रीकल्चर के डिपार्टमेन्ट का सवाल है, मेरे खयाल से, शायद ही ऐसा उदाहरण हो, जिसमें किसी ने तकाबी मांगी हो और उसके नियमों के अनुसार, उसे न मिली हो ।

जहां तक राजस्थान में तकाबी देने का प्रश्न है यह स्वाभाविक है कि कुल मिलाकर रकम कम होने से किसी तहसील में दो हजार, किसी में ढाई हजार, कहीं पांच हजार से ज्यादा तकाबी नहीं दे सके हैं; इसलिये सब को तकाबी नहीं मिल सकी है। और तकाबी न पहुंचने की वजह से, बहुत से आदमियों को न मिलने के कारण से, निराश होना पडता है। इस कारण कहा जाता है कि कुछ आदमियों को तकाबी नहीं

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

मिली। परन्तु हरेक चीज को हम यह कहकर कि तकाबी पार्टी पोलिटिक्स के आधार पर दी जाती है, गलत है। जो सही बात है वह नहीं कही जाती केवल इस दृष्टि से कही जाती है। हम आज इस बात का असर पैदा करने का प्रयत्न करते हैं कि किसी खास पार्टी का खयाल रखकर ही तकाबी लोन दिया जाता है। मैं समझता हूं और सदस्यों को यह मालूम होना चाहिये कि हरेक व्यक्ति का खयाल रखते हुए तकाबी वितरण की जाती है।

दूसरी बात यह कही गई है कि कुछ इलाकों के अन्दर राजस्थान में अकाल की स्थिति बड़ी भयंकर है, लोग बडी मुश्किल से अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। कई आदमी घर छोड कर बाहर चले गये हैं। मैं मानता हूं कि उन लोगों के सामने दिक्कतें हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सम्मुख इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर पिछले तीन सालों से लगातार कुछ इलाकों के अन्दर वर्षा की कमी के कारण और कुछ इलाकों के अन्दर अतिवृष्टि के कारण दुष्काल पड़ा है और उससे लगातार आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। इसका असर खासतौर से बीकानेर के इलाके के अन्दर और उदयपुर डिविजन के, जिन भीलों के बारे में यहां पर जिक्र आया करता है, इलाकों के अन्दर दुष्काल का असर हुआ है। जोधपुर डिविजन में कुछ इलाके के अन्दर इन बातों का असर हुआ है, सरकार इस बात से अनभिज्ञ नहीं। माननीय सदस्य भी वहां की हालात से परिचित होंगे, मैंने खुद ने जाकर उन इलाकों का दोरा किया है और वहां के हालात को देखा है। देखकर के जो आज तक सूचनायें दी हैं और आपके सामने आगे भी आयेंगी जिससे आपको स्पष्ट प्रतीत होगा कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि उन इलाकों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचायें। राहत पहुंचाने के अन्दर इस बात का खयाल रखते हैं कि जहां तक संभव हो ऐसा काम उस इलाके में शुरु किया जाए, जिससे एक तरफ तो अकाल से पीडित लो ों को राहत मिले और दूसरी तरफ वहां उस जगह ऐसा स्थाई काम ो जाये जिससे रुपये बेकार न जायें। पिछले वर्ष जो अकाल का काम राजस्थान के अन्दर किया गया उस कार्य के बारे में सदन के माननीय सदस्य चाहे ,जस इलाके में जाएं वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो पैसा राहत के कार्य के लिये खर्च किया गया वह ठीक तरह से खर्च किया गया। उस अकाल के काम के जरिये हमने सैकडों नहीं हजारों की तादाद में कुए या ो नए बनवाये या पुराने कुए तैयार करवाए। पीने के पानी का बहुत सी जगह आराम हुआ । कुछ जगह जहां रास्ते नहीं जाते थे उनके रास्ते को ठीक कराया गया। छोटेमोटे इस तरह के काम किये गये जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हों। राजस्थान सरकार द्वारा पिछले वर्ष अकाल के लिये जो भी काम किये गये उन कामों में मैं समझता हूं अगर आप सही दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो माननीय सदस्यों को यह मालूम होगा कि जो रुपया खर्च हुआ है वह लाभप्रद तरीके से खर्च हुआ है। इस वर्ष भी हम हर इलाके की आवश्यकता को ध्यान में रखकर रुपया खर्च करना चाहते हैं, खर्च करने के लिये अलग अलग इलाके के अन्दर मन्जूरियां दी जाचुकी हैं। जैसे बीकानेर डिविजन में सड़कों का काम ज्यादा ।लया गया है। उदयपुर डिविजन के अन्दर छोटे मोटे तालाबों को बनाने के काम पर रुपया खर्च किया जायगा। इस कार हम दुष्काल को मिटाकर जनता को राहत पहुंचाने के काम में पूरी तौर से क्रियाशील व जागरूक हैं। इसमें किसी को भी कल्पना करने की ोर यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि सरकार इस अकाल को निवारण करने में उदासीन तरीके से काम करेगी,

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। सरकार का आर्थिक संकट होते हुए भी सरकार ने इस ओर अवश्य ध्यान रखा है, आगे भी खास तौर से ध्यान रखकर चलेंगे; इस बात का मैं आश्वासन देना चाहता हूं।

एक बात सेट्लमेन्ट रेट्स के बारे में कही गई कि बहुत सी जगह तिगुने सेट्लमेन्ट रेट्स कायम हो गये। मैं समझता हूं कि अबतक कुछ इलाकों में ज्यादा रेट्स लगने की बात जरूर हुई है। उस पर तुरन्त ध्यान दिया गया और आवश्यक कार्यवाहियां की गई। मुझे तो ऐसा मालूम नहीं है कि कहीं भी तिगुनी रेट्स लगी हों। इसी बात के दौरान में मैं आप से यह भी कहना चाहता हूं कि लाखों आदमियों को परचे बांटे गये और शायद ही राजस्थान के अन्दर पिछले वर्षों में ऐसा हुआ हो। सेट्लमेन्ट की दृष्टि से यह वर्ष राजस्थान के लिए महत्त्वपूर्ण है जिसमें लाखों लोगों को परचे बांट दिये गये; जिससे किसानों को राहत मिली है। फिर भी किसानों को कानून की जानकारी न होने के कारण दिक्कतें आई हैं। अब हमने हिदायत जारी की है और वे बीच-बीच में किसानों को पूरी तरह से बताते रहते हैं कि क्या रेट्स लगाये जा रहे हैं, किस तरह की जमीन दर्ज की गई है। जिस तरह से हम काम कर रहे हैं इसकी प्रगति को लक्ष्य में रखते हुए सदन को यह कहना चाहता हूं कि दो साल के अन्दर सारे राजस्थान के अन्दर जहां पहले जिन्स में रेट्स लिये जाते थे वहां वहां नकदी लगान कायम हो जायगा। इस प्रकार एक बहुत बड़े और आवश्यक काम को पूरा करने में इस वक्त सरकार लगी हुई है। इन सारी बातों को देखते हुए इस बात का हर्ष होना चाहिये कि जो हमारे राजस्थान में बहुत से झगड़े टंटे की जड़ है उसका खात्मा हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्यों ने देखा होगा कुछ इलाकों में लगान को लेकर के झगडे-फिसाद इतने बढ़ जाते हैं कि कत्ल होजाता है। बड़ी खुशी की बात यह है कि उदयपुरवाटी के इलाके में जहां पर काफी झगड़े इसी बात को लेकर हुए हैं वहां पर सेट्लमेन्ट का काम शान्ति के साथ चल रहा है और इसमें दोनों पक्ष किसान वर्ग व दूसरा वर्ग पूरा सहयोग दे रहे हैं और वे महसूस कर रहे हैं कि हमें इसमें सहयोग देना चाहिये। इस बड़े काम को ज्यादा से ज्यादा और अच्छे ढंग से पूरा करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है। मुझे खुशी होगी ऐसे अवसर पर जब कि राजस्थान के अन्दर अच्छे और शान्ति पूर्ण ढंग से व्यवस्थित आधार पर किसानों को राहत पहुंचे और पुरानी चीजों में परिवर्तन आये। एक माननीय सदस्य ने इस हाउस में जातीयता की भावना को भडकाने के लिए जाटों और राजपूतों की चर्चा की और काफी उत्तेजित रूप से की। मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति इन चीजों को राजस्थान के हित में उचित नहीं समझेगा।

कुछ शान्ति के तरीकों से एक पुरानी व्यवस्था को एक नई व्यवस्था की ओर आगे बढ़ाना है। उस व्यवस्था की ओर शान्तिपूर्वक जब बढ़ने की बात और आशाएं हैं उस अवसर पर इस तरह की चर्चाएं इतने जिम्मेदार सदन के अन्दर करना, मैं समझता हूं कि वातावरण को सुधारने के बजाय कभी कभी उस वातावरण को दूषित करना भी हो सकता है। जब ये चीजें कही जाती हैं तो उनके पीछे प्रतिहिंसा की भावना और दूसरी भावनाएं हुआ करती हैं: लेकिन उन चीजों को हम हजम करके और ज्यादा ऊंची बातें, जो कि शासन को सुधारने के लिए आवश्यक हैं, कहें तो ज्यादा उचित प्रतीत होगा।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट में जो नायब तहसीलदार काफी बड़ी तादाद में हैं उनको जितने चाहिए उतने अधिकार नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यह सुझाव एक बहुत ठीक तरीके का सुझाव है, और सरकार उस पर विचार कर रही है। हम भी चाहते हैं कि नायब तहसीलदारों

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

को अधिकार दिये जायें, और उन अधिकारों के द्वारा ज्यादा वहां के लोगों को राहत मिले। रेवेन्यु एक्ट जो आगे लाया जायगा, जो बिल यहां पेश होगा, उसके अन्दर इन बातों का ध्यान रखा जाएगा।

असिस्टेन्ट कलेक्टर्स, जागीरों के बारे में यह कहा गया है कि उनके पास काम नहीं है। यह कहना गलत है। उनके साथ लेन्ड रेकॉर्ड डिपार्टमेन्ट के काम को जोडा है, जिससे जागीर के काम के साथ साथ उस पर भी देखरेख रखें। इस तरह से जहां पर कम काम हैं वे शासन को ज्यादा व्यवस्थित करने में ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं।

मैं समझता हूं कि पिछले वर्षों में, जो काफी संकट के वर्ष रहे हैं, कई दृष्टियों से, शासन ने यह पूरा प्रयत्न किया है कि हम दिक्कतों के बावजूद बराबर आगे प्रगति करें और प्रगतिशील कदम उठायें, जिससे कि राजस्थान का हित हो।

मेरे एक माननीय मित्र ने यह कहा कि टिड्डियों को मारने के लिए जो दवा डाली गई है उससे शायद एक भी टिड्डी नहीं मरी है। मुझे आश्चर्य हुआ उनकी यह बात सुनकर कि हमारे सदन में भी कोई है जो यह चर्चा कर सकते हैं या समझ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, टिड्डियों के बारे में यह जो काम किया गया उस काम के लिए न केवल राजस्थान में और भारतवर्ष में ही प्रशंसा की गई है किन्तु यहां के काम की प्रशंसा एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रशंसा का विषय है। पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में उस तरीके की व्यवस्था नहीं हुई जैसी व्यवस्था, तरीके से, भारत सरकार की तरफ से और राजस्थान सरकार की तरफ से यहां हुई है अथवा वे काम कर रहे हैं। अगर दोनों मिलकर पूरी तौर पर काम नहीं करते तो, अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के कई इलाकों में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के कई राज्यों के अन्दर टिड्डियां बडे २ दलों में उडती हुई मिलतीं। और उन्होंने न केवल राजस्थान राज्य में ही बल्कि बाहर के कई राज्यों में फसलों का नाश किया होता। लेकिन यह राजस्थान के अन्दर की व्यवस्था थी कि टिड्डियों के इस आक्रमण को, जो इतिहास में सबसे बड़ा आक्रमण माना गया है, कन्ट्रोल किया गया। उसके बाद, यह तो मैं नहीं कहता कि सब की सब टिड्डियां मार दी गई। बहुत सी आती है और उनमें से कुछ आगे जाती हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में सफलता के साथ में इस कार्यवाही को किया गया। इस बात को वे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम समझें तो सही। यह कहना कि एक टिड्डी नहीं मरी, उससे वही अन्दाज होता है जिस तरह की टीकाएं हमारे सामने लाई जाती हैं।

सदन की जानकारी के लिए अर्ज करना चाहूंगा कि राजस्थान में हजारों बीघे जमीन पर, हजारों भूमिहीन किसानों को बसाया गया है। कई इलाकों के अन्दर और अब आग इस ओर प्रगति की जा रही है।

मैं और भी कुछ बातें, अध्यक्ष महोदय, अर्ज करता; लेकिन मैं समझता हूं कि भाषणों ने पहले ही इतना समय सीमित कर दिया है कि हम लोगों के लिए ज्यादा अधिक कहने का अवसर छोड़ा ही नहीं। कुछ कहना होगा तो आगे अवसर मिलने पर सदन के समक्ष उन बातों को अर्ज करूंगा। मैं अब इतना ही कहकर समाप्त करूंगा।

श्री खेतसिंह—ओन ए प्वाइन्ट आफ इनफॉर्मेशन, सर। अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी हासिल करना है कि उन्होंने जिस फेमीन रिलिफ के लिए विश्वास दिलाया है तो क्या में पूछ सकता हूं कि १० तारीख का 'हिंदुस्तान टाईम्स' उन्होंने यदि पढ़ा हो तो में उसमें जो जोधपुर का समाचार है, सरकार इसके लिऐ क्या कर रही है।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—इसका जवाब में अपने भाषण में दे दूंगा।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मुझे सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिऐ विरोधी दल के नेता को कि उन्होंने राजप्रमुख महोदय के भाषण के सिलसिले में और बहुत सी आलोचनाओं के योग्य बातों को बतलाते हुए कम से कम शांति-व्यवस्था के बारे में यह स्वीकार किया कि वह संतोषजनक है, और उन्होंने बडी उदारता पूर्वक मुझे और सरकार को बधाई दी। में उसके लिये कृतज्ञ हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं उनको और विरोधी दल को।

उसके साथही उन्होंने कुछ त्रुटियां भी बताई, जिनके बारे में मेरी यह धारणा है कि वह उनके विचार तथ्यों से थोडे परे थे। उसमें कुछ गलत फहमी मालूम होती है। विरोधी दल के नेता ने यह शिकायत की कि हमारी आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, जिसने वाकई में प्रशंनीय काम किया है, जिसको कि वह भी स्वीकार करते हैं, और आर्मूड कॉन्स्टेबुलरी के प्रशंसनीय काम को जितना वह महमूस करते हैं उससे कंई गुना ज्यादा सरकार मानती है, जिसके काम में उनसे बहुत सहायता मिली है, का केवल प्रशंसा से काम चलता नहीं, उनको जो वेतन, भत्ते आदि दिये जाते हैं वह बहुत थोडे हैं। मुझे थोडा खेद हुआ उस समय जब उन्होंने आर्मूड कॉन्स्टेबुलरी की सहानुभूति, उचित सहानुभूति प्रकट करते हुए कुछ थोडे आगे बढे और उन्होंने इस प्रकार के विचार भी प्रकट किये जिनसे सहज ही उस प्रकार की सेवाओं में सरकार के प्रति असंतोष और अपने कर्तव्य के प्रति अकर्मण्यता पैदा हो सकती है। इस प्रकार के उन्होंने विचार और शब्द प्रकट किये। मैंने उस समय भी यही कहा था कि इस सदन में बैठ कर हम जिन बातों पर अपने विचार प्रकट करें, जिन शब्दों को प्रकट करें, उनको बहुत तोल कर कहें। यह सही है, में भी मानता हूं, कि आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी ने जितना प्रशंसनीय काम किया है और जिस प्रकार की कठिनाइयों में उन्होंने काम किया है उनको देखते हुए जो वेतन भत्ते आदि हम दे रहे हैं वे कम हैं। उन्हें अधिक यदि हम दे सकें तो वह अनुचित नहीं होगा, वह सारा उचित ही होगा; लेकिन फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि जो वेतन, भत्ते आदि दे रहे हैं वे ऐसे हैं जो सारे नगण्य हों अथवा उनको पाने वाले सिपाहियों को अपना कर्तव्य पालन नहीं करना चाहिये, या कि सरकार उनकी कठिनाइयां और उनकी जरूरतों के प्रति विचारशून्य है। मैंने दूसरे राज्यों में इस प्रकार की सेवाओं को मिलने वाले वेतन भत्ते आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आपको यह विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरी यह इच्छा है कि यदि हो सके तो जितना वेतन, भत्ते आदि हम दे सकते हैं उनसे अधिक दें, लेकिन व्यवहारिकता यह है कि पिछले बजट के समय में भी मैंने यह चाहा था कि उनके वेतन, भत्ते आदि को बढाया जाय, बढाने की मेरी तीव्र इच्छा थी। मेरे साथी भी मुझसे सहमति रखते थे, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण वह संभव नहीं हो सका। अबकी बार हमारा विचार है कि हम अधिक भत्ते, वेतन आदि दें, और इस दफा हम कर सकेंगे या नहीं, यह आगे की बात है। में कहना चाहता हूं कि जितना अधिक हम

[श्री टीकाराम पालीवाल]

कर सकेंगे उसमें कमी नहीं होगी, लेकिन जो कुछ दिया जा रहा है वह भी दूसरे राज्यों के मुकाबले में ऐसा नहीं है जिसके प्रति असंतोष प्रकट किया जा सकता हो, इस प्रकार की सेवाओं के लिए । मैं अपने माननीय मित्र की जानकारी के लिए कुछ थोडे से आंकडे बताता हूं, दूसरे राज्यों के, जो इस प्रकार की सेवांओं के लिए दिये जा रहे हैं ।

भिन्न भिन्न राज्यों में इस प्रकार की सेवाओं के नाम कुछ भिन्न भिन्न हैं । हमारे राजस्थान में आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रोविन्शियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी कहते हैं । इस प्रकार से इसके भिन्न भिन्न नाम हैं । लेकिन इस प्रकार की सेवाओं के लिए जो वेतन दरें दी हुई हैं वह मैं आपकी जानकारी के लिए सुनाता हूं :-

उत्तर प्रदेश	में	३०।१।४५	
पंजाब	में	४०।१।५०	
मध्य प्रदेश	में	३०।१।३५	
मद्रास	में	३२।२।४२	
बिहार	में	२५।१।४०	
उडीसा	में	२८।½।४०	
आसाम	में	२८।½।४०	दो वेतन की दरें ।
		३०।½।४५	

यह 'ए' क्लास राज्यों की बात है । 'बी' क्लास राज्यों में :-

मध्य भारत	में	२५।१।३०	
पेप्सू	में	३०।१।४०	
सौराष्ट्र	में	३०।½।३५	
हैदराबाद	में	३०।½।४०	और एक दूसरी; दो वेतन की दरें हैं ।
त्रावणकोर-कोचीन	में	२५।१।३५	
मैसूर	में	३२।२।४३	

इनके मुकाबले में राजस्थान में ३०।१।४५ है । इस प्रकार आप देखेंगे कि 'बी' श्रेणी के किसी भी राज्य से हमारी वेतन की दरें अच्छी हैं । 'ए' क्लास राज्यों में केवल पंजाब के वेतन की दर हमसे कुछ ही अच्छी है । हमारे यहां ३०।१।४५ हैं तो वहां ४०।१।५० हैं; लेकिन पंजाब की आर्थिक स्थिति और हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा अन्तर है । ....

श्री जसवन्तसिंह-ऑन ए पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन, सर ।

हमारे श्रीमान् उपमुख्य मंत्री महोदय ने यह फरमाया है कि जहां तक मेरा खयाल है, हमने तनख्वाह, एलाउन्सेज पर कभी एतराज किया ही नहीं । हमने जो कहा है उसको होम मिनिस्टर साहब

Page No.58

[श्री जसवन्तसिंह]

या तो जानते ही नहीं या जानबूझ कर उसको कहने के लिए तैयार नहीं हैं । मैंने कहा था कि लिविंग कन्डीशन्स, जिसमें हमारी आर्मड कान्स्टेबुलरी रह रही है, वह ऐसी बुरी है कि कोई मानव इस प्रकार को कन्डीशन्स में रह नहीं सकता है। उन कन्डीशन्स में उनको रखकर आप यह चाहते हैं कि वे दिल से काम करें, लेकिन यह नामुमकिन है । मानव का यह स्वभाव है कि जब तक उसकी परवाह नहीं की जाय तो वह दिल से काम नहीं करेंगे । मैं यह बताना चाहता हूं कि आज भी उनके पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है । रेगिस्तान के मुल्क में वहां इतनी ठंड पड़ती है लेकिन सोने के लिए छत नहीं है । गर्मी वहां ११५–११७ डिग्री मामूली तौर पर पड़ती है; लेकिन उन आदमियों के रहने के लिये कोई छत नहीं है। गर्मी में तो लोग दरख्तों की छाया के नीचे भी सो जाते हैं, लेकिन राजस्थान बनने के बाद दरख्त भी तो बुरी तरह से काटे गये हैं । सरदी की मोसम में उन्हें बगैर छत के रहना पड़ता है । पीने के लिए पानी का प्रबन्ध नहीं है, सवारी के लिए ऊंट का प्रबन्ध नहीं है । खाने को जो प्रोवीजन लाया जाता है वह १५–१५ या २०–२० मील से अपने कन्धों पर लाते हैं ....

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री) –Is it a new speech or a repetition of the old one.

श्री जसवन्तसिंह–वह इसलिए है कि मैंने जो एतराज किया था उस एतराज का गलत जवाब दिया जा रहा है; इसलिए मैं कहता हूं ।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)–अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि उनको वेतन-भत्ते आदि की दरों के बारे में कोई शिकायत नहीं है; वह ठीक है। मैं धन्यवाद देता हूं उनको, इस बात के लिए कि उन्होंने खुद ने यह स्वीकार किया है । यह ठीक है कि इस समय वह कॉन्स्टेबुलरी हमारे बोर्डर पर ड्यूटी दे रही है, वह अपना काम कर रही है ।

आप लोगों को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जिससे हमारे सिपाहियों का साहस टूटे । हमारे सिपाही बड़े साहस से काम करते हैं । वे कितनी कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, यह एक सोचने की बात है । क्या मेरे लायक दोस्त यह कहना चाहते हैं कि रेगिस्तान को बदला जा सकता है ? क्या इस रेगिस्तान में मीठे पानी की नदियां बहाई जा सकती हैं ? मैं यह कहूंगा कि उन सैनिकों के लिए सब तरह का प्रबन्ध है । यह सही है कि उनकी छाया के लिए वृक्ष नहीं हैं। वृक्ष एक, दो, चार दिन में लगाये नहीं जा सकते। सैनिकों को सेना में जिस प्रकार के साधन होने चाहिये, वे उपलब्ध हैं । मुझे मालूम नहीं कि वे सदस्य जो इस बात को कहते हैं उन्होंने फ्रन्ट पर जाकर परिस्थिति को देखा है या नहीं । मैं यह कहूंगा कि मैं वहां पर गया हूं और सिपाहियों से मिला हूं । उनके साथ जाकर मैंने देखा है और उनके साथ खाना भी खाया है । हम उनके लिए बेरेक्स नहीं बना सकते हैं, लेकिन टेन्ट्स बने हैं। वे ऐसे नहीं हैं जिससे उनको वर्षा और धूप से तकलीफ हो । हमने बोर्डर पर जिस प्रकार के आयोजन हो सकते हैं, किये हैं और मैंने अपने सिपाहियों को देखा है कि वे बडी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। उनके चहरों पर मुस्कराहट मैंने देखी । उनके चेहरे कभी उदास नहीं थे और वे बडी खुशी से काम कर रहे थे । इसलिए मैं समझता हूं कि आपका यह कहना कि उनको वहुत ज्यादा दुख है, उचित नहीं जान पडता ।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

इसके अलावा हमने वहां पर ऐसा प्रबन्ध कर दिया है कि जिससे एक ही बेड़े को बहुत समय तक नहीं रहना पड़े । वे वहां पर बारी बारी से जाते हैं । नये और पुराने अपनी अपनी बारी से आते-जाते रहते हैं जिससे उनको आराम मिलता रहता है और वे अपने हैडक्वार्टर पर आते हैं । इस प्रकार का इन्तजाम हमने अपने सैनिकों के लिये किया है और जो सुविधायें दी जा सकती हैं हमने दी हैं । यह सच है कि सामान को सभी जगह मोटरों व लारियों द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है मगर जितनी दूर तक हमारे ट्रक व मोटर लोरीज जाती हैं, वहां तक तो सामान पहुंचाया जाता है। मगर रेगिस्तान में ऐसी जगह भी हैं जहां पर हमारे ट्रक व मोटर लॉरीज़ नहीं जा सकती हैं, सिर्फ ऊंट या आदमी ही सामान ले जा सकते हैं । इसके लिए हमने प्रबन्ध किया है कि सामान ऊंटों पर पहुंचाया जावे । मैं अभी कुछ दिन पहले देख कर आया हूं कि वहां पर इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है ।

आपने यह फरमाया कि पानी भी कई जगह दूर से लाना पड़ता है मगर यह सैनिक जीवन है, लाना ही पड़ता है । सैनिक ड्राईंग रूम में बैठने वाले नहीं । इसलिए हमको चाहिये कि जिन परि-स्थितियों में वे काम कर रहे हैं उसके लिए हमें उनका उत्साह बढ़ाना चाहिये ।

मेरे माननीय मित्र ने यह नहीं बताया कि कौन से कार्य ऐसे थे जिनको सरकार कर सकती थी, और नहीं किये । मेरी राय में सरकार रेगिस्तान को नहीं बदल सकती, वहां वृक्ष बहुत जल्दी नहीं उगा सकती। यह भी हम नहीं कर सकते कि रेगिस्तान के टीलों पर सड़कों का जाल बिछा दें । मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सिपाही बहुत उत्साह, मुस्तैदी व महनत से अपना कार्य कर रहे हैं । इस बात का सरकार को पूरा विश्वास है और जो कार्य वे लोग कर रहे हैं वह सराहनीय है ।

एक बात मुझे और निवेदन करनी है और वह है लॉ एण्ड आर्डर के संबन्ध में । बहस के दौरान में शायद इस ओर के किसी सदस्य ने कुछ कहा, जिससे विरोधी दल के नेता को कुछ ऐतराज हुआ और मैंने उनको कहते सुना था कि शायद सरकार की ओर से या इस दल की ओर से यह माना जाता है कि कुछ विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग के खिलाफ कठिन कार्यवाही की गई । मैं सच कहता हूं कि कठिन कार्यवाही किसी विशेष दल के खिलाफ़ नहीं की गई है । जिन व्यक्तियों के खिलाफ सरकार को सन्देह हुआ कि वे व्यक्ति डकैतों को सहायता दे रहे हैं, उनको आर्म्स दे रहे हैं या किसी प्रकार की दूसरी सूचना दे रहे हैं और जिन जिन के बारे में सरकार को सूचना मिली, उनके खिलाफ सरकार ने कुछ कार्यवाही की । और मैं समझता हूं कि उस कार्यवाही का असर अच्छा हुआ । यह धारणा, कि किसी विशेष वर्ग के खिलाफ कार्यवाही की गई, सर्वदा गलत है । मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही सरकार ने किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष दल के लोगों के खिलाफ नहीं की है । आप लिस्ट उठाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि इसमें सभी जातियों के लोग हैं । इत्तफाक से इसमें ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका समाजिक दर्जा ऊंचा रहा हो । मगर सरकार की यह नीति रही है कि जहां तक राज्य की सुरक्षा और शांति का सवाल है उसमें सरकार भिन्न भिन्न वर्गों के विचार से, जातीयता के विचार से, राजनैतिक विचार से नहीं चली है, न चलना चाहती है ।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

मैं यह मानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में, राज्य संचालन में, कहीं भी किसी प्रकार की दलगत राजनैतिक, जातिगत या वर्ग के आधार पर विचार नहीं किया जाना चाहिये। न तो इन विचारों के कारण किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सकती है और न जहां ऐसी कार्यवाही करने की आवश्यकता हो वहां इन विचारों से हिचकिचाहट ही हो सकती है। यह सरकार की निश्चित नीति रही है। बहुत से लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ी, दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ी जिनका समाज में ऊंचा स्थान था। इसमें किसी को कोई खुशी नहीं थी, वह कार्य अरुचिपूर्ण था; परन्तु कर्त्तव्य पालन के लिये, राज्य की सुरक्षा के लिये और जनता की सुरक्षा के लिये वह कार्य करना ही पड़ा।

मैं यह दावा नहीं करता कि हर मामले में हर एक कदम जो सरकार ने उठाया, वह शत-प्रतिशत सही रहा होगा। हो सकता है कि जहां १००–५० आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है, एक दो मामलों में वह आधार सर्वथा सही नहीं हों। परन्तु आप मानेंगे कि जैसी अराजकता हमारे राज्य में फैल चुकी थी, भय और त्रास का वातावरण बन गया था, उसमें ऐसी कड़ी कार्यवाही करना आवश्यक हो गया था और जनता के दिलों में सरकार की सुरक्षा की नीति के प्रति विश्वास पैदा करना जरूरी था जिस से सरकार को निश्चित रूप से गुप्त सूचनाओं के आधार पर ही कार्य करना पड़ा। वे गुप्त सूचनाएं कई बार सर्वथा सही थीं और हो सकता है कई जगहों में वे सर्वथा सही नहीं हों। अतः मैं दावा नहीं करता कि शत-प्रतिशत कदम सही कारणों पर निर्धारित था। जितनी छान-बीन हम कर सकते थे, उसके बाद जो आवश्यक जंचा राज्य की सुरक्षा के लिये वह किया, नेकनियती से, मजबूती से किया ये कार्यवाहियाँ तो गुप्त सूचनाओं के आधार पर थीं, अदालतों में जो साक्षी होती है उनके आधार पर भी अदालतें जो निर्णय करती हैं और अपील करने पर ऊपर की अदालत उस निर्णय को गलत मानती है, तो ऐसी हालत में यह कहना कि ट्रिब्यूनल ने जो सरकार के पास सामग्री थी, उसको पूरा नहीं माना; इससे आपको सरकार की नीति पर सन्देह नहीं करना चाहिये।

इस तरह की नीति सरकार की रही है और हमेशा रहेगी। राज्य संचालन में कोई पक्षपात न तो आने दिया है और न आने दिया जायगा।

विरोधी पक्ष की ओर से यह भी बताया गया है कि डकैतियों की संख्या तो कम हुई पर चोरियां बहुत होती हैं। यह किसी किसी समय के लिये ठीक हो सकता है; लेकिन पूरा ओवर ऑल करके देखा जाये तो ऐसा मालूम नहीं होता। किसी महीने में ज्यादा चोरियां हुईं तो किसी महीने में कम। इसका कारण यह भी हो सकता है कि जब शासन व्यवस्था कमजोर दिखाई देती थी तो लोगों का साहस बहुत बढ़ गया था, खुले आम डाके डाले जाते थे। लॉ एण्ड ऑर्डर को जब मजबूती से पकड़ा गया तो बहुत से डाकू मारे गये, बहुत से पकड़े गये और जो लोग पहले डाके डालते थे उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया। उनकी जो एनर्जी डाके डालने में पहले लगती थी वह एनर्जी गुपचुप चोरियां करने में लगाई, यह हो सकता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं और यह सदन विश्वास करे कि पुलिस के जिस फोर्स ने, न्याय के जिस दण्ड ने डकैतियों को रोका है वह चोरियों को भी रोकेगा। यह सदन को विश्वास करना चाहिये।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

अब मैं एक दो बातें प्लानिंग के बारे में कहकर अपने भाषण को समाप्त करूंगा। प्लानिंग के विषय में विकास योजना में जो केन्द्र से सहायता मिली है उसके बाबत कुछ सदस्यों ने असन्तोष जाहिर किया है। यह बात सही है कि राजस्थान के विस्तार और पिछड़ी हुई हालत को देखते हुए जितनी सहायता हमें केन्द्र से मिलनी चाहिये, या जितनी हम चाहते थे, उतनी नहीं मिली, पर यह भी सही नहीं होगा कि जो सहायता मिली है उसको बहुत कम करके कूंता गया है। कुछ आंकड़े बताये गये थे कि अमुक राज्य को पर हैड ५०) रुपये आते हैं कहीं ३०) रुपये, कहीं ३५) रुपये आते हैं और राजस्थान में केवल ११) रुपये ही पर-हैड (Per Head) आते हैं। एक दृष्टि से यह अंक सही है पर यह ११) रुपये पर हैड का फीगर मिसलीडिंग (misleading) है। जो राजस्थान में १६ करोड़ की रकम खर्च की जाने वाली है उसपर से यह ११ का फीगर पर-हैड गिना है। इसमें दूसरा जो खर्चा होता है वह नहीं गिना गया है मसलन २९ करोड रुपया भाकरा बन्ध पर खर्च होने वाला है, इसके अलावा चंबल नदी में अगला जो समय बाकी है उसमें करीब १५ करोड रुपया खर्च होगा वह ७.५ (सेवन पाइंट फाइव) राजस्थान का होगा उससे जो फायदा होनेवाला है उसका बहुत सा हिस्सा राजस्थान का होगा। वह जो १६ करोड की रकम है उसके अलावा २ करोड़ ५ लाख रुपया अभी हम विशेष रूप से विकास आयोजन से, प्लानिंग कमीशन से बात करके प्राप्त कर चुके हैं। इस तरह कुल जोड़ १६ करोड़ नहीं ५५ करोड की रकम होती है, और ५५ करोड की रकम को अच्छा मानना चाहिये।

हम यदि यह कहें कि यह ठीक नहीं तो इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। कितनी ही धन सम्पत्ति हम राजस्थान में लगा सकते हैं। रुपया लगाने के लिये बहुत जगह है; लेकिन हमें अपने साधनों को भी देखना होगा और केन्द्र के साधन भी देखने होंगे।

केन्द्र केवल हमें ही नहीं देता है केन्द्र के सामने सारे देश का प्रश्न है। इसलिये मैं समझता कि जितना हमें केन्द्र ने दिया है उसके लिये हम उनके अनुगृहीत हैं। दूसरे प्रान्त, जैसे बम्बई ५०–६० रुपये पर-हैड खर्च करेंगे वह सारे केन्द्र की सहायता पर ही निर्भर नहीं है बम्बई का भी उसमें अच्छा अनुपात में हिस्सा है। परन्तु हम हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उतना खर्चा नहीं कर पाते हैं। इसलिये हमको केन्द्र पर आश्रित रहना पड़ता है। केन्द्र ने हमको जो कुछ दिया यद्यपि वह हमारी आशा से कम पडता है लेकिन फिर भी, जितना भी उन्होंने हमको दिया उनकी सहायता को हम भुला नहीं सकते। यह नहीं हो सकता कि हम उनसे सहायता लेते जावें और यह कहते जावें कि हमें केन्द्र ने कुछ नहीं दिया। ये दोनों बातें नहीं हो सकतीं।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जिसे दूसरे मित्र स्वयं कह सकते हैं, पर शायद वह बोलेंगे नहीं, वह है फाइनेन्स के बारे में। एक मित्र ने जो कुछ यहां कहा वह मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसा लगा कि मानो जान बूझकर कटाक्ष कर रहे हैं। फाइनेन्स का पोर्टफोलियो चेंज करने का अर्थ यह लगाते हैं कि पहले के फाइनेन्स मिनिस्टर अयोग्य थे, इसलिये बदले गये। यह गलत बात है। फाईनेन्स के कठिन कार्य को जिस कठिनाई से उन्होंने चलाया वह सराहनीय है। जिनके प्रयत्न से आगे का भविष्य सुधर रहा है, उसके लिये यह बात कहना ठीक नहीं होगा। फाइनेन्स कमीशन से जो आर्थिक सहायता मिलने वाली है वह भूतपूर्व फाइनेन्स मिनिस्टर के मेमोरेंडम और प्रयत्नों

[श्री जयनारायण व्यास

के कारण ही मिलने वाली है, यह हमको नहीं भुलाना चाहिये। इकोनोमिक्स मेजर्स को काम में लाने में भी ये कितने तत्पर रहे, यह मैं जानता हूं। बहुत से लोग निर्णय करने में जान बूझकर गलती कर बैठते हैं। जिस दृष्टि से काम किया जाता है उसकी ओर ध्यान न देकर मनमाना निर्णय कर बैठते हैं। जिस व्यक्ति ने कर्त्तव्य परायणता से काम किया उसके लिये इस तरह की बात कहना, इस सदन के वहस के लायक बात नहीं पोर्टफोलियो कई कारण से बदला जा सकता है।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर जो व्याख्यान हुए हैं उनमें से मुख्य मुख्य बातों के ऊपर कुछ शब्द कहूं उससे पहले मैं दो एक शब्द माननीय सदस्यों की सेवा में उपस्थित करना चाहूंगा। वे ये हैं कि यह सदन एक उत्तरदायी सदन है जिम्मेदार सदन है और इसमें सुनी-सुनाई और अखबारों की रिपोर्टस् के ऊपर या कल्पना पर धारणाएं नहीं बनानी चाहिये; बल्कि फेक्ट्स के ऊपर और ठोस बातों के ऊपर अपनी धारणाएं बनानी चाहिये। यदि ऐसा करें तो संभव है कि जिस तरह की टीका-टिप्पणी हुई उतनी शायद नहीं होती। अभी-अभी माननीय राजस्व मंत्री बोल रहे थे तो खेतसिंहजी ने एक स्टार्वेशन डेथ (भूख के कारण मृत्यु) की कहानी सुनाई थी कि हिन्दुस्तान टाइम्स में उन्हें एक ही फेमिली के चार आदमी मरने के समाचार पढने में आये हैं और मैंने कहा कि मैं इसका जवाब दे दूंगा। मैं आपके जरिये उनको, सदन को और हिन्दुस्तान टाइम्स को और अन्य व्यक्तियों को सूचना देना चाहता हूं कि दो महिनों में उस गांव में एक भी मौत नहीं हुई। ज्यों ही मैंने अखबार में यह खबर पढ़ी मुझे खयाल आया कि संभव है ऐसा हुआ हो। मैंने कमिश्नर को टेलिफोन किया। कुछ जवाब आया; फिर दुबारा टेलिफोन किया। जवाब आया कि दो महिनों पहले वहां दो एक आदमी मरे थे, बाद में वहां कोई मौत नहीं हुई। ७० हजार आदमियों के भूखों मरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अममन हमारे यहां गप्पें हांक दी जाती हैं। नेहरूजी के पूछने पर एक अखबारवाले ने कहा कि यदि मैं बढ़ा चढ़ाकर कोई बात नहीं लिखूं तो मेरा अखबार ही नहीं चल सकता। मैं समझता हूं कि जिम्मेदार अखबारों के लिये इस तरह से लिखना ठीक नहीं है और जिम्मेदार सदस्यों के लिये इस तरह की बातों को सही मानना ठीक नहीं है। इसी तरह एक भाई ने बहुतसी बातें और कही थीं। अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज किया था कि इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिये जो जिम्मेदारी को नीचे गिराती हों। सदन का स्तर ऊंचा उठाने की दृष्टि से मैं अर्ज कर रहा हूं। राजप्रमुख महोदय के भाषण में वर्णित बातों के विषय में जानकारी ठीक ढंग से करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कुछ सही बातें प्रश्नों और उनके उत्तरों द्वारा जानी जा सकती हैं। कुछ सही बातें आपसी बातचीत से भी जानी जा सकती हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, खास कर विरोधी दल के सदस्यों को, कि वे जो भी बातें जो ऑफिशियल सिक्रेटस् नहीं हैं, जानना चाहेंगे तो उनको मैं बतलाने के लिये हमेशा तैयार रहूंगा। मैं उनको सहयोग दूंगा, जानकारी देने के लिये, ताकि गलत बातें कहने का मौका नहीं मिले।

मान्यवर राजप्रमुख के भाषण पर दो तीन बातें छोटी छोटी हुई थीं। एक तो यह कहा गया कि हिन्दी में भाषण नहीं हुआ। मैं इस बात को मानता हूं और सदन को सूचना देना चाहता हूं कि राजप्रमुख यहां पर ज्यादा नहीं रह सके थे, कौटुम्बिक कारणों से। उनके एक कुटुम्बी बीमार थे, वो यहां अचानक आये थे। मैंने उनसे प्रार्थना करवादी थी। वे आगे जाकर कोशिश करेंगे कि वे हिन्दी में भाषण दें। (हर्ष ध्वनि)

[श्री जयनारायण व्यास]

दूसरी बात जो हमारे मित्र श्री गोपीलालजी यादव ने कही थी कि राजप्रमुख को चाहिये कि वे सरकार से ही नहीं बल्कि विरोधी पक्ष से भी सलाह करके भाषण तैयार किया करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजप्रमुख का भाषण विरोधी दल की पोलिसी का द्योतक नहीं होता है, बल्कि वह सरकार की पोलिसी का द्योतक होता है (करतल ध्वनि)।

भाषण के संबंध में आलोचना की जो तीसरी बात नजर में आई वह यह थी कि भाषण में एचीवमेन्टस (Achievements) की कोई बात ही नहीं थी। राजा मानसिंहजी ने कहा कि भाषण में कोई एचीवमेन्ट की बात ही नहीं थी। पोलिसी के बारे में कांग्रेस की कोई आइडियोलोजी नहीं है। भाषण में भाकरा नांगल, चम्बल प्रोजेक्टस, शिक्षा, स्वायत्त संस्थाएं, पंचायत आदि का जो जिक्र किया गया है वह कोई एचीवमेन्ट नहीं है। सरकार पर स्ट्राइक्स कराने व लोक आउट का चार्ज लगाया गया है। वे जिम्मेदार आदमी हैं। वे स्वयं जिम्मेदार पद पर रह चुके हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि किशनगढ़ मिल में लोक आउट चला था स्ट्राइक नहीं हुई थी। सरकार ने मिल मालिक को कहा कि लोकआउट बंद करो। उसने हाई कोर्ट में रिट पेश करदी।

श्री राजा मानसिंह—On a point of information, Sir, I should like to inform the Hon'ble Chief Minister that I was not referring to any incident. I was referring to the Satyagrha at Alwar.

श्री जयनारायण व्यास—It is all the more wonderful, sir, that he has generalised a statement by referring to a fact which never happened.

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of information, Sir, I may inform the Hon'ble Chief Minister that demonstrations were taken.

श्री अध्यक्ष—Order.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि उन्होंने एक दो जगह के स्ट्राइक की बात कही थी। मैं मान लेने के लिये तैयार हूं कि एक दो जगह स्ट्राइक हुइ हों और लाठी चार्ज भी हुआ हो किन्तु जैसा कि उन्होंने, जो एक जिम्मेदार आदमी हैं, तोड मरोड कर कहा है, वह मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कई आन्दोलनों में रहा हूं। मैंने रियासतों के आन्दोलनों को देखा है। मैंने जोधपुर के आन्दोलन को देखा है, मैंने भरतपुर के आन्दोलन को देखा है, मैंने अलवर के आन्दोलन को देखा है। लाठी चार्ज, स्पियर (Spear) चार्ज भी देखे हैं और घोड़ों पर बैठकर लोगों को पीटते भी देखा है; किन्तु यहां पर ऐसी बात नहीं हुई है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

श्री जसवन्तसिंह—यहां पर ऐसी बात नहीं है?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—यह क्रेडिट हमको है। यदि यहां ऐसी बात नहीं हुई है तो Credit goes to us.

[श्री जयनारायण व्यास]

एक बात जो मुझे नजर आई वह यह है कि कुछ सदस्यों का यह मत है कि मंत्रियों पर अच्छा हमला करें; ताकि वे बोलने के लिए खड़े हों तो हिचकिचा जायें। मंत्रियों पर चारों तरफ से जो कहा गया है उनमें बहुतसी बातें गलत कही गई हैं जो मैं आपको फिर बतलाऊंगा। मंत्री जो होता है वह यही समझ कर होता है कि उसको अपनी चमड़ी मोटी रखना है, उनका पिनप्रिकिंग (Pinpricking) होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मैं एक मंत्री की हैसियत से नहीं कह रहा हूं किन्तु एक सदस्य की हैसियत से कह रहा हूं और वह भी पिनप्रिकिंग के लिहाज से नहीं। यदि बातों को उल्टा सीधा करके रखा जाय तो यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जिस बात को मैं अर्ज करना चाहता था वह यह है कि जब कुछ सदस्य, जैसा कि कहा गया था, बोल रहे थे तो मैं यहां सदन में हाजिर नहीं था। मैं उनको यह बता दूं कि मैं लोबी में बातें नहीं कर रहा था किन्तु सरकार का काम ही कर रहा था। एक अखबार में खबर छपी कि फलां जगह चार आदमी मर गये। इस पर प्रश्न भी पूछा गया। यहां मंत्री लोग बैठे हुए थे और सारी बातों का नोट मेरे पास था। मैं आंख से ओझल था किन्तु दिल से नहीं। यद्यपि मैं यहां शरीर से नहीं रहा हूं या मेरे दूसरे साथी नहीं रहे हों लेकिन शरीर ऊपर उठे हुए होने पर भी मेरा दिल यहीं था। (हंसी) सारे साथियों की जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलीटी है। वे अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना जानते हैं।

हमारे विरोधी दल के माननीय नेता ने कुछ बातें कही थीं। मेरा खयाल है कि विरोध करने के लिए ही विरोधी बातें कह डाली हो; ऐसी बात नहीं है। उन्होंने यह कह डाला कि 'अगर आप लोगों से काम नहीं चलता है तो आप सरकार छोड क्यों नहीं देते', न्याय क्यों नहीं कर देते, उनके पास सरकार आजायगी तो वे जल्दी ही फैसला कर देंगे। मेरे खयाल से उनका इशारा कम्युनिस्ट सदस्य की तरफ ही था। मेरे खयाल से यह ठीक नहीं है। पहले आप मोस्को ट्रायल और पीपल्स कोर्ट की हालत को पढ़ लीजिएगा मेरे जैसे व्यक्ति या मेरे साथियों को तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे दूसरे लोगों को आने वाली हो। अतः सोच करके ही बात कहियेगा। (हंसी)

मैं दूसरी बात जो अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि मिनिस्टरों पर जो हमला किया जाता है वह उनकी मोटरों के कारण। मोटरों की भों-भों की आवाज सदन तक पहुंच जाती है। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, मोटर अजीब बला है। अजीब बला इसलिए है कि हम मिनिस्टरों को जो मोटरें मिली हुई हैं कि वे इतनी बुजुर्ग हो चुकी हैं कि काफी पेट्रोल खाती हैं और चलती हैं तो ठाठ से। मैं आपको कोन्फिडेन्स में लाकर कह सकता हूं कि मोटरों को धक्का लगाने का मौका मिनिस्टर महोदयों को मिला है। इन मोटरों के बारे में तो हम सोच भी रहे हैं।

पर मैं इस सलाह को मानने वाला नहीं कि आप यह कहें कि मिनिस्टर दौरे ही न करें क्यों कि अगर हम दौरा न करें तो यह कहा जाता है कि आँखें बन्द करके बैठे हैं और करें तो इस तरह से भों-भों करती हुई मोटरें इस सदन में चली आती हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वे तो अपनी कॉन्स्टिटुएन्सी में चले गये। मेरा खयाल है कि जिस कॉन्स्टिटुएन्सी में जावें, चाहे वह अपनी ही में जावे तो यह कहना और न जावें तो वैसे कहना; यह कोई अच्छी बात नहीं है। फिर मोटरों के लिये तो हम

[श्री जयनारायण व्यास]

सोच रहे हैं। मैंने चीफ मिनिस्टर जोधपुर की हैसियत से और मेरे मित्र श्री जसवन्तसिंहजी ने, चीफ मिनिस्टर, बीकानेर की हैसियत से, राजस्थान सरकार को मोटरें जो दी थीं वे काफी पुरानी थीं। इन मोटी बुजुर्ग मोटरों के बदले में ऐसी मोटरें, जो छोटी हों, अच्छी हों, कम खर्चीली हों, या दूसरे तरीके की हों तो ज्यादा अच्छा है। पर अगर फिगर्स पर ही सोचा जावे तो कोई भी बरी नहीं हो सकता, इन भारी बुजुर्ग मोटरों को चलाकर। कुंवर साहब भी इससे सहमत होंगे। मोटरें अच्छी हों और कम खर्चीली हों, जैसे कि किसी गाय के बारे में कहा जाता है कि कम खाने वाली और ज्यादा दूध देने वाली हो, तो यह हम सोचेंगे। पर दौरे ही हम न करें तो जैसा अभी मेरे साथी कुंवर साहब ने कहा था, बोर्ड़र के बारे में हाल ही मालूम न हो सके। मैंने खुद ने उधर दौरे किये हैं और बोर्ड़र की हालत देखी है। हमारे जो काम करने वाले नोजवान बोर्ड़र पर हैं उनका कहना बिलकुल भिन्न है; उस कथन से, जैसा कि माननीय मेरे साथी कुंवर जसवन्तसिंह ने कहा है। मैं तो वहां पर गया हूं जहां बीकानेर युनिट के लोग थे, वे बड़े खुश थे, सन्तुष्ट थे और बड़े उत्साह से काम करते थे। वे कभी यह देखने की कोशिश नहीं करते कि हम में किसी तरह की कमजोरी आ गई है। मुझे आश्चर्य हुआ, यह सुन कर कि डाकू उनको पकड कर ले जाते हैं। हमने कई डाकुओं को मारा है। इतना होने पर कभी किसी एक आध हमारे आदमी को वे भी पकड़ सकते हैं। उसके लिए और वह भी एक ऐसे आदमी को १५ हजार देने की बात हमारे कुंवर जसवन्तसिंहजी करते हैं जो उनके पड़ोसी हैं; यह तो ठीक है कि वे बीकानेर युनिट में जसवन्तसिंहजी के पड़ोस में रहते हैं। मैं साफ अर्ज कर देना चाहता हूं कि मुझे तो यह सोच कर थोडा सा आश्चर्य हुआ कि हमारे कुंवर जसवन्तसिंहजी ऐसी बात कैसे कहते हैं। उन्हें तो हिम्मत दिलानी चाहिये थी। राजपूतों के लिए तो जान प्यारी नहीं, शान प्यारी है। उस शान को छोड़कर जान के लिए आप १५ हजार के रिश्वत की बात करें (तालियां) और वह भी मुझ ब्राह्मण से; जो पैसा नहीं, उपदेश दे सकता है।

एक साहब जो कि कभी कभी जोश में बड़ी अजीब सी बातें कह जाते हैं वह भी मिनिस्टरों के बारे में ही है। एक मेरे मित्र ने कह दिया कि कैबिनेट में मैंने अपने यस-मेन ले लिये या अब भी कभी लूंगा यस-मेन लूंगा। यह कोई अच्छी बात नहीं है। पालीवालजी ने जिन्हें लिया उन्हीं को मैंने ले लिया तो हम दोनों के वे यस-मेन होगये मान लें। यह खुदा का दावा कैसे करने लगे कि यह मेरा यस-मेन है और वह जो आगे लूंगा वह भी होगा; मानो जो खुदा को पता वह इनको पता हो जाता है। मैंने अपने साथियों के नाम अभी मालूम भी नहीं किये और मुझे मालूम भी नहीं उससे पहले ही उन्हे पता लग गया, फिर एक शब्द यह भी सुनने में आया कि इनके चरित्र भी बिगड़े हुऐ हैं। मैं समझता हूं कि मुझे ऐसी बातों की उपेक्षा करनी चाहिये आखिर मिनिस्टर को भी मनुष्य समझें, इतनी बस में प्रार्थना करना चाहता हूं; आप जैसे हम भी इन्सान हैं। ये हमारे कलीग (Colleague) हो सकते हैं, कभी आप हमारी जगह हो सकते हैं। कभी हम उधर की बेंचो में भी बैठ सकते हैं। पर इस तरह की बातें इस सदन में बैठकर कहने से बचने की हमें कोशिश करनी चाहिये।

मेरे जवान दोस्त हैं, जयेन्द्रसिंहजी। उन्होंने एक मिनिस्टर के बारे में यह कहा कि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्युएन्सी में कूए बनवा दिये। यह अलवर कॉन्स्टीयुट्एन्सी के बारे में हैं। उनसे मेरा यह कहना है कि कूए खुदवाना पी.डब्ल्यू.डी. का काम नहीं है; यह तो इरीगेशन का काम है और इरीगेशन का काम

[श्री जयनारायण व्यास]
जिसके हाथ में है वे डूंगरपुर के रहने वाले हैं, अलवर के रहने वाले नहीं हैं; यह जो कूए व पम्पिंग सेट्स आदि है उनका ताल्लुक नहीं। यह १६५१ में, जब मैं चीफ मिनिस्टर था, उससे पहिले तय हुए हुए हैं। हुक्म की देरी से तामील होती है। उस वक्त तामील नहीं हुई। अब उनकी तामील हो रही है। उनको यह ध्यान होना चाहिये कि वह पी.डब्ल्यू.डी. के मेम्बर की कांसटीटयुएन्सी की चीज नहीं इरीगेशन की चीज है। कुए खुद रहे हैं और किस कॉन्स्टीट्एन्सी में खुद रहें हैं इस बात की उनको तकलीफ हो रही हो तो उनको उस तकलीफ को निकाल देना चाहिये और अगर कुए खुद जाने की तकलीफ हो तो उनको बरदाश्त करना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह तकलीफ शायद उनके लिये बरदाश्त करने योग्य है।

एक बात जो कही गई वह खास तौर से बहुत जिम्मेदार व्यक्ति, श्री जसवन्तसिंहजी की तरफ से कही गई कि प्लॉटस् बेचने में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। दूसरे साहब ने कहा कि प्लॉट्स जो १००) रुपया प्रतिगज के हिसाब से बेचे जा सकते थे उनको छः रुपया गज दे दिया गया। मैंने यह देखने की कोशिश की कि दरअसल मामला क्या है? मैंने देखा कि कहीं प्लॉट बेचने का नाम लेकर कोई नया प्लॉट तो नहीं रचा जा रहा है। मैं यह नहीं मानता कि मिनिस्टरों से गलती नहीं हुआ करती। होती है, मैंने देखने की कोशिश की, अध्यक्ष महोदय, कि मिर्जा इस्माईल के जमाने में, श्री वी. टी. कृष्णमाचार्य के जमाने में, पीछे हम लोगों के आने पर भी प्लॉट्स बेचे गये उनके भाव मैंने देखे; चार आने, आठ आने एक रुपया दो रुपया, चार रुपया प्रतिगज के हिसाब से बेचे गये। १४) रुपया बड़ी से बड़ी रकम है। उसमें बड़े बड़े लोग भी थे जिनको एक रुपया गज मिला। जिन लोगों ने उन दिनों प्लॉट्स लिये थे उनमें प्रति एकड का प्टलॉस् पांच हजार रुपये का मिला है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई में ४८४० वर्ग होती है। पांच पांच हजार में ४८४० वर्ग के प्लॉट बिके थे। वह अच्छी बात थी। उस समय इसको बसाना था। बाद में जब ये मिनिस्टर आये तो इनके जमाने में जो प्लॉटस दिये गये थे वह उसी रेट्स के अनुसार थे जैसे कि रेट्स डेवलपमेन्ट ट्रस्ट ने कायम किये थे; उससे कम किसी से नहीं लिये गये। आज जिन प्लॉटों के लिए कहा जाता है कि वे १००) रुपये गज के भाव से बिक सकते थे आज यदि हम अपोजिशन में बैठे हुए हों तो हम भी कह सकते हैं कि वे लाख रुपये में बिक सकते हैं; यह एक जबानी कल्पना है। फैक्टस् के उपर क्रिटिसिज्म करें तो न्याय संगत होगा। यह जो प्लॉटस बिके हैं डेवलपमेन्ट ट्रस्ट के निश्चय के अनुसार ६),७), रुपया प्रतिगज के हिसाब से बेचे गये हैं। सेठ साहूकारों को और जागीरदारों को डेढ़ रुपया गज या एक रुपया गज में प्लॉट मिल गये और डाक्टरों को और दूसरे लोगों को चार रुपया प्रति गज के हिसाब से मिले हैं और जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनको साढ़े छः रुपया गज के हिसाब से प्लॉट दिये गये। अगर हम इस तरह से प्लॉट बड़े बड़े आदमियों के लिए रिजर्व कर दें तो अन्याय होगा। इससे मध्यम श्रेणी के लोगों का भला नहीं हो सकता।

अभी एक बात सदन के सामने यह कही गई कि कई जगहों से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वाटर्स हटाये जा रहे हैं और उनके हटाने में भी पक्षपात से काम लिया जारहा है मुझे मेरे उन साथियों से ऐसी बातें सुन कर बड़ा आश्चर्य होता है, जो मेरे साथ रहे हुए हैं और जिन्होंने हमें देखा है। इसके लिये मैं यह कहूंगा कि यह बात सही है कि कई जगहों से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वाटर्स हटाये

[श्री जयनारायण व्यास]

जा रहे हैं । लेकिन इस संबन्ध में मैं यह बतला देना चाहता हूं कि इस संबन्ध में पहले एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी की सिफारिश के अनुसार ही हेडक्वाटर्स हटाये जा रहे हैं। अभी मेरे एक मित्र ने शाहपुरा से हेडक्वाटर्स उठाने का जिक्र किया है और कहा कि किसी को खुश करने के लिए वहां से हेडक्वाटर्स हटाये जा रहे हैं । इसके बारे में मैं थोडासा स्पष्टीकरण करना चाहता हूं :

१६५१ में जब पहले व्यास चीफ मिनिस्टर नहीं था उस वक्त मि० डे को सरकार ने इस काम के लिये नियुक्त किया था । उन्होंने सब जगह जा कर देखा और अपनी राय देना शुरू किया । १६५१ के जून में जब न तो कोई अखबार निकलता था, न व्यास मिनिस्टरी ही थी, उस समय १८ ऑफिसरों की एक कमेटी इसके लिये बैठी थी; जिसमें कलेक्टर, कमिश्नर, एस.डी.ओ., पुलिस के अफसर, जेल के अफसर, पी.डब्ल्यू.डी. के अफसर, रेवेन्यू के अफसर आदि थे ; जिन्होंने बैठ कर यह तय किया था । उन्होंने यह तय किया कि जहां पर जेल के लायक जगह नहीं हो, हेडक्वाटर्स के लायक जगह नहीं हो, वहां से हेडक्वाटर्स हटा दिये जाने चाहिये ।

सितम्बर १६५१ में यह तय हुआ था कि शाहपुरा हेडक्वाटर्स के लिये उपयुक्त स्थान नहीं है और यहां से हेडक्वाटर्स हटा दिया जाए । यह तय हो गया था सितम्बर १६५१ में ही; मगर चुनावों के कारण उस समय इसको नहीं हटाया गया क्योंकि वह इलेक्शन का हेडक्वाटर भी था ।

फरवरी ,१६५२, में यहां से हेडक्वाटर को हटाने का आर्डर हुआ; मगर किसी तरह से वह आर्ड़र कार्यरूप में नहीं आया और वह नहीं हट सका। नवम्बर १६५३ में जब मैं चीफ मिनिस्टर होता हूं और मैं कार से जाते हुये वहां के लोक-अप को देखता हूं तो वहां ६ फु०-१०फु०. के कमरे में १६ आदमियों को बन्द पाता हूं। मुझे खयाल आया कि यहां से तो हेडक्वाटर्स हटाने की बात थी, फिर यह अभी तक क्यों नहीं हटाया गया । यह वहां के लोक-अप की हालत है। मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि वहां पर एक दफे १७ आदमी और उसके पहले १० और उसके पहले २६ आदमी तक रखे गये थे । कैदियों को इस प्रकार एक छोटे से कमरे में बन्द रखा जाए ,इस बात को मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता । क्या आप यह पसन्द करेंगे कि कोई भी सभ्य सरकार ६० वर्ग फु० के कमरे में १६-१६ तथा १६ आदमियों को बन्द करे । क्या आप इस बात का समर्थन करने को तैयार हैं? जब यहां पर उपयुक्त जगह ही नहीं तो फिर इस चीज को सदन के सामने कहना कि किसी को खुश करने या पोलिटिकल एम (aim) पूर्ति के लिये यह कार्य किया गया है; ऐसी बदनामियों को सदन बर्दाश्त नहीं करेगा । यदि आप किन्हीं फेक्ट्स पर आलोचना करें तो ठीक होगा, वरना यह कोई अच्छी बात नहीं है ।

मुझे वक्त ज्यादा लेना चाहिये; मगर मैं आपका वक्त ज्यादा न लेकर कोशिश करूंगा कि जो कुछ मुझे कहना है उसे संक्षेप में ही कह कर समाप्त कर दूं ।

एक चीज जो चारों कोनों से कही गई वह राजपूत जाति के सम्बन्ध में थी। जिस वक्त वे बातें कही जाती थीं उस समय मुझे ऐसा मालूम होता था कि कांग्रेस और कांग्रेस के लोग और कांग्रेस की यह

[श्री जयनारायण व्यास]

सरकार राजपूत जाति के पीछे पड़ी हुई है और उसने इनको तबाह करने का बीड़ा उठा लिया हो इस प्रकार की हमारी जो भावना है, मैं समझता हूं कि उसको खतम करना चाहिये । ऐसी बातें न हमारे दिमाग में हैं और न आपके दिमाग में होनी चाहिये । मैं तो यह कहूंगा कि राजपूत जाति जो एक कीमती जाति है और जिससे काफी देश की सेवा कराई जा रही है और जिसने देश की काफी सेवायें की थीं वह इस वर्ग के, जो शासन कर रहा है, दोस्त के लायक है । आप इस वर्ग से राजपूत जाति को अलग करने की कोशिश न करें । मैं इसके लिये आपसे अपील करूंगा । इसी में इस देश को फायदा है । राजपूत जिन्दा रहेंगे, जाट जिंदा रहेंगे और कांग्रेस जिंदा रहेगी; हमारे थोड़े से अलग अलग विचार हैं वे भी रहेंगे । कभी कभी कुछ टक्करें भी होंगी पर यह प्रयास करना चाहिये इस राजपूत जाति को दूसरे वर्गों से, पोलिटिकल वर्गों से दूर नहीं किया जाय क्योंकि उन वर्गों से राजपूत जाति को ज्यादा फायदा है । मैं अपील के तौर पर विरोधी दलके नेता और दूसरे सज्जनों से अर्ज करूंगा कि वह राजपूत जाति को दूसरे वर्गों से अलग करने की कोशिश न करें ।

अब मैं कुछ शब्द कृषि के बारे में कहूंगा । कृषि-उन्नति कार्य का राजप्रमुख के भाषण में काफी उल्लेख था; लेकिन यह होते हुए भी जगह जगह से एतराज आये कि उन्होंने जमीन फालतू रखी है । माननीय जसवन्तसिंहजी ने भी कहा कि गंगानगर जिले में हजरों बीघा जमीन बेकार पड़ी है । मैं कहता हूं कि बेकार नहीं है, जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है एक्स-सोल्जर्स को जमीनें दी गई हैं, रिफ्यूजीज को भी जमीनें दी गई हैं । गंगानगर की जमीन स्विच लगाकर नई नहीं पैदा की है, गंगासिंहजी के जमाने की है । थोड़ी सी जिम्मेवारी हमारी है और आपकी भी है ।

श्री जसवन्तसिंह—वह जमीन अब बेकार हुई है, पहले बेकार नहीं थी ।

श्री जयनारायण व्यास—एक्स-सोल्जर्स भी गंग केनाल की जमीन को लेंगे और रिफ्यूजीज भी लेंगे । एग्जेक्ट फीगर्स तो मैं नहीं दे सकता ।

श्री जसवन्तसिंह—आपने जो बात कही वह सही नहीं है ।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—जंगल काटने की बाबत बातें कही गई है इसके लिए एक्शन लिया जायगा । सरकार की इच्छा नहीं रहते हुए भी लोग जंगलों को काट देते हैं । लेकिन सरकार की यह इच्छा कैसे हो सकती है कि पूरे के पूरे जंगलों को काट कर सारे के सारे राजस्थान को रेगिस्तान बना दिया जाय । ऐसी बात नोटिस में आएगी तो एक्शन लिया जायगा । जंगल नहीं काटने का कानून बना हुआ है । मुझे मालूम है कि कई जागीरदारों नें जंगल काटे हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि जागीरें रहेंगी या नहीं । मैंने उनको मना किया कि ऐसा क्यों करते हो, इससे क्या होगा ?

तो इस तरह जंगल काटने के बाबत जब शिकायत आयेगी तो एक्शन लिया जायगा ।

श्री जसवन्तसिंह—हमें शिकायत है ।

श्री हिम्मतसिंह—दौरे में जाते हैं तब आप भी देखते ही हैं ।

श्री जयनारायण व्यास—शिक्षा के बारे में कहा गया है कि ध्यान नहीं दिया गया । मैं भी मानता हूं कि हम इन दिनों में आर्थिक कठिनाईयों में जरूर आये हैं लेकिन शिक्षा के लिये हमारी तवज्जो तो है; पहले से ज्यादा खर्चा करते हैं। मैं आपको सूचना दे दूं की अगले साल प्राइमरी शिक्षा के लिये हमारा २० लाख का बजट है फिर २४ लाख का होगा और धीरे धीरे हम शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेंगे ।

माननीय चिमनसिंहजी ने कहा कि २७० गांवों के लिये एक होस्पिटल है। (विपक्ष की ओर से आवाज आई, "चिमनसिंह कोई नहीं है") चिमनसिंहजी नहीं तो चतरसिंहजी होंगे। २७० गांवों के फासले से होस्पिटल हो सकता है और नहीं भी; इस पर हमें बैठ कर विचार करना है । होस्पिटल नहीं होंगे तो हमें आयर्वेदिक एड-पोस्ट से मदद लेनी होगी ।

श्री चतरसिंह—यह बात मैंने नौखा मंडी के लिये कही थी ।

श्री अध्यक्ष—You have given credit to another man.

श्री जयनारायण व्यास—शांति और व्यवस्था के बारे में पालीवाल जी ने कह ही दिया है । उन्होंने कहा कि उक्त सूचनायें कभी पूरी की पूरी सही भी नहीं हो सकतीं। मैं इसमें एड कर देना चाहता हूं कि सही भी होती हैं और साबित नहीं हो सकती। खतरे को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिये; जब तक इन्सान के मरने-जीने का सवाल लॉ एण्ड ऑर्डर में आ जाता है ।

एक शब्द में आबू के बारे में कह देना चाहता हूं। सब जानते हैं कि आबू के बारे में हम चिन्तित हैं। एक कमेटी बनी है, उसमें कोई पोलिटिकल पार्टी के मेम्बर नहीं हैं, बिलकुल विद्यार्थियों की है। अगर कोई यह चाहता हो कि आबू के लिये हम मिलिट्री एक्शन कर दें तो यह तो हम नहीं कर सकेंगे और अगर कोई यह चाहता हो कि जिस तरह हम कांग्रेस में प्रोसेशन ले कर जाते थे उस तरह प्रोसेशन लेकर जायं तो हम यह कभी भी नहीं करेंगे। परन्तु हम पूरी कोशिश करेंगें, आबू लेने की और हम आबू लेकर रहेंगे। (करतल ध्वनि)

एक भ्रम लोगों में फैला हुआ है कि राजस्थान पर आर्थिक संकट आगया है, नौकरों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, बड़ी गड़बड़ी हो जायगी। मैं आर्थिक स्थिति पर बोलने के समय इस बात पर खुलासे से बोलूंगा। आर्थिक संकट जरूर है पर इसे हम इस तरह हल नहीं करना चाहते कि जो हमारे पास है उसको बेच दें, कोट भी बेच दें, पेंट भी बेच दें। मेरे साथी कहते हैं कि १७ करोड़ सिक्युरिटी के आपके पास मौजूद थे उनका क्या हुआ। उनको मैं इतला कर दूं कि १७ करोड की नहीं १३ करोड सिक्यूरिटी थी, वह यों की यों पड़ी हुई है।

श्री एच. के. व्यास—Question, Sir..........

श्री अध्यक्ष—Order.

श्री जयनारायण व्यास—इस तरह १३ करोड सिक्यूरिटी को खत्म कर दें; यह तो ठीक नहीं। जिस समय हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ था तो भारत सरकार ने मंजूर किया था कि जो हमको आवश्यकता होगी, दो साल के बाद में जांच करके उसकी पूर्ति करेंगे। अब दो साल पूरे हो गये तो हमारा फर्ज है कि हम भारत सरकार से कहें कि आप इसकी जांच करें और हमारी मदद करें। फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट आई है। उससे जाहिर है कि मदद करने के कारण हैं। मुझे अफसोस नहीं कि रेलवे हमारे पास नहीं रही, मुझे अफसोस नहीं कि सांभर साल्ट की आमदनी चली गई, आगे जा कर हमारी कस्टम ड्यूटी है वह भी चली जायगी।

इसका भी मुझे अफसोस नहीं है कि हमारी एक्साइज ड्यूटी कम होजाय। हम फिर ड्यूटी लगावेंगे। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे; यह बाद की बात है। यह बात जरूर है कि जब सारी आमदनी का जरिया केन्द्र को दे दिया गया है तो उन जरियों के हिसाब से जो कुछ अर्थ हमको हमारी आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिए मिलता है तो अवश्य मिलना चाहिए और इस बात को केन्द्र भी मानता है। केन्द्र तो इस बात को माने और हमारे मित्र लोग कहें कि रेलवे के मुआवजे के बारे में कुछ नहीं होना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि यह बात अनपेट्रियोटिक है, अपने ही लिए खतरनाक है। हमें केन्द्र से अवश्य ही मदद मिलनी चाहिए और मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि आप लोगों को मेरी इस में मदद करनी चाहिए; ताकि सरकार अच्छी तरह से चल सके। मैं आपको बताऊं, और श्री जसवन्तसिंहजी भी जानते हैं कि महाराजा गंगासिंहजी ने राउन्ड टेबल कॉन्फ्रेन्स के वक्त कहा था कि रेलवे को सेन्टर में जाने दिया जाय। उन्होंनें कहा था कि "State and Intra State Railways should remain with province in order to enable them to develop themselves."

श्री जसवन्तसिंहजी—यह थीम तो दूसरा था।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—यह थीम दूसरा ही हो। किन्तु मेरा कहना यह है कि पेट्रियोटिज्म रहना चाहिए।

श्री जसवन्तसिंह—अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेट्रियोटिज्म के लिये कहा है, अत:.......

श्री अध्यक्ष—When the Hon'ble speaker does not yield, I cannot allow.

श्री जसवन्तसिंह—But can he make allegations?

श्री अध्यक्ष—There are no allegations.

श्री जसवन्तसिंह—He calls unpatriotic.

श्री अध्यक्ष—He says to the House that it will unpatriotic. The Leader of the House has said that the House will be unpatriotic.

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूं कि हमारे समझने में थोड़ी गलती हुई है। हम केन्द्र से रुपया मांग रहे हैं और उसके लिए यह कहा जाय कि वह न मिले, तो इसी भावना से मैंने यहां यह बात

[श्री जयनारायण व्यास]

कही है और इस विषय में मेरी और कोई भावना नहीं थी। यदि इससे मेरे साथी को दुःख पहुचा हो तो मुझे इस बातका खेद है। मेरी तो भावना यही है कि हमें हमारे डेवलपमेन्ट के लिए केन्द्र से पैसा मिले।

मुझे बहुत सारी बातें कहनी थीं, किन्तु सवा छः बजने वाले हैं, अतः में बहुत सारी बातें नहीं रख सकूंगा। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बहुत सारे सुझाव रखें हैं और जो लाभप्रद हैं। मैं श्री जसवन्तसिंहजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत कुछ कमेटियों के निर्माण के बारे में सुझाव रखे हैं। कुछ कमेटियाँ हमने बनाई हैं और कुछ कमेटियां, मैं विश्वास दिलाता हूं कि, इस सेशन में ही बना दी जावेंगी और वे भी उनकी सलाह से बनाई जावेंगी। वैसे मैंने उनकी सलाह ली भी है। एक यह सुझाव दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट छपनी चाहिएं। जो पुराना तरीका एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट छापने का था वह तो अब रहा नहीं है। फिर भी हमको जो सूचनाएं मिली हैं उनके प्रकाशन की व्यवस्था हुई है और आगे भी होती रहेगी; यह मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं।

नमक और ऊन के व्यापार और उद्योग के विकास के लिए डॉक्टर मंगलसिंहजी ने जो बातें कही हैं में उनको स्वीकार करता हूं और मैं आपको यह सूचित कर दूं कि सरकार द्वारा एक एक्सपर्ट अफसर, नियुक्त कर दिया गया है जो यह देखेगा कि कुम्हेर आदि स्थानों में नमक बन सकता है या नहीं, उससे आमदनी हो सकती है या नहीं, उससे नफा होगा या नुकसान। इस सम्बन्ध में जांच हो रही है और यह बात सरकार के ध्यान से बाहर नहीं है।

इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं माइन्स के बारे में आपको कुछ कहना चाहता हूं। माइन्स के बारे में प्रश्नोत्तरों के समय साफ कर दिया गया था। मेजर माइन्स, माइनर माइन्स और पर्सनल माइन्स; ये तीन प्रकार की माइन्स, मेरे खयाल से कही जा सकती हैं। मेजर माइन्स भारत सरकार के नियन्त्रण में होती हैं। माइनर माइन्स को हम वर्क आउट करते हैं और उसमें भी कुछ पर्सनल फेक्टर आजाता है। कुछ लोगों की माइन्स में रुचि है। इन पर्सनल मामलों में तो मेम्बर्स को और मुझे नहीं पडना चाहिए। मैं, मेजर माइन्स के मामलों में, मानता हूं कि हमको भारत सरकार से कुछ तय करना पड़ेगा क्योंकि ये माइन्स उनके नियन्त्रण में होने से उनसे हमको कभी कभी नुकसान होता है। लोग माइन्स और ट्रान्सपोर्ट के बारे में यह कहते हैं कि पहले तो इनसे फायदा होता था और अब क्यों नहीं होता है? पहले का सिस्टम ही फिर क्यों नहीं लागू रहने दिया जाता है? अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में यह कहना है कि पहले मोनोपोली सिस्टम था, एक आदमी को मोनोपोली दे दी जाती थी और उससे फायदा भी होता था। किन्तु भारत के संविधान में "मोनोपोली" हटा दी गई है। ट्रान्सपोर्ट में मोनोपोली से फायदा नहीं उठाया जा सकता है और यह हमारे लिए दुर्भाग्य है और देश के लिए भी दुर्भाग्य है। अब अच्छा तरीका चालू हुआ है और वह धीरे धीरे (adjust) हो जायगा।

एक बात और कहकर मैं खतम कर दूंगा; क्योंकि वक्त से ज्यादा जाना मैं नहीं चाहता। वह यह कि एक इशारा यह किया गया था कि हमको, पाकिस्तान के बारे में, कि हमें उसके वार के लिए भी

[श्री जयनारायण व्यास]

तैयार रहना चाहिये । मेरा ऐसा खयाल है कि हमें इस तरह का अपना खयाल इस सदन में नहीं प्रकट करना चाहिये। वैसे यह केन्द्र का विषय है ।

(आवाजः "यह भी अनपेट्रियोटिक है, ऐसा कह दें")

इसके बारे में मैं कुछ न कह कर जो है वह समझ लेता हूं। I consider what it is worth.

अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने सदन के सामने मुझे अपने भाव व्यक्त करने का मौका दिया । यद्यपि मुझे जो कुछ कहना था वह मैंने कहा क्योंकि क्रिटिसिज्म का जवाब मुझे देना था इसलिए मैंने भी इसी रूप में बहुत कुछ कहा। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथी, कुं० जसवन्तसिंहजी, को मेरी कुछ बातें बुरी लगी । मुझे इसका दुःख है और यह मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मेरी कभी भी मन्शा यह नहीं रही और न यह है कि मैं किसी भी व्यक्ति के दिल को दुखाऊं । फिर मेरे दिल में इनके दिल को दुखाने की बात आही नहीं सकती । हां, जो कुछ क्रिटिसाइज किया गया था उसका जवाब देना मेरा हक था और वही मैंने किया है। हम एक खेल खेल रहे हैं। खेल कई तरह के होते हैं और खिलाड़ी भी कई तरह के । हम राजनीति का खेल खेल रहे हैं । एक इस साइड में है और एक उस साइड में है । हमें यह खेल खेलते हुए भी स्पोर्टसमैन स्पिरिट ही बतानी चाहिये । मुझे कतई दुःख नहीं है कि मेरे बारे में कुछ भी कहा गया हो । यह तो भुखमरिया है, जिनका चित्त प्रसन्न है । मैं तो यही मानता हूं कि जो तकलीफ में भी प्रसन्न रह कर कर्तव्य करेगा वह संसार में कामयाबी हासिल करेगा। हमें पोलीटिक्स का खेल खेलना ही है और इस खेल में हमें हमेशा स्पोर्टस् मैन स्पिरिट बताना है ।

यही प्रार्थना अन्त में करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बिना विरोध के इस एड्रेस पर एक मत से धन्यवाद के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और जो संशोधन है उसे वापस ले लेंगे। यही मैं अर्ज करना चाहता हूं ।

संशोधन वापिस ले लेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा ।

(करतल-ध्वनि)

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मेरे मित्र व्यास जी ने जो एक चीज बताई इस हाउस में, उससे एक गलतफहमी पैदा हो गई है । इसके संबन्ध में दो शब्द कह देना चाहता हूं ।

मैंने एक ऐसी चीज रक्खी थी कि जिसके लिए अपोजीशन को एप्रीशियेट करना चाहिये। पर मुझे खेद है कि मेरे अमेन्डमेन्ट को पढ़ा तक नहीं गया है । अगर पढ़ लेते तो यह बात नहीं कही जाती । उसमें मैंने लिखा हैः

"but respectfully beg to point out that the advice given by the Raj Pramukh to the House about the successful working of democracy is the very anti-thesis of real democracy; and that he has omitted to advise the

majority party to have the greatest regard for the feelings and views of the minority, and that he has failed to make use of the opposition and other sources available to him to make sure that whatever material was placed before him by the Government for his address to the Assembly is the whole truth."

मुझे खेद है कि जो लिखित चीज है उस पर गलतफहमी पैदा हो सकती है तो उनके जो भाषण हुए हैं उनमें कितनी सच्चाई होगी ।

श्री जयनारायण व्यास—मैं तो यह कहता हूं कि:—He should treat these things in the spirit of laws of game; press hard, push hard, kick hard. I do not bother about that, but observe the rules of the game.

श्री अध्यक्ष—(श्री गोपीलाल यादव को सम्बोधित करते हुए) You want to put it to vote.

श्री गोपीलाल यादव—जी, हां ।

श्री अध्यक्ष—So I read the amendment. First, the main motion is this:—

"That the members of the Assembly assembled in this session are deeply grateful to H. H. the Rajpramukh for the address which he has been pleased to deliver to the House."

And after this Shri Gopi Lal Yadav wants to add—

"but respectfully beg to point out that the advice given by the Rajpramukh to the House about the successful working of democracy is the very anti-thesis of real democracy, and that he has omitted to advise the majority party to have the greatest regard for the feelings and views of the minority, and that he has failed to make use of the opposition and other sources available to him to make sure that whatever material was placed before him by the Government for his address to the Assembly is the whole truth."

(विराम)

The question is "That the amendment motion be accepted."

(अस्वीकृत)

The motion fails.

(विराम)

Now we come to the main motion.

The question is "That the motion of thanks be accepted."

Page No.74

(स्वीकृत)

The motion is accepted.

Now before we disperse, I want to give one information that the Hon'ble Members can collect those papers from the Notice Office which have not been delivered to them.

(विराम)

We now adjourn for tomorrow to meet at 2 p. m.

(सदन की कार्यवाही ६–१५ सायं को, दिनांक १७–२–५३ के २ बजे मध्याह्न तक के लिये स्थगित हुई।)

सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक १६ फरवरी १९५३ ई.

एम० आर० पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या १०४ के उत्तर का शेष भाग जो सदन की मेज पर रखा गया)

उपरोक्त योजनाओं में से गंगापुर, हिन्डोन में बीज वितरण के लिये गोदाम बनाये जायेंगे जिसमें प्रति गोदाम में निम्न खर्चा होगा:—

गोदाम के बनाने का खर्च	१५०००
कीमत बीज	२००००
स्टाफ, चौकीदार आदि	५५०
	३५५५०

इसके अतिरिक्त दूसरी योजनाओं में से भी आवश्यकतानुसार इन दोनों जिलों में खर्चा किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त हिन्डोन सब-डिविजन में एक विकास योजना ब्लॉक में कार्य जारी है जिसके आधीन २२ लाख रुपये तीन वर्ष में खर्च होंगे।

Page No.76

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सहकारिता व ग्राम निर्माण कार्य
सब-डिस्ट्रिक्ट हिंडौन व गंगापुर (राजस्थान)

सहकारी विभाग

ग्राम	सन्	सहकारी शिक्षा	सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता ।
सब-डिविजन	५१-५२	३००) ट्रेनिंग सहायक इन्सपेक्टर	१०००)
हिंडौन	५२-५३	६२०) ट्रेनिंग सहायक इन्सपेक्टर व ऑडीटर	विचाराधीन

ग्राम पुनर्निर्माण विभाग

,,	५१-५२	४१०६) ग्राम सुधार कार्य केन्द्र पटोंदा
	५२-५३	४००२) ,,
	५३-५६	५०४००) ,,

सहकारी विभाग

सब-डिविजन	५१-५२
गंगापुर	५२-५३

ग्राम पुनर्निर्माण विभाग

,,	५१-५२	अर्थाभाव से इस सब-डिस्ट्रिक्ट में ग्राम सुधार केन्द्र नहीं है ।
	५२-५३	..
	५३-५६	..

परिशिष्ट २

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो प्रश्न-समय में नहीं लिये गये और सदन की मेज पर रखे गए)

२०५ (6/Dy. C.M.) Will the Home Minister be pleased to state--

(i) What is the Division-wise monthly institutions of cases and police challans for the contravention of Food Consumption order ;

(ii) Is the Minister aware that more than 75 p. c. genuine cases are neglected by the police because they are tipped and only the poor are dragged to courts ?

(iii) Is the Government taking some early decision to declare such contraventions as non-cognizable when many other big and small states have altogether removed or relaxed to a great extent such restrictions ?

(iv) When should that be expected ?

उत्तर—

(i) A statement showing the monthly institution of cases for the contravention of Food Consumption Control Order and police challans in each Range for 1952 is enclosed herewith.

(ii) No instance has so far come to notice where the police neglected genuine cases as a result of their having been tipped. They have instructions to treat Rich and Poor alike.

(iii) The matter is under the consideration of Government.

(iv) Decision will be announced shortly.

Page No.78

सन् १९५२ में फूड कन्जम्प्शन कन्ट्रोल आज्ञा के अन्तर्गत निर्धारित किए ग, अभियोगों का मासिक क्षेत्रानुसार विस्तृत विवरण

माह	जयपुर क्षेत्र निर्धारित	जयपुर क्षेत्र चालान किए गए	कोटा क्षेत्र निर्धारित	कोटा क्षेत्र चालान	उदयपुर क्षेत्र निर्धारित	उदयपुर क्षेत्र चालान	बीकानेर क्षेत्र निर्धारित	बीकानेर क्षेत्र चालान	जोधपुर क्षेत्र निर्धारित	जोधपुर क्षेत्र
जनवरी	२२	६	३	३	४०	२८	३	३	३	१
फरवरी	३५	१०	३	२	३४	२४	१	१	५	५
मार्च	३१	१६	३	२	३१	२४	–	–	८	८
अप्रल	२६	१४	४	४	६१	४३	७	७	[illegible]	[illegible]
मई	२१	१२	५	३	५६	४०	१	१	१	१
जुन	२०	९	–	–	२९	२३	–	–	३	३
जुलाई	२५	१७	–	–	२०	१८	–	–	–	–
अगस्त	१८	९	१	१	३७	२७	–	–	२	[illegible]
सितम्बर	१०	६	१	१	२२	१८	४	४	१	[illegible]
अक्तूबर	१०	८	१	१	३४	२२	–	–	१	[illegible]
नवम्बर	११	६	३	२	१९	१२	१	१	२	[illegible]
दिसम्बर	७	६	–	–	३१	२२	१	१	१	–
योग	२३६	११९	२४	[illegible]	४१४	३०१	१८	१८	[illegible]	[illegible]

सन् १९५२ में कुल निर्धारित एवं चालान किए गए

....

अभियोगों की संख्या

क्षेत्र	निर्धारित	चालान किए गए
जयपुर	२३६	११९
कोटा	२४	१९
उदयपुर	४१४	३०१
बीकानेर	१८	१८
जोधपुर	३१	२७

उपरोक्त विवरण में भरतपुर सवाई माधोपुर एवं झुंझुनू जिलों म निर्धारित एवं चालान किए गए अभियोगों की संख्या सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि इन जिलों मे हुए उपरोक्त अभियोगों की मासिक सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं ह। इन जिलों में सन् १९५२ में निर्धारित एवं चालान किए गए कुल अभियोगों की संख्या क्रमशः १४ एवं ९; इस प्रकार जयपुर क्षेत्र म सन् १९५२ में चालान किए गए अभियोगों की संख्या २५० है तथा निर्धारित की १२८ है।

१०६. (२६-ए./पी. डब्ल्यू.एम.) श्री भवानी सहाय शर्मा, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर ५—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

अजबगढ़ से प्रतापगढ़ वाली सड़क की हालत कैसी है? इस सड़क की मरम्मत कब हुई थी और उस मरम्मत में कितनी रकम ठेकेदारों को अदा की गई थी?

उत्तर—

यह एक कच्ची पहाड़ी सड़क है और इसकी दशा अच्छी नहीं है। मरम्मत इस विभाग द्वारा करवाई गई है और १४०० रु. आर्थिक वर्ष सन् १९५०-५१ में खर्च हुये हैं व सन् १९५१ व ५२ में और ५२-५३ में मरम्मत में ८०० रुपये (४००+४००) खर्च हुये हैं।

१०७. (३० पी. डब्ल्यू. एम.) श्री भैरूंसिंह, डिविजन नम्बर १६—क्या पृथक राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(अ) राजस्थान से सन् १९५०, १९५१, १९५२ म कितन कितने मादा पशुओं (भेड़, बकरी, गाय) की निकासी हुई?

(ब) इस निकासी से सरकार को क्या क्या आमदनी हुई?

(स) क्या सरकार को मालूम है कि इस निकासी से राजस्थान की कृषक जनता को काफी हानि होती है?

(ड) यदि हां, तो क्या सरकार मादा, (भेड, बकरी, गाय) पशुओं की निकासी रोकने के आदेश प्रदान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर—

(a) The figures of export of Sheep, She-goats and Cows in the years 1950-1951; 1951-1952 and 1952-53 (up to October, 1952) are as under.

		Animals exported.	
Year.	*Sheep.*	*She-goats.*	*Cows.*
1950-51.	22,184.	2,38,830.	49.
1951-52.	16,707.	1,68,506.	26.
1952-53. (upto Oct. 52)	5,564.	72,822.	30.

(b) The revenue derived on this account is as under.—

Revenue earned by export duty on animals.

Year.	*Duty on Sheep.*	*She-goats.*	*Cows.*	*Total.*
1950-51	66,605	7,10,558	264	7,77,427
1951-52	49,616	5,05,187	239	5,55,042
1052-53 (upto Oct. 52)	14,732	2,18,588	301	2,33,621
Total	1,30,953	14,34,333	804	15,66,090

(c) The Government does not agree that this export is harmful to the cultivators. Rajasthan is an area where sheep, she goat and cattle are reared in abudance and the export of sheep and she-goat has been going on for ages and still no dearth of these animals has been experienced and this is not affecting the country in any way, rather a continual flow of these animals is advantageous, specially because the cattle rearers who have this profession as their main stay get the advantage and the country does not lose.

(d) In view of the reasons explained above there is no idea to ban the export of sheep and she-goat. The export of cow is banned and it is only under special permits that cows are allowed to be taken out of Rajasthan. The number of cows shown here as exported will show that these cows have been allowed mostly on the transfer of Railway servants working in the Railways within Rajasthan State or given in dowery.

108. (14F.M.) Shri T.M. Bapana M. L. A. (Div. No. 149) Will the Education Minister be pleased to state—

(i) What is the number of students in Middle School, Pur (District Bhilwara) and what is the accommodation?

(ii) Is that accommodation sufficient?

(iii) If not, will the Government get some rooms constructed from the next year's budget?

उत्तर-

१. मिडल स्कूल, पुर में छात्र संख्या २६० है व कमरे ३ हैं ।

२. इसके लिये यह स्थान अपर्याप्त है ।

३. यह मामला विचाराधीन है, किन्तु फिर भी फन्ड्स पर निर्भर है ।

Page No.81

१०६ (२४/एफ. एम.) **श्री भोपालसिंह, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर २०**—क्या शिक्षा मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे —

क्या मेड़ता तहसील के पालड़ी नामक ग्राम म जहां स्कूल का मकान व अध्यापकों के निवास-स्थान ठिकाना पालड़ी ने बना दिये हैं और जहां १८० लड़के पढ़ते हैं सरकार मिडिल स्कूल खोलन का प्रबन्ध करेगी ?

उत्तर—

इस ग्राम में मिडिल स्कूल खोले जाने की आवश्यकता को दृष्टिकोण में रखते हुए तथा सरकार की आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे अन्य स्कूलों के मामलों के साथ इस विषय पर विचार किया जावेगा।

110. (7/Dy. C. M.) Shri T. M. Bapna, M.L.A. (*Div. No.* 119) Will the Home Minister be pleased to state :—

(*i*) Is the Government aware of corruption and nepotism prevailing to a great extent in Police employees in Rajasthan in general and Bhilwara District in particular?

(*ii*) How many complaints were made against Police Officers in Bhilwara District within last three years? How many of them were investigated and with what results?

(*iii*) What early special measures are being taken by Government to check such corruption and nepotism?

उत्तर—

(क) यद्यपि यह दावा नहीं किया जा सकता कि सब के सब पुलिस कर्मचारी भ्रष्टाचार से विमुक्त हैं, तथापि ऐसी धारणा कि भ्रष्टाचार व कुल पक्षपात पुलिस कर्मचारियों में ही अधिकतया पाया जाता है, न्यायसंगत न होगी।

(ख) १९. इन सब में जांच की गई, ९ झूंठे प्रमाणित हुये, ६ में पुलिस कर्मचारियों को दन्ड दिया गया तथा ४ अभी तक विचाराधीन हैं।

(ग) भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुल श्रेणियों के कर्मचारियों में पुरजोर कार्यवाही की व्यवस्था की गई है। समाचारपत्रों में समय समय पर मौके पर पकड़े गये भ्रष्टाचारी पुलिस कर्मचारियों की गिरफ्तारियों की खबरें छपती रही हैं।

प्रश्न संख्या १११

श्री श्यामलाल—क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे —

कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट की योजना के अन्तर्गत अब तक हिन्डोन ब्लॉक म क्या क्या काय हुआ है ?

उत्तर :—

कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत अब तक हिन्डौन ब्लॉक में जो काम हुए हैं वे निम्न प्रकार हैं—

१. कृषि और पशु पालन में विस्तार

इस क्षेत्र में दिनांक ३१ जनवरी, १९५३ तक खाद के २७८ गड्ढे खोदे गये हैं। ग्रामवासियों को १४० मन गेहूं और ५० मन जौ के अच्छे बीज का वितरण किया गया। इस ब्लॉक के गांवों में कृषकों को एक बोरी एमोनियम सलफेट भी बांटा गया। एक नये प्रकार के चारे के बीज, जिसे 'बरसीम' कहते हैं, का प्रचार किया गया और ऐसा ६ सेर बीज कृषकों को बांटा गया। दिनांक २५ व २६ जनवरी को हिन्डौन में और दिनांक २७ से ३१ तक घोंसला में कृषि विभाग द्वारा कृषि संबंधी प्रदर्शनियां की गई। ग्राम सेवकों द्वारा अच्छे बीज और खाद के लाभ बतलाते हुए चार्ट तैयार किये गये।

२. स्वास्थ्य और ग्रामीण सफाई

महुवा में हाईस्कूल के अहाते में एक छोटा कुआ वहां के मुख्य अध्यापक तथा विद्यार्थियों द्वारा दिये गये श्रम दान से खोदा गया। यहां स्कूल के लड़कों द्वारा स्वेच्छा से किये गये श्रमदान से एक छोटासा बाग भी लगाया गया है। महुवा में दो कुओं की, एक हरिजनों के लिये और दूसरा सामान्य जनता के लिये, गांव वालों के स्वेच्छा से दिये गये श्रम द्वारा मरम्मत की गई। महू में भी एक कुए की मरम्मत की गई। इस अभिप्राय के लिए सरकार ने सीमेन्ट दिया और निर्माण के लिये पत्थर तथा अन्य सामग्री एवं श्रम (दक्ष और अदक्ष दोनों प्रकार का) स्वयं ग्राम वालों द्वारा दिये गये। समूचे घोंसला गांव की पूर्ण रूप से सफाई की गई तथा सफेदी की गई। इस गांव में पानी पीने के एक कुए की भी मरम्मत की गई। इस ब्लॉक में सफाई की प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई है और प्रति तीन महीने में सबसे अधिक साफ सुथरे गांव के लिये एक झंडा पारितोषिक रूप में दिया जाता है। इस बार वह झंडा घोंसला गांव को मिला है।

३. शिक्षा

इस ब्लॉक क्षेत्र में ७ जवाहर बाल मन्दिर (बेसिक स्कूल) खोले गये जिनमें प्रत्येक स्कूल में एक अध्यापक रखा गया है।

४. सामाजिक शिक्षा

मंडावर में जवाहर बाल मंदिर के अध्यापक के प्रोत्साहन से फुटबॉल तथा वॉलीबॉल की एक क्लब खोली गई है। घोंसला में कबड्डी, रस्सा कशी, सबसे अधिक स्वस्थ एवं साफ सुथरे लड़के, सबसे अधिक साफ सुथरे मकान और सर्वोत्तम कामों की प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई है।

५. आने जाने के मार्ग

मंडावर और कराई में गांव वालों के सहयोग से कच्ची सड़कों को साफ किया गया। घौंसला से मुख्य पक्की सड़क तक तीन मील की एक मौसमी सड़क का गांव वालों के सहयोग तथा मूल्य रहित श्रम द्वारा निर्माण किया गया।

गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या गृह मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे –

(क) साल १९५२ में असले के लाइसेन्स के मुताल्लिक जिला गंगानगर में कितनी दरख्वास्तें दी गई, और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(ख) अगर उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

उत्तर –

(क) लगभग ३५००, उनकी जांच हो रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

— —

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १०३ का उत्तर देखिये)

जिला भीलवाड़े में सन् १९५२-५३ में किये जाने वाले पीने के पानी के साधनों के निर्माण एवं प्रबन्ध का विवरण

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	पंचायत	तहसील	अनुमानित खर्च	पंचायत द्वारा दिया जाने वाला योग नकद या डील मेहनत के रूप में	सरकारी सहायता
१	२	३	४	५	६	७
१	एक नया तालाब खुदवाना व एक कुए को गहरा करवाना ।	आकोला	कोटडी	७५००	२५००	५०००
२	एक नया कुआ खुदवाना व तीन पुराने कुओं की मरम्मत ।	बेमाली	करेडा	६७००	३३५०	३३५०
३	दो तालाबों की मरम्मत व खुदवाई ।	चिताम्बा	करेडा	५०००	२०००	३०००
४	छः कुओं को गहरे करवाना व मवेशियों की एक प्याऊ बनवाना ।	अरवड	अरवड	८०००	२०००	६०००
५	पंचायत क्षेत्र में चार तालाबों की मरम्मत व खुदवाई, ६ कूए गहरे करवाना व ३ प्याउओं की मरम्मत ।	पियास	मोडल	५७००	१९००	३८००
६	एक नया कुआ खुदवाना, ४ पुराने कुओं की व एक तालाव की मरम्मत व उनको गहरे करवाना व गुलाबपुरा में पानी की टूटियें लगवाना ।	गुलाबपुरा	हुरडा	१२५००	३१००	९४००
७	४ तालावों की मरम्मत व उनको गहरे करवाना व तीन कूओं को गहरे करवाना ।	हटुन्दा	जहाजपुर	६०००	२०००	४०००

१	२	३	४	५	६	७
८	एक नया कुआ खुदवाना व एक प्याउ बनवाना।	रोपा	जहाजपुर	६०००	२०००	४०००
९	तीन कूओं की मरम्मत।	सूवाना	भीलवाडा	२३००	८००	१५००
१०	चार कूओं की मरम्मत व उनको गहरे करवाना।	पुर	भीलवाडा	४०००	१०००	३०००
११	बीगोद, खटवाड़ा व नया गांव में ३ कूओं की मरम्मत :	बीगोद	मांडलगढ़	११००	४००	७००
१२	चार तालाबों व नाडियों की मरम्मत व २ कूओं व तीन वावड़ियों को गहरे करवाना।	हरगांव	सहाडा	४४७५	१५८५	२८६०
१३	पंचायत क्षेत्र के कूओं को गहरे करवाना।	महेन्द्रगढ़	सहाडा	२०००	५००	१५००
१४	पंचायत क्षेत्र में ६ कूओं की मरम्मत व उनको गहरे करवाना।	बनकाखेडा	भीलवाडा	२१००	७००	१४००
१५	उदल्यास व सातल्यास के कूओं की मरम्मत व उनको गहरे करवाना।	उदग्यास	कोटडी	१०५०	३५०	७००
१६	पांच कूए गहरे करवाना व बंधवाना व एक तालाब खुदवाना।	कोटडी	कोटडी	३०००	१०००	२०००
१७	पंचायत क्षेत्रों में ६ कूओं व तीन तालावों की मरम्मत व उनको गहरे करवाना।	बनेडा	बनेड़ा	३०००	१०००	२०००
१८	एक नए कूए की खुदवाई व दो पुराने कूओं की मरम्मत।	गोरख्या	करेड़ा	३०००	१०००	२०००

१	२	३	४	५	६	७
१९	दो कूए गहरे करवाना व उनकी मरम्मत।	चांदरास	करेड़ा	२४००	८००	१६००
२०	पंचायत क्षेत्र के ६ कूओं की व एक तालाव की मरम्मत व उनको गहरे करवाना।	कालियास	आसींद	१९००	९००	१०००
२१	एक तालाब व कूए की मरम्मत	बरसनी	आसींद	१९००	१०००	९००
२२	पांच कूए गहरे करवाना व उनकी मरम्मत।	बाग़ोर	मांडल	३०००	१५००	१५००
२३	चार कूओं व एक तालाब की मरम्मत व गहरे करवाना।	लुहारिया	मांडल	३०००	१०००	२०००
२४	मेझा व कोली खेड़ा में दो नये कूए खुदवाना।	मेझा	मांडल	२१००	७००	१४००
२५	पंचायत क्षेत्र में ११ कूओं की मरम्मत व उनको गहरे करवाना।	टीकोला	शाहपुरा	७५०	१५०	६००
२६	एक कूए व एक तालाब की मरम्मत।	रायपुर	रायपुर	१८००	६००	१२००
२७	दो कूए गहरे करवाना।	आसाहोली	रायपुर	६००	२००	४००
२८	एक तालाब की मरम्मत व गहरा करवाना।	नांदला	रायपुर	४५०	१००	३५०
२९	पंचायत क्षेत्र में एक तालाब व सात कूओं की मरम्मत व उनको गहरे करवाना।	फूलियां	फूलियां	३०००	१०००	२०००

१	२	३	४	५	६	७
३०	पांच कूओं की मरम्मत व एक प्याउ बनवाना ।	धनोप	फूलियां	३०००	१०००	२०००
३१	एक नया कूआ खुदवाना व पुराने १४ कूओं की मरम्मत व गहरे करवाना ।	आगूचा	हुरड़ा	३०००	१०००	२०००
३२	एक तालाब, एक बावडी व कूए की मरम्मत ।	टूंकरवाड	हुरड़ा	३०००	१०००	२०००
३३	गांवाई कूओं की मरम्मत ।	रायला	बनेडा	२११०	६१०	१५००
३४	तालाब की खुदवाई ।	सुवाना	भीलवाड़ा	३०००	७८५	२२१५
३५	,,	रूपाहेली	भीलवाड़ा	३०००	७८५	२२१५
	योग			१,२१,४३५	४०,३१५	८१,१२०